Daily
THE PHOTON NEWS
सच के हक में...
द फोटोन न्यूज
Published from Ranchi

आम बजट 2024-25

4800000.21

करोड़ रुपये का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया पेश

सबका ध्यान सबका कल्याण

वैश्विक स्तर पर भारत की वृद्धि को वित्त मंत्री ने बताया एक चमकता हुआ सितारा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विगत 10 वर्षों के कार्यकाल में 'सबका साथ, सबका विकास' नारे पर फोकस किया। सबका विश्वास अर्जित करने पर भी जोर दिया। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बड़ा धक्का लगा और उनके नेतृत्व में भाजपा पूर्ण बहुमत तक नहीं पहुंच सकी। उन्हें अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बहुमत की सरकार बनानी पड़ी। उनके तीसरे कार्यकाल का साल 2024-25 का पहला आम बजट मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में प्रस्तुत किया। बजट के विजन को देखने और समझने से पता चलता है कि सरकार ने 'सबका ध्यान, सबका कल्याण' फार्मूले पर फोकस किया है।

- एक घंटा 23 मिनट का रहा वित्त मंत्री का भाषण
- शुद्ध कर प्राप्तियां 25.83 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान
- राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.9 फीसद रहने का अनुमान
- 7.75 लाख तक का इनकम टैक्स फ्री, 17.5 हजार का फायदा
- रोजगार और कौशल विकास पर दिया गया जोर
- छात्रों को 5 हजार रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6 हजार रुपये एकमुश्त सहायता
- बिहार को 41 हजार करोड़ और आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ की सहायता, सत्ता संतुलन बनाए रखने का बेहतर प्रयास
- पारिवारिक पेंशन पर छूट की सीमा 15 हजार से बढ़ाकर हुआ 25 हजार रुपये
- कैंसर के इलाज की तीन दवाओं को मूल सीमा शुल्क से दी जाएगी छूट
- मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबीएस तथा मोबाइल चार्जर होंगे सस्ते
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुरूआत करने का एलान

वेतनभोगी वर्ग को राहत

सीतारमण का एक घंटा 23 मिनट का बजट भाषण वेतनभोगी वर्ग के लिए थोड़ी राहत लेकर आया। नई टैक्स रिजीम चुनने वाले करदाताओं के लिए अब 7.75 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बिहार को 41 हजार करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ रुपये की मदद देने का ऐलान किया। इसके माध्यम से सत्ता संतुलन को बनाए रखने का बेहतर प्रयास किया गया है।

आनेवाले वर्षों में और मजबूत होगी वृद्धि

वित्त मंत्री ने बजट में रोजगार पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 लोकसभा में पेश करते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत की वृद्धि एक चमकता सितारा बना हुआ है, जो आने वाले वर्षों में ऐसा ही बना रहेगा। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में उधार के अलावा कुल प्राप्तियां 32.07 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि कुल व्यय 48.21 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है। उन्होंने बजट में शुद्ध कर प्राप्तियां 25.83 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.9 फीसदी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए स्पेशल स्कीम लाने का वादा भी किया। बजट में उन्होंने कहा कि नई कर व्यवस्था चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये किया जाएगा। टैक्स स्लैब में बदलाव से करदाताओं को 17.5 हजार रुपये का फायदा होगा।

नौकरी पेशा और पेंशनर्स को फायदा

बजट में पारिवारिक पेंशन पर छूट की सीमा 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन दोनों बदलावों से चार करोड़ नौकरी पेशा और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। नई कर व्यवस्था में व्यक्तिगत आयकर दरों पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत कर दर संरचना को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा।

नए टैक्स स्लैब का स्ट्रक्चर

इससे 0 से 3 लाख रुपये तक की आय पर शून्य, 3 से 7 लाख रुपये तक की इनकम पर 5 फीसदी, 7 से 10 लाख रुपये तक की आय पर 10 फीसदी, 10 से 12 लाख रुपये तक की इनकम पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी और 15 लाख से अधिक की इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री ने आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा करने का ऐलान किया, जिससे टैक्स संबंधी विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी।

एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव

बजट में निवेशकों के सभी वर्गों पर लगने वाले एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे देश के स्टार्टअप को फायदा मिलेगा और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि कैंसर के इलाज की तीन दवाओं को मूल सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं मोबाइल फोन और मोबाइल पीसीबीएस तथा मोबाइल चार्जर पर बीसीडी को घटाकर 15 फीसदी करने का प्रस्ताव करती हूं।

एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर

सीतारमण ने केंद्रीय बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी, जिसमें 5000 रुपये प्रति महीने इंटर्नशिप भत्ता और 6 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।

पूंजीगत व्यय 11.11 लाख करोड़ रुपये

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अगले 5 साल में बुनियादी ढांचे के लिए मजबूत राजकोषीय समर्थन बनाए रखने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय 11.11 लाख करोड़ रुपये होगा, जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 फीसदी होगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय घाटा 2024-25 तक सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 फीसदी रहने का अनुमान है, जबकि हमारा लक्ष्य घाटे को 4.5 फीसदी से नीचे पहुंचाना है।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

निशुल्क सौर बिजली योजना पर वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरूआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे एक करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिल सकेगी। यह योजना इसे और बढ़ावा देगी।

आदिवासियों पर फोकस

वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान आदिवासियों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरूआत करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत आदिवासी बहुल गांवों एवं आकांक्षी जिलों में रह रहे आदिवासी परिवारों को इसके दायरे में लाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के दायरे में 63 हजार आदिवासी बहुल गांव आएंगे, जिससे कि पांच करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समुदायों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति में सुधार लाना होगा।

विकसित भारत की ठोस नींव रखेगा बजट : पीएम

मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे विकसित भारत की ठोस नींव रखने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग को सशक्त करेगा। प्रधानमंत्री ने बजट को देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाला बताते हुए कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह बजट देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले हैं। ये जो नव मध्यम वर्ग बना है, ये बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट

है। प्रधानमंत्री ने बजट में युवाओं पर जोर दिए जाने का हवाला देते हुए कहा कि इसके उपायों से युवाओं के लिए कई नए अवसर खुलेंगे। उन्होंने कहा कि इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मीडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलितों और पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट से छोटे व्यापारियों, एमएसएमईएस को प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। बजट में मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत फोकस है। इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें हर शहर, हर गांव, हर घर उद्यमी बनाना है। इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में एमएसएमई के लिए ऋण में आसानी बढ़ाने वाली नई योजना शुरु की गई है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को हर जिले तक ले जाने के लिए बजट में अहम घोषणाएं की गईं। यह बजट हमारे उपकरणों के लिए, इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए पूरे नए अवसर लेकर आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ने पिछले 10 वर्षों में यह सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार टैक्स से राहत दी जाए।

राहुल गांधी ने बजट को बताया 'कुर्सी बचाओ बजट'

कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वास्तव में यह आम बजट 'कुर्सी बचाओ बजट' है। उन्होंने सरकार के बजट को 'कॉपी पेस्ट' भी कहा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कुर्सी बचाओ बजट। सहयोगियों को खुश करने की कोशिश की गई है। अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे किए गए। इसमें आम भारतीय को कोई राहत नहीं दी गई। उन्होंने बजट को कांग्रेस के घोषणापत्र और पिछले बजट का कॉपी पेस्ट भी बताया।

यह देश की तरक्की का बजट नहीं : मल्लिकार्जुन खड़गे

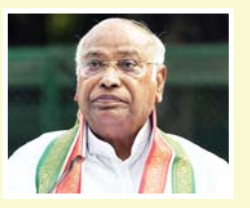

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सकार के बजट पर निशाना साधते हुए लिखा, कांग्रेस के न्याय के एजेंडे को ठीक तरह से कॉपी भी नहीं कर पाया मोदी सरकार का 'नकलची बजट'। मोदी सरकार का बजट अपने गठबंधन के साथियों को ठगने के लिए आधी-अधूरी 'रेवड़ियां' बांट रहा है, ताकि एनडीए बची रहे। ये 'देश की तरक्की' का बजट नहीं, 'मोदी सरकार बचाओ' बजट है। 10 साल बाद उन युवाओं के लिए सीमित घोषणाएं हुईं हैं, जो

सालाना दो करोड़ नौकरियों के जुमले को झेल रहे हैं। किसानों के लिए केवल सतही बातें हुईं हैं, डेढ़ गुना एमएसपी और आय दोगुना करना - सब चुनावी धोखेबाजी निकली। उन्होंने लिखा, 'ग्रामीण वेतन को बढ़ाने का इस सरकार का कोई इरादा नहीं है। दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, माध्यम वर्ग और गांव-गरीब लोगों के लिए कोई भी क्रांतिकारी योजना नहीं है, जैसी कांग्रेस-यूपीए ने लागू की थी। ह्मगरीब :शब्द केवल स्वयं की ब्रांडिंग करने का जरिया बन गया है, ठोस कुछ भी नहीं है। महिलाओं के लिए इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे उनकी आर्थिक क्षमता बढ़े और वो वर्कफोर्स में अधिक से अधिक शामिल हों। उल्टा महंगाई पर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है।

मांग से ज्यादा जरूरत के मुताबिक मिला बजट

30 हजार करोड़ की बिहार सरकार ने की थी डिमांड

बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे के बनने का रास्ता साफ चार घंटे में पूरी होगी इन दोनों शहरों के बीच की दूरी

केंद्रीय बजट में बिहार को सड़कों को बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को सदन में बजट पेश करते हुए पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे के साथ साथ बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए 26 हजार करोड़ रुपये देने का एलान किया है।

इन शहरों को फायदा : बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे के बनने से बक्सर, भोजपुर, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नवादा, जमुई, शेखपुरा, बांका और भागलपुर के लोगों को फायदा पहुंचेगा। बक्सर से भागलपुर का सफर पूरा करने में फिलहाल 9 घंटे का समय लगता है। इसके लिए लोगों को 380 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। एक्सप्रेस वे के बनने से यह सफर मात्र चार घंटे में पूरी की जा सकेगी।

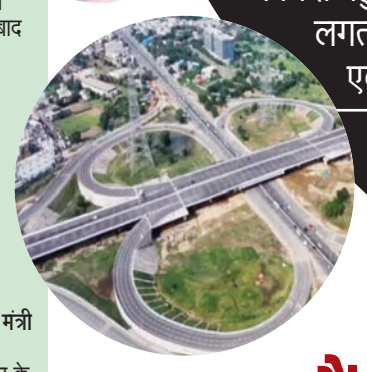

- उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी सरकार
- चार एक्सप्रेस-वे और एक गंगा नदी पर पुल बनाने की घोषणा
- 26 हजार करोड़ से होगा बिहार में सड़क निर्माण
- 11 हजार करोड़ बाढ़ प्रभावित इलाकों के प्रबंधन पर होगा खर्च

हम खुश हैं : नीतीश

बिहार के लिए केंद्र ने खोला पिटारा

AGENCY DELHI :

मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 लोकसभा में पेश किया। वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत की वृद्धि एक चमकता सितारा बना हुआ है, जो आने वाले सालों में ऐसी ही बना रहेगा। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बिहार के लिए अपना पिटारा खोल दिया है, जबकि आंध्र प्रदेश के लिए बजट में 15 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। वि?त मंत्री ने कहा कि सरकार अगले 5 साल में बुनियादी ढांचे के लिए मजबूत राजकोषीय समर्थन बनाए रखने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय 11.11 लाख करोड़ रुपये होगा, जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 फीसदी होगा। उन?होंने कहा कि वित्तीय घाटा 2024-25 तक सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 फीसदी रहने का अनुमान है, जबकि हमारा लक्ष्य घाटे को 4.5 फीसदी से नीचे पहुंचाना है। निशुल्क सौर बिजली योजना पर वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरूआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे एक करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिल सकेगी। यह योजना इसे और बढ़ावा देगी। सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि हमारी सरकार आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं। उन?होंने कहा कि राज्य की पूंजी की आवश्यकता को समझते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के

माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी। वित्त मंत्री ने बिहार के लिए अपना पिटारा खोलते हुए कहा कि 21,400 करोड़ रुपये की लागत से बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी। हमारी सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के शीघ्र पूरा होने और वित्तपोषण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है जो आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवन रेखा है। सीतारमण ने कहा कि अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर पर हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को समर्थन देंगे। यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा। हम सड़क संपर्क परियोजनाओं पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा के विकास में भी सहयोग करेंगे और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन का पुल बनाया जाएगा।

बिहार को काफी मदद मिली: नीतीश कुमार

मोदी सरकार के आम बजट को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होने कहा कि बजट से हम खुश हैं। विशेष दर्जा के लिए हमलोग आंदोलन कर रहे थे। आज जो बोल रहे हैं जब उनकी पार्टी केंद्र में थी तब क्या किए? हम इसके लिए लगातार बोलते रहे हैं। हमने कहा विशेष राज्य जा दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद कीजिए। हम लोगों ने कह दिया था बिहार को मदद करिए उसी में कई चीजों की मदद की घोषणा हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार को केंद्र सरकार की ओर से पूरी मदद मिल रही है। विशेष राज्य का दर्जा बंद कर दिया, तो जो मदद होनी चाहिए थी। वो विकास के लिए हो रही है। उन्होने कहा कि पहले बिहार का बुरा हाल था।

केंद्र के बजट में बिहार का बजा डंका : विजय

बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा भले ही अभी न मिला हो, लेकिन मोदी सरकार के बजट में बिहार को काफी कुछ मिला है। 26 हजार करोड़ अगल-अलग योजनाओं के लिए प्रस्तावित किए गए है। जिसमें सड़क, हाइवे, बाढ़ नियंत्रण और हवाई अड्डे शामिल हैं। वहीं बिहार के मॉनसून सत्र में आज भी हंगामा हुआ। पूरा विपक्ष बिहार को विशेष राज्य के दर्जा पर अड़ा है। इस बीच नीतीश सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा विपक्ष को घेरा। और जमकर निशाना साधा। मंत्री विजय चौधरी ने केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया और कहा कि बिहार को कभी किसी बजट में अब तक इतनी मदद कभी नहीं मिली थी। वहीं विपक्ष दल के एक नेता के झुनझुना लेकर सदन में पहुंचने पर उन्होने कहा कि एक और केंद्र के बजट में बिहार का डंका बज रहा है।

संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा बजट : संजय

रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बजट विकसित भारत की प्रतिबद्धता को पूर्ण करने की दिशा में ऐतिहासिक है। यह बजट मध्यवर्गीय, किसानों, महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनायेगा। साथ ही संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा। सेठ ने कहा कि इस बजट में किसान, मध्य वर्ग और युवाओं को बड़ी सौगात दी गई है। कृषि क्षेत्र में 1.52 लाख करोड रुपये दिए गए हैं। युवाओं के लिए रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी पांच योजनाओं के लिए दो लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। 500 बड़ी कंपनियां में एक करोड़ युवाओं को इंटरशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे। साथ ही एक करोड़ छात्रों को 5000 मासिक भत्ता दिया जाएगा।

बाढ़ के लिए फंड को लेकर बोले- बहुत अच्छी पहल

बिहार को विशेष पैकेज मिलने से ग्रामीण खुश

AGENCY MUZAFFARPUR :

बिहार को केंद्रीय बजट में विशेष पैकेज दिया गया है। साथ ही बाढ़ नियंत्रण और प्रभावित क्षेत्र के लिए राहत और पुनर्वास सहित कई अन्य विकास कार्य को लेकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों ने पीएम मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि अब बाढ़ के दंश से निजात मिलेगी। गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर जिले के आधा दर्जन अधिक प्रखंड बाढ़ से प्रभावित रहते हैं।मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अलग-अलग राज्यों में बाढ़ नियंत्रण, उपायों और सिंचाई परियोजनाओं को मजबूती देने के लिए आज 11,500 करोड़ रुपये की व्यापक वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की है। इसके साथ ही बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्र में फ्लड कंट्रोल और फ्लड रिलीफ के काम में तेजी लाई जा सकेगी। लोकसभा में 2024-25 के लिए बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार आगे बढ़ाए गए सिंचाई लाभ कार्यक्रम के साथ-साथ ही अब और अन्य स्रोतों के माध्यम से अलग-अलग परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और यह मील का पत्थर साबित होगा। बिहार में अक्सर बाढ़ आती है और कई बार इसका कारण देश से बाहर की नदियों में पानी छोड़ा जाना होता है। हर साल भारत के बाहर से आने वाली कई नदी के साथ-साथ ही सहायक नदियों के कारण बाढ़ का सामना करना पड़ता है। उम्मीद है कि अब इन परियोजनाओं द्वारा सहायता मिलेगी। साथ ही बाढ़ से हुए व्यापक नुकसान को देखते हुए हमारी सरकार बहुपक्षीय विकास सहायता के माध्यम से ही पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए सहायता प्रदान करेगी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्र औराई, कटरा, गायघाट, मुसहरी, मीनापुर और कांटी प्रखंड मुख्य रूप से शामिल हैं।

केंद्रीय बजट पर लालू- तेजस्वी और रोहिणी आचार्य ने कहा-

आम आदमी के दिल पर खंजर है यह बजट

AGENCY PATNA :

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 का पहला बजट मंगलवार को पेश किया। इस बजट में बिहार को कई तोहफे मिले हैं। लेकिन बिहार को इस बार भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। जिस पर बिहार की सियासत गरमाई है। अब इस पर राजद सुप्रीमो लालू यादव, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राज नेता रोहिणी आचार्या ने बिहार को लेकर हुई घोषणाओं पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से बिहार को निराश किया गया। लालू यादव ने अपने खास अंदाज में बजट की आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि एक घिसा-पिटा हट है ये बजट,

जुमलों की रट है ये बजट, गरीब और किसान के सपने कर रहा बंजर है ये बजट, आम आदमी के दिल पर खंजर है ये बजट।

तेजस्वी यादव ने कहा है कि रूटीन आवंटन, पूर्व स्वीकृत, निर्धारित और आवंटित योजनाओं को नई सौगात बताने वाले बिहार का अपमान न करें। पलायन रोकने, प्रदेश का पिछड़ापन हटाने तथा उद्योग धंधों के साथ-साथ युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए हम विशेष राज्य के दर्जे की मांग से इंच भर भी पीछे नहीं हटेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज के बजट ने बिहार के लोगों को फिर निराश किया है। बिहार को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए एक रिवाइवल प्लान की जरूरत थी। जिसके लिए विशेष राज्य के दर्जे के साथ विशेष पैकेज की सख्त जरूरत है।

बजट पर लालू यादव की बेटी और राजद नेता **रोहिणी आचार्य** ने बजट को भरमाने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि आज पेश किया गया बजट गुमराह करने वाला है। पुराने प्रावधानों को इस तरह से पेश किया गया है कि आम आदमी को लगे कि कुछ बड़ी रियायतें और राहत दी गई हैं और चरमराती अर्थव्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से बड़े बदलाव किए गए हैं। रोहिणी ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे बिहार के लिए वित्तीय सहायता के रूप में मात्र 41,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह बिहार के हितों की सीधी-सीधी अवहेलना है। यह तो ऊंट में मुंह में जीरा जैसी बात हो गई। कुछ निजी निर्माण और सीमेंट कंपनियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बिहार में राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए 26,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

वित्त मंत्री के जरिये पेश किया गया आम बजट देश के नौजवानों, महिलाओं, किसानों, दलित और आदिवासियों को धोखा देने वाला है। दोनों संयुक्त रूप से बजट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। दोनों नेताओं ने कहा कि लोकसभा चुनाव में मिली शिकस्त के कारण और कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बजट में सिर्फ घोषणाएं की गई है। पूरे देश में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ और किसानों के सम्मान से खिलवाड़ किया गया है। आवश्यक दिनचर्या और खाद्य पदार्थों पर टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई है। इसलिए यह आम बजट पूंजीवाद को फायदा और देश की 80 प्रतिशत जनता मजदूर छात्र नौजवान एवं विकास से वंचित लोगों पर बोझ डालने वाला बजट है। केंद्र सरकार ने पूंजीपतियों को ध्यान में रखकर बजट बनाया है, जो देश की 80 प्रतिशत जनता के हित में नहीं है।

महेंद्र पाठक व अजय कुमार सिंह

वित्तमंत्री सीतारमण की ओर से पेश किया गया आम बजट आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि खास लोगों के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ये बजट प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाओ या सत्ता बचाओ योजना के अंतर्गत आया है। ये बजट देश के लिए कतई नहीं है। भट्टाचार्य मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। सुप्रियो ने कहा कि इस बजट से ये जाहिर हुआ कि केंद्र सरकार अंदर से कितनी डरी हुई है। इस डर के कारण ही आंध्र प्रदेश पर खास ध्यान दिया गया है। साथ ही बिहार पर भी बजट को फोकस किया गया है। थोड़ा ध्यान ओडिशा पर भी ध्यान दिया गया है। इससे ऐसा लगता है कि बाकी 27 राज्य इस देश में है ही नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हालिया चुनावों को मुद्दाविहीन हो कर लड़ा। केवल सांप्रदायिक बातें की। उन्होंने कहा कि बजट भी उसी की झलक जैसा है।सुप्रियो ने कहा कि बजट में सबसे ऊपर एग्रीकल्चर सेक्टर आता है। इससे पहले के बजट में एग्रीकल्चर के लिए कुल राशि का 6.5 प्रतिशत हिस्सा हुआ करता था। आज ये घटकर 3.9 प्रतिशत पर आ गया है। बजट में एमएसपी की कोई चर्चा नहीं है, जो अत्यंत अहम सेक्टर है और जिससे पेट भरा जाता है, उस पर कोई बात नहीं हुई। केवल फल और सब्जी पर बात हुई।

सुप्रियो भट्टाचार्य, झामुमो नेता

वित्त मंत्री ने कांग्रेस का पढ़ा घोषणा पत्र : पी चिदंबरम

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश करते समय कई योजनाओं की शुरूआत की। पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि वित्त मंत्री ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जारी कांग्रेस का घोषणापत्र पढ़ा है। पूर्व वित्त मंत्री ने एक्स पर लिखा, ₹मुझे यह जानकर खुशी हुई कि माननीय वित्त मंत्री ने चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस का घोषणापत्र 2024 पढ़ा। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की भी खुशी है कि वित्त मंत्री ने रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन को अपना लिया है, जो कांग्रेस के घोषणापत्र के

पेज नंबर 30 पर है। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा, मुझे इस बात की भी खुशी है कि उन्होंने कांग्रेस के घोषणापत्र के पेज 11 से प्रत्येक ट्रेनी को भत्ते के साथ ट्रेनिंग योजना शुरू की है।₹ उन्होंने वित्त मंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि काश निर्मला सीतारमण कांग्रेस के घोषणापत्र से कुछ और विचार कॉपी कर पातीं। पूर्व वित्त मंत्री ने पर लिखा,₹मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि वित्त मंत्री ने एंजल टैक्स को खत्म कर दिया है। कांग्रेस कई सालों से इसे खत्म करने की मांग कर रही थी और घोषणापत्र में पेज 31 पर भी ऐसा ही कहा गया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि वह जल्द ही इस पर आगे बात करेंगे। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की नौ प्राथमिकताओं को सामने रखा, जिसमें रोजगार, कौशल, कृषि और विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने अपना सातवां बजट पेश करते हुए कहा, इस बजट में हम रोजगार, कौशल, टरटए और मध्यम वर्ग पर फोकस करेंगे। उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु अनुकूल किस्मों के लिए कृषि अनुसंधान को बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों ने ढट मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है और ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए इसे फिर से चुना है।

मांग से ज्यादा जरूरत के मुताबिक मिला बजट

“ प्रधानमंत्री ने एक बार फिर मिडिल क्लास फॅमिली को टैक्स के बोझ से दबा दिया है। चुनाव के बाद लगा था कि देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर मिडिल क्लास फॅमिली को टैक्स के बोझ से दबा दिया हैं, चुनाव जीत के बाद लगा था कि टैक्स में राहत दी जाएगी, लेकिन उल्टा हो गया। युवाओं को नौकरी के बदले इर्म्नशिप का झुनझुना वो भी ईएमआई में दिया गया है। केंद्रीय मंत्री को झारखंड का चुनाव प्रभारी बनाया गया है, लेकिन वे भी कुछ नहीं दिला सके। आश्चर्य है कि बजट में स्वास्थ्य सेवा का जिक्र नही है, उसके बजट को घटाया गया है, जिसका मतलब साफ है कि जनता की जान से भाजपा सरकार को कोई लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर यह बजट आईवाश है। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विकास फंड देना और झारखंड को उपेक्षित करना आदिवासी विरोधी मानसिकता का परिचायक है।

बन्ना गुप्ता, स्वास्थ्य व खाद्य आपूर्ति मंत्री

“ मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में विशेष रूप से अन्नदाताओं, महिलाओं की समृद्धि, युवाओं के रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित है। बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। शेफाली ने कहा कि यह कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार एवं कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा संरक्षण, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास और नई पीढ़ी के सुधार, चतुर्दिक समृद्धि एवं सशक्त विकास को समर्पित बजट है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया।

शेफाली गुप्ता, भाजपा की महिला नेता

“ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट पेश किया। महंगाई से जनता त्रस्त है, लेकिन बजट में आम जनों के लिए कुछ भी खास नहीं किया और इस बजट में झारखंड वासियों और झारखंड राज्य के लिये कुछ भी नहीं है। जमीनी स्तर पर इससे किसानों को कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। सरकार को बजट में बताना चाहिए था कि पिछले 10 वर्षों में आपने कितनी नौकरियां दीं। इस बजट में जनता को राहत देने वाला कुछ नहीं है केवल आंकड़ों की बाजीगरी है।

मंगल कालिंदी, विधायक, जुगसलाई

“ युवा, गरीब, महिला, किसान सभी के सशक्तीकरण के लिए समर्पित है। यह बजट विकसित भारत के भविष्य निर्माण का बजट है। आदिवासियों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरूआत करने की घोषणा की है। 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक का पूंजीगत व्यय आवंटित किया गया है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर के लिए घोषणाएं पूर्वी भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगी। कौशल और रोजगार सृजन की घोषणाएं ऐतिहासिक हैं।

अर्जुन मुंडा, पूर्व केंद्रीय मंत्री

“ वर्ष 2024 का आम बजट संतुलित है। बजट में युवा वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए व्यापक प्रावधान हैं।उच्च शिक्षा लोन योजना, रोजगार लिंक्ड स्कीम व बारह महीने की इंटर्नशिप स्कीम द्वारा युवाओं को शिक्षित कर उन्हें रोजगार से जोड़ने की बात की गई है। यह बजट स्वागत योग्य है।

अभिषेक शुक्ला, युवा आजसू

“ मोदी सरकार ने युवाओं और किसानों को इस बजट के माध्यम से लॉलीपॉप थमा दिया है। मतलब आप लॉलपॉप का आनंद लीजिए और मस्त रहिए। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में युवाओं से पहली नौकरी पक्की गारंटी का वादा किया था. मोदी सरकार ने इस बजट में उसकी नकल की है. लेकिन किसको नौकरी मिलेगी, यह सरकार तय करेगी। इसमें क्या प्रावधान होंगे, यह साफ नहीं किया गया है। इस बजट से किसानों को कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। किसानों को जैविक खेती सिखाने वाली कंपनियों को इससे फायदा होने वाला है, लेकिन किसानों के हाथ कुछ भी लगने वाला नहीं है।

डॉ. अजय कुमार, पूर्व सांसद, जमशेदपुर

“ यह बजट केंद्र सरकार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला तथा देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिकाऊ बनाने वाला है। बजट से भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। आयकर स्लैब में सहूलियत देने का केंद्र सरकार का प्रयास सराहनीय है। इससे मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचेगा। दूसरी ओर, पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम करने तथा जीएसटी में सुधार करने की आम जनता की उम्मीदें पूरी नहीं हो पायी है। कैपिटल गेन पर टैक्स में वृद्धि से भी मध्यम वर्ग को नुकसान होगा। खुदरा कीमतों की वृद्धि की प्रवृति से भी आम जनता के पॉकेट से रोजाना दो-चार-दस रुपये खींचकर बाजार में जाएगा। उम्मीद है कि बजट पर लोकसभा में बहस के दौरान भारत सरकार इसका ध्यान रखेगी कि मध्यम एवं निम्न मध्यम वर्ग को बचत हो और अर्थव्यवस्था में सुधार का लाभ केवल संगठित वर्गों तक ही समित नहीं रहे, बल्कि समाज के असंगठित समूहों को लाभ दिया जा सके।

सरयू राय, विधायक, जमशेदपुर पूर्वी

“ वित्त मंत्री के जरिये पेश किया गया आम बजट देश के नौजवानों, महिलाओं, किसानों, दलित और आदिवासियों को धोखा देने वाला है। दोनों संयुक्त रूप से बजट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। दोनों नेताओं ने कहा कि लोकसभा चुनाव में मिली शिकस्त के कारण और कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बजट में सिर्फ घोषणाएं की गई है। पूरे देश में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ और किसानों के सम्मान से खिलवाड़ किया गया है। आवश्यक दिनचर्या और खाद्य पदार्थों पर टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई है। इसलिए यह आम बजट पूंजीवाद को फायदा और देश की 80 प्रतिशत जनता मजदूर छात्र नौजवान एवं विकास से वंचित लोगों पर बोझ डालने वाला बजट है। केंद्र सरकार ने पूंजीपतियों को ध्यान में रखकर बजट बनाया है, जो देश की 80 प्रतिशत जनता के हित में नहीं है।

महेंद्र पाठक व अजय कुमार सिंह

“ एक तरह से देखा जाए तो बजट में राजनीति को साधने की कोशिश की गई है। बिहार और आंध्रप्रदेश को विशेष सहायक इसी रूप में देखी जा सकती है। कुल मिलाकर आम बजट कुछ खास को फायदा पहुंचाने वाला ही जान पड़ता है। इसमें देश के आम लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं है।

जैदी अली रजा, प्रदेश महासचिव, सपा

सुविचार

बुद्धिमान लोगों में खुशी सबसे दुर्लभ चीज है, जो मैं जानता हूं।
-अर्नेस्ट हेमिंग्वे

Daily
THE PHOTON NEWS
सच के हक में...
द फोटोन न्यूज Published from Ranchi

Sara Tendulkar's Blue Lehenga...

Ranchi ● Wednesday, 24 July 2024 ● Year : 02 ● Issue : 186 ● Ranchi Edition ● Page : 12 ● Price : ₹3 ● www.thephotonnews.com E-Paper : epaper.thephotonnews.com

SHARE

सेंसेक्स	:	80,429.04
निफ्टी	:	24,479.05

SARAFA

सोना	:	6,915
चांदी	:	96.00

(नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

सेना ने पुंछ में नियंत्रण रेखा पर विफल की घुसपैठ

JAMMU : जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में मंगलवार तड़के सेना ने नियंत्रण रेखा पर आतंकवादियों की घुसपैठ विफल कर दी। इस दौरान मुठभेड़ में एक जवान घायल हो गया। व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर कहा कि सतर्क सैनिकों ने सुबह तीन बजे बट्टल सेक्टर में घुसपैठ कर रहे आतंकवादियों पर प्रभावी ढंग से गोलीबारी करके घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। भारी गोलीबारी के दौरान एक बहादुर जवान घायल हो गया है। सूत्रों के अनुसार हथियारबंद आतंकवादियों के समूह ने कृष्णाघाटी सेक्टर के बट्टल अग्रिम क्षेत्र में घुसने की कोशिश की लेकिन सतर्क सैनिकों ने उनकी हरकतों को भांप लिया और तुरंत कार्रवाई की। भीषण गोलीबारी कर सैनिकों ने आतंकवादियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।

बांग्लादेशियों के मामले में ममता के बयान पर मांगा जवाब

KOLKATA : पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी. वी. आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनकी टिप्पणी पर रिपोर्ट मांगी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे हिंसा-प्रभावित बांग्लादेश के लोगों को 'आश्रय' देंगी। यह जानकारी राजभवन ने मंगलवार को दी है। राजभवन मीडिया सेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि बाहरी मामलों को संभालने का अधिकार केंद्र सरकार का है। उन्होंने लिखा, किसी विदेशी देश से आने वाले लोगों को शरण देने का मामला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। एक मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह की सार्वजनिक घोषणा करना कि वे विदेशी नागरिकों को आश्रय देने की जिम्मेदारी ले रही हैं, संविधान के गंभीर उल्लंघन का संकेत देता है।

कोल्हापुर में बारिश का कहर जारी, 51 मकान ढहे

MUMBAI : कोल्हापुर जिले में बारिश का कहर पिछले चार दिनों से जारी है, जिससे विभिन्न इलाकों में 51 मकान ढह गये हैं। जिले की तीन तहसीलों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से पंचगंगा नदी चेतावनी स्तर को पार कर खतरे के निशान तक पहुंचने को उतावली है। इसके चलते नदी किनारे के गांवों में सतर्कता बरती जा रही है। इसके साथ ही कोल्हापुर शहर के सुतारवाड़ा इलाके के 4 परिवारों के 20 नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कलेक्टर अमोल येडगे ने बाढ़ संभावित क्षेत्रों के नागरिकों से समय रहते शिफ्ट करने और प्रशासन को सहयोग करने की अपील की है। बाढ़ की स्थिति के अनुसार कोल्हापुर नगर निगम ने उन स्थानों की सूची की घोषणा की है, जहां 2021 में शहर में बाढ़ का पानी आया है। जैसे-जैसे बाढ़ का स्तर बढ़ता है, वैसे-वैसे नागरिकों को स्थानांतरित करना चाहिए।

हमास और फतह के बीच मतभेद खत्म करने को बीजिंग में बनी सहमति

AGENCY BEIJING : गाजा पट्टी में गहराते युद्ध संकट के बीच फलस्तीन के प्रतिद्वंद्वी समूहों हमास और फतह ने वर्षों से जारी आपसी मतभेदों को खत्म करने के लिए बीजिंग में एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। चीन के सरकारी मीडिया ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

गाजा पट्टी में गहराते युद्ध संकट के बीच यह घोषणापत्र फलस्तीनी क्षेत्र में मिलकर सरकार बनाने के मकसद से हमास और फतह को एकजुट करने के लिए जारी कई दौर की बातचीत का नतीजा है। हालांकि, दोनों पक्ष आपसी मतभेद दूर करने के लिए पहले भी कई ऐसे घोषणापत्र पर दस्तखत कर चुके हैं, जो विफल रहे हैं। ऐसे में इस बात को लेकर संदेह पैदा हो गया है कि क्या चीन प्रायोजित वार्ता से वास्तव में कोई समाधान निकल सकता है। इस घोषणापत्र पर ऐसे समय में हस्ताक्षर किए गए हैं, जब इजराइल और हमास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समर्थित संघर्ष-विराम प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं, जो गाजा पट्टी में नौ महीने से जारी युद्ध को समाप्त कर सकता है और हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजराइली

चीन के विदेश मंत्री की मौजूदगी में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करते प्रतिनिधि

नागरिकों की आजादी का रास्ता खोल सकता है। हालांकि, समझौते पर सहमति बनने के बावजूद युद्ध के बाद गाजा पट्टी की स्थिति को लेकर संशय बरकरार रहेगा, क्योंकि इजराइल इस क्षेत्र के शासन में हमास की किसी भी भूमिका के खिलाफ है। उसने युद्ध समाप्त होने के बाद गाजा को फतह-प्रभुत्व वाले फलस्तीनी प्राधिकरण द्वारा संचालित करने के अमेरिका के आह्वान को भी खारिज कर दिया है। युद्ध के बाद गाजा पट्टी के प्रशासन को लेकर अनिश्चितता के कारण संघर्ष विराम वार्ता और जटिल हो गई है।

सरकारी प्रसारणकर्ता 'सीसीटीवी' के मुताबिक, फलस्तीन के दोनों प्रतिद्वंद्वी समूहों ने 'मतभेद खत्म करने और फलस्तीनी एकता को मजबूत करने' के संबंध में बीजिंग घोषणापत्र पर दस्तखत किए।

इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने मंगलवार को इस समझौते को खारिज कर दिया और कहा कि गाजा में हमास एवं फतह का कोई संयुक्त शासन नहीं होगा 'क्योंकि हमास के शासन को कुचल दिया जाएगा।'

चीनी टेलीविजन चैनल 'सीजीटीएन' ने सोशल मीडिया मंच 'वीबो' पर एक पोस्ट में कहा कि फलस्तीन के दोनों प्रतिद्वंद्वी समूहों ने 12 अन्य राजनीतिक गुटों के साथ चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की और इसके साथ ही रविवार को शुरू हुई बातचीत का समापन हुआ।

बीजिंग में हालिया वार्ता के बाद जारी एक संयुक्त बयान में इस संबंध में कोई विवरण नहीं दिया गया है कि सरकार कब और कैसे बनेगी। इसमें केवल यह कहा गया है कि सरकार 'गुटों के बीच सहमति से' बनाई जाएगी।

हमास ने वर्ष 2007 में हिंसक संघर्ष के दौरान फलस्तीन के तत्कालीन राष्ट्रपति महमूद अब्बास के वफादार फतह लड़ाकों को गाजा पट्टी से खदेड़कर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से ही दोनों समूह एक-दूसरे के विरोधी रहे हैं।

नीट-यूजी 2024 पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला

विवादों से घिरी परीक्षा को रद्द करने से किया इनकार

न्यायालय ने दोबारा परीक्षा की मांग वाली याचिका को किया खारिज

NEW DELHI BHASHA: उच्चतम न्यायालय ने विवादों से घिरी नीट-यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिकाओं को मंगलवार को खारिज कर दिया और कहा कि प्रश्नपत्र के व्यवस्थित रूप से लीक होने और अन्य गड़बड़ियों को दर्शाने वाली कोई सामग्री रिकॉर्ड में नहीं है।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एवं वरिष्ठ अधिवक्ताओं नरेंद्र हुड्डा, संजय हेगड़े और मैथ्यूज नेदुमपरा सहित विभिन्न वकीलों की दलीलें करीब चार दिनों तक सुनीं।

पीठ ने 20 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए फैसले के प्रभावी हिस्से को लिखा और कहा कि विस्तृत फैसला बाद

में सुनाया जाएगा। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि नीट-यूजी 2024 परीक्षा के नतीजों में गड़बड़ी हुई है या इसमें प्रणालीगत उल्लंघन है। हालांकि, पीठ ने कहा कि प्रश्नपत्र लीक की घटना हजारीबाग और पटना में हुई थी- यह तथ्य विवाद का विषय नहीं है। एनटीए और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय पांच मई को आयोजित परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक सहित बड़े पैमाने पर कथित गड़बड़ी को लेकर निशाने पर है। एनटीए देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में मेडिकल संबंधी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) आयोजित करती है। पांच मई को 571 शहरों के 4,750 केंद्रों पर 23.33 लाख छात्रों ने नीट-यूजी 2024 परीक्षा दी थी। इनमें 14 विदेशी शहर भी शामिल थे।

भौतिकी के प्रश्न को लेकर आईआईटी के विशेषज्ञों ने कहा- केवल एक सही उत्तर था

NEW DELHI : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली के तीन विशेषज्ञों की समिति ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट-यूजी 2024' में पूछे गए भौतिकी के एक विवादास्पद प्रश्न का केवल एक ही सही उत्तर था, न कि दो। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने सोमवार को आईआईटी-दिल्ली के निदेशक को भौतिकी के इस विवादित प्रश्न को लेकर तीन विषय विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने तथा मंगलवार दोपहर तक सही जवाब पर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। सुनवाई शुरू होने पर सीजेआई ने रिपोर्ट में लिखी बातों का हवाला दिया और कहा, 'हमें आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट मिली है। आईआईटी निदेशक रंगन बनर्जी ने भौतिकी विभाग की एक समिति गठित की और वे बताते हैं कि तीन विशेषज्ञों की एक टीम ने प्रश्न की जांच की। टीम का कहना है कि चौथा विकल्प सही जवाब है।' सीजेआई ने कहा कि चौथा विकल्प, जो कहता है कि 'पहला कथन सही है, लेकिन दूसरा कथन गलत है', सही जवाब है।

इथियोपिया में भूस्खलन में बच्चों समेत कम से कम 157 लोगों की मौत

ADDIS ABABA : इथियोपिया के एक दूरस्थ क्षेत्र में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में कम से कम 157 लोगों की मौत हो गयी है। एक स्थानीय अधिकारी ने यह जानकारी दी। स्थानीय प्रशासक दागमावी आयेले ने बताया कि दक्षिणी इथियोपिया के केंचो शाचा गोजदी जिले में मिट्टी धंसने की घटना में मारे गए लोगों में बच्चे और गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। ज्यादातर लोग सोमवार सुबह हुए भूस्खलन में दब गए, जब बचावकर्मी एक दिन पहले हुए एक अन्य भूस्खलन के बाद पीड़ितों की तलाश कर रहे थे। आयेले ने बताया कि मलबे से पांच लोगों को जीवित निकाला गया। उन्होंने बताया, 'कई बच्चे हैं जो हादसे में अपनी मां, पिता, भाई और बहन समेत पूरे परिवार को खो चुके हैं तथा लाशों से लिपट रहे हैं।' बचाव अभियान जारी रहने के कारण मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। इथियोपिया में जुलाई में शुरू होने वाले बारिश के मौसम में भूस्खलन होना आम है। बारिश का यह मौसम सितंबर मध्य तक जारी रहने की संभावना है।

सीएम ने 256 विशेष परिवारों को दिया आशियाना

हेमंत बोले-कुष्ठाश्रम परिसर कहलाएगा निर्मल आवास

परिसंपत्तियों का वितरण करते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ● फोटोन न्यूज

PHOTON NEWS RANCHI: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को पीएम-आवास योजना (शहरी) अंतर्गत साईं सिटी के पास स्थित नवनिर्मित मुड़मा कुष्ठाश्रम परियोजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज इस परियोजना का लाभ 256 विशेष परिवारों को मिल रहा है। ये आशियाना एक विशेष समूह के लिए बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं चाहूंगा कि इस परिसर को 'निर्मल आवास' के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का सदैव प्रयास रहा है कि हर जरूरतमंद व्यक्ति चाहे वे किसी भी वर्ग-समुदाय के हों, जिस स्थिति या परिस्थिति में रह रहे हों उन तक सरकार की आवाज पहुंचे, सरकार द्वारा संचालित जनकल्याण की योजनाएं पहुंचे।

मुख्यमंत्री ने 183 चयनित अभ्यर्थियों को दिया नियुक्ति पत्र

RANCHI : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित असिस्टेंट टाउन प्लानर, जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, माइनिंग इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल), स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर, पाइपलाइन इंस्पेक्टर पद के 183 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र बांटा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज फिर वही सकारात्मक ऊर्जा एवं उत्साह के साथ राज्य के विकास को गति देने के उद्देश्य से नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। कुछ नियुक्तियां झारखंड लोक सेवा आयोग एवं कुछ नियुक्तियां झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की गई है।

राष्ट्रगान के लिए मजबूर किए गए युवक की मौत की जांच करे सीबीआई : कोर्ट

NEW DELHI BHASHA : दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 23 वर्षीय एक युवक की मौत से संबंधित मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दिया, जिसे 2020 में शहर के उत्तर पूर्वी हिस्से में हुए दंगों के दौरान कथित तौर पर पीटा गया और राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किया गया था। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हुआ था। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में पुलिस

कर्मियों द्वारा फैजान को चार अन्य मुस्लिम पुरुषों के साथ कथित तौर पर राष्ट्रगान और 'वंदे मातरम' गाने के लिए मजबूर करते हुए एवं पीटते हुए देखा जा सकता है। फैजान की मां ने मामले की विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने के लिए याचिका दायर की थी। इस पर फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि अभी तक पहचाने नहीं गए पुलिसकर्मियों पर 'धार्मिक कट्टरता से प्रेरित' होकर मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन करने का आरोप हैं। यह तथ्य कि अपराधी स्वयं जांच एजेंसी के सदस्य हैं, भरोसा पैदा नहीं करता है। न्यायमूर्ति भंभानी ने टिप्पणी की कि पुलिस जांच के दौरान घृणा अपराधों से तत्परता से निपटने के फैसले की भावना को पूरा नहीं किया गया है।

मध्यप्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी नीति में संशोधन को मिली मंजूरी

BHOPAL : मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2023 में संशोधन को मंजूरी दी, जिससे राज्य में अपना कारोबार स्थापित करने वाली कंपनियों को कई लाभ मिलेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में 'मध्यप्रदेश आईटी, आईटीईएस (सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं) और ईएसडीएम (इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण)' निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 में संशोधन को मंजूरी दी गई।

एसीबी ने एसआई को 20 हजार घूस लेते रंगेहाथ किया गिरफ्तार

LATEHAR : पलामू के एंटी करप्शन ब्यूरो ने लातेहार के बारियातू थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक (एएसआई) धीरेंद्र कुमार को 20 हजार रुपये घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी ने बताया कि बारियातू थाना में अफीम रखने के मामले में एक मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में वादी के भतीजे को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

एएसआई धीरेंद्र कुमार ने कुछ दिनों बाद इसी कांड में वादी को फंसाने की धमकी देकर तीन लाख रुपये की मांग की थी। वादी ने पैसे देने से इनकार कर दिया, लेकिन एएसआई ने वादी पर लगातार पैसे के लिए दबाव बनाया। इसके बाद वादी ने एसीबी से इसकी शिकायत की। एसीबी के पुलिस उपाधीक्षक ने इस मामले का सत्यापन किया। मामला सत्य पाए जाने पर एसीबी की पलामू छापेमारी टीम ने दंडाधिकारी और दो स्वतंत्र गवाहों के सामने धीरेंद्र कुमार को 20 हजार घूस लेते गिरफ्तार किया। धीरेंद्र कुमार बिहार के कैमूर जिले के हरिनाथपुर स्थित अहिनौरा गांव के रहने वाले हैं।

अनुसंधान | तपेदिक के 100 साल पुराने टीके में नई शक्ति जोड़ने की पहल

और बढ़ेगी नौ हजार साल पुरानी बीमारी से लड़ने की क्षमता

WITWATERSRAND : तपेदिक 9,000 साल से भी अधिक पुराना है। यह सबसे संक्रामक जीवाणु रोग है और 2022 में एक करोड़ छह लाख लोग इससे बीमार पड़े। इनमें से 23 प्रतिशत अफ्रीका में थे। तपेदिक के खिलाफ एकमात्र टीका, बैसिलस कैलमेट-गुएरिन (बीसीजी) टीका, 100 वर्ष से अधिक पुराना है और मुख्य रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए प्रभावी है। यूनिवर्सिटी ऑफ विटवाटरसैंड स्कूल ऑफ पैथोलॉजी के शोधकताओं ने बीसीजी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जीन-संपादन करके टीका विकास में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।

प्रमुख शोधकताओं में से एक, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बवेश काना, द कन्वरसेशन अफ्रीका के नादिन ड्रेयर को इस सफलता के पीछे का विज्ञान और अन्य टीकों के लिए इसकी क्षमता के बारे में बताते हैं।

टीके कैसे काम करते हैं?

टीके मुख्य रूप से खतरनाक संक्रामक एजेंटों की नकल करके काम करते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली वैक्सीन को 'आक्रमणकारी' के रूप में पहचाने और फिर इसके प्रति प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करे। लेकिन आप नहीं चाहेंगे कि आक्रामक एजेंट आपको बीमार कर दे। यह समझने के लिए कि टीके कैसे काम करते हैं, यह देखने में मदद मिलती है कि

प्रतिरक्षा प्रणाली कैसे काम करती है, क्योंकि टीके आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली की प्राकृतिक गतिविधि का उपयोग करते हैं।

प्रतिरक्षा प्रणाली: जठरांत्र पथ में लगभग 100 खरब बैक्टीरिया और वायरस होते हैं। बैक्टीरिया, वायरस या अन्य रोग पैदा करने वाले रोगजनकों की सतह पर मौजूद प्रोटीन और शर्करा का आकार मानव शरीर में मौजूद प्रोटीन और शर्करा से भिन्न होता है। ये मार्कर रोगजनक से जुड़े आणविक पैटर्न हैं, जिन्हें आमतौर पर पीएएमपी के रूप में जाना जाता है। कोरोनोवायरस पर स्पाइक्स के बारे में सोचें। तो, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली आक्रमणकारियों को तुरंत पहचान लेती है। और शरीर घटनाओं की एक जटिल श्रृंखला से लड़ता है जिसमें कई अलग-अलग प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं एक साथ काम करती हैं। एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाने में सक्षम है। ये एंटीबॉडी बैक्टीरिया की सतह पर प्रोटीन या शर्करा से चिपक सकते हैं, और यह बैक्टीरिया को मारता है या उन्हें निष्क्रिय कर देता है। उनका आकार बिल्कुल सही होना चाहिए, कुछ-कुछ दरवाजे में फिट होने वाली चाबी की तरह। इन श्वेत रक्त कोशिकाओं को बी-कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है। सही आकार की एंटीबॉडीज का उत्पादन करने में कई दिन लग सकते हैं। इस समय तक आपके शरीर में रोग पैदा करने वाले अरबों बैक्टीरिया हो सकते हैं। एक बार जब सही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं, तो वे तेजी से विभाजित हो जाती हैं और एक उत्पादन लाइन में बदल जाती हैं, जिससे एंटीबॉडी का समूह बनता है जो हमलावर एजेंटों से चिपक जाते हैं और उन्हें निष्क्रिय कर देते हैं। अंततः, आपका शरीर सभी आक्रमणकारियों से छुटकारा पा लेता है और आप स्वस्थ हो जाते हैं। एंटीबॉडीज रक्त में रहती हैं, और कुछ श्वेत रक्त कोशिकाएं विशिष्ट बैक्टीरिया के लिए स्मृति कोशिकाएं भी बन सकती हैं, यदि वे शरीर पर फिर से आक्रमण करते हैं। तो उपकरणों के इस संग्रहित शस्त्रागार के साथ प्रतिरक्षा प्रणाली भविष्य के आक्रमणों पर तुरंत प्रतिक्रिया करेगी।

टीके: टीके प्रतिरक्षा प्रणाली की तरह ही काम करते हैं। उनमें कमजोर या मृत बैक्टीरिया या वायरस या सतह से केवल कुछ प्रोटीन या शर्करा होते हैं। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को यह विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त है कि एक वास्तविक आक्रमणकारी शरीर में प्रवेश कर चुका है।

21 चालक दल के सदस्यों में से एक की मृत्यु

अरब सागर में पनामा के जहाज में लगी आग पर पाया गया काबू

AGENCY NEW DELHI : अरब सागर में पनामा के मालवाहक जहाज एमवी मैरस्क फ्रैंकफर्ट में लगी आग पर भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने पांचवें दिन काबू पा लिया है। रासायनिक विशेषज्ञों सहित चार सदस्यीय बचाव दल को सफलतापूर्वक जहाज पर चढ़ा दिया गया है। आग की घटना में मैरस्क फ्रैंकफर्ट के 21 चालक दल के सदस्यों में से एक की मृत्यु हो गई है। इस ऑपरेशन में आईसीजी के तीन जहाजों और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टरों को लगाया गया है।

गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से श्रीलंका के कोलंबो जा रहे जहाज एमवी मैरस्क फ्रैंकफर्ट में 19

जुलाई को गोवा से लगभग 102 समुद्री मील दक्षिण-पश्चिम में आग लग गई थी। यह जहाज अंतरराष्ट्रीय समुद्री खतरनाक सामान (आईएमडीजी) कार्गो ले जा रहा था। अचानक आग लगने के बाद व्यापारिक जहाज के अगले हिस्से में विस्फोट ?होने से आग तेजी से भड़क गई। इस जहाज पर चालक दल के 21 सदस्यों में 17 फिलिपिनो, दो यूक्रेनी, एक मोंटेनिग्रिन और एक रूसी थे।

BRIEF NEWS

आज डोमिसाइल आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि देने का लिया संकल्प

RANCHI : झारखंडी सूचना अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष आदिवासी मूलवासी जन अधिकार मंच के केंद्रीय उपाध्यक्ष पूर्व प्रत्याशी हटिया विधानसभा क्षेत्र विजय शंकर नायक 24 जुलाई 2024 को 10 बजे डोमिसाइल आंदोलन में हुए शहीदों की 22 वीं पुण्य तिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। उन्होंने कहा कि स्मरण हो कि 24 जुलाई 2002 के डोमिसाइल स्थानीयता नीति एवं नियोजन नीति के आंदोलन में अपने अधिकार, अस्तित्व एवं राज्य की नौकरियों में अपने हिस्सेदारी को लेकर आदिवासी मूलवासी समाज द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन में हमारे क्रांतिकारी आंदोलनकारी साथी वीर शहीद कैलाश कुजूर, विनय तिग्गा एवं संतोष कुंकल ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनकी 22वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आगामी 24 जुलाई 2024 को समय प्रातः 10 बजे स्थान त्रिमूर्ति चौक मेंकोन कॉलोनी डोरंडा रांची में विजय शंकर, आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष राजू महतो श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन शहीदों को माल्यार्पण कर संकल्प लेंगे।

जेएसएससी की सहायक आचार्य परीक्षा अब 28 को

RANCHI : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से सहायक आचार्य की कक्षा छह से आठवीं के लिए अब 28 जुलाई को परीक्षा होगी। यह परीक्षा 25 जुलाई को होने वाली थी, लेकिन इस दिन नक्सली बंदी के वजह से स्थगित कर दी गई है।

आदिवासी छात्र संघ ने पारा शिक्षकों को समर्थन देने का किया एलान

RANCHI : आदिवासी छात्र संघ ने झारखंड के पारा शिक्षकों के समर्थन घोषणा की है। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ के संगम उरांव ने कहा कि पारा शिक्षकों की स्थिति को लेकर जो संघर्ष चल रहा है, वह न केवल उनके अधिकारों के लिए, बल्कि पूरे शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता के लिए भी महत्वपूर्ण है। पारा शिक्षक हमारे शिक्षा तंत्र का अभिन्न हिस्सा हैं। पारा शिक्षकों ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अनेक विद्यार्थियों को शिक्षा का अधिकार उपलब्ध कराया। इन शिक्षकों को उचित मानदेय, स्थिरता और सम्मान मिलना ही चाहिए।

बारिश में भी हड़ताल पर डटे रहे मनरेगा कर्मी

RANCHI : झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ का अनिच्छित कालीन हड़ताल का आज दूसरा दिन भारी बारिश मे भी जारी रहा। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में मनरेगा कर्मचारी हड़ताल पर डटे रहे। संघ ने अपना नैतिक समर्थन झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ को लिखित रूप में दिया। संघ के ब्रजेश कुमार ने राज्य भर से आए बीएफटी संघ को संबोधित करते हुए कहा कि मनरेगा संघ की मांगे जायज है। जिस तरह मनरेगा कर्मियों से काम लिया जाता है उतना मानदेय नहीं दिया जाता है। जो अन्यायपूर्ण है। यही स्थिति बीएफटी कर्मियों की भी हैं।

हाईकोर्ट ने चिकित्सा में लापरवाही से संबंधित याचिका की सुनवाई के दौरान कहा-

रिम्स में चिकित्सा व्यवस्था में हो सुधार वरना इसे बंद करना बेहतर

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों में चिकित्सा में लापरवाही से संबंधित एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान रिम्स की कुव्यवस्था पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से मौखिक कहा कि या तो रिम्स में चिकित्सा उपकरण, मेडिकल फैसिलिटी सहित आधारभूत संरचना उपलब्ध कराई जाए अन्यथा इसे बंद करना ज्यादा बेहतर होगा। कोर्ट ने कहा कि रिम्स में मेडिकल सुविधाओं का अभाव, मरीज के देखभाल में लापरवाही अक्सर देखने को मिलता है। रिम्स की व्यवस्था सही नहीं रहने पर लोग प्राइवेट अस्पतालों के शरण में जा रहे हैं। रांची शहर में ही कई प्राइवेट अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे इन प्राइवेट अस्पतालों की संख्या झारखंड में दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम में हेल्थ केयर की जगह वेल्थ केयर पर ध्यान रखा जाता है। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल करने का आग्रह किए जाने पर मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि शपथ पत्र में राज्य सरकार की ओर से ऐसी बातें कही जाती हैं, जिससे लगता है कि स्विट्जरलैंड में हैं। कोर्ट ने पिछले पांच सालों में झारखंड में क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं लेने वाले नर्सिंग होम एवं अस्पतालों पर कार्रवाई और इस एक्ट का अनुपालन नहीं वालों पर लगे जुमार्ना के संबंध में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को बताने को कहा है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का अनुपालन नहीं करने वाले अस्पताल एवं नर्सिंग होम पर कितना जुमार्ना लगाया गया है। मामले के अगली सुनवाई आठ अगस्त को होगी। याचिकाकर्ता के पिता की मौत मेदांता, रांची में अक्टूबर 2017 को इलाज में लापरवाही की वजह से हुई थी। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर झारखंड में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने एवं इस एक्ट का अनुपालन करने का निर्देश अस्पतालों को देने का आग्रह किया गया था। बाद में कोर्ट ने इस विषय में वृहत संभावनाओं को देखते हुए इसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था।

सड़कों पर फेंके रहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट

राज्य में नर्सिंग होम एवं हॉस्पिटल से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण को लेकर झारखंड ह्यूमन राइट कनफेडरेशन की जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डायरेक्टर इन चीफ, हेल्थ डिपार्मेंट के शपथ पत्र पर असंतोष जताया। मौखिक कहा कि डायरेक्टर इन चीफ, हेल्थ ने दावा किया है कि झारखंड के 1633 प्राइवेट और पब्लिक नर्सिंग होम से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट का निष्पादन कर दिया जाता है। बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट के साथ इन सभी 1633 नर्सिंग होम का करार है, जिससे उनके मेडिकल वेस्ट का प्रतिदिन उठाव किया जाता है। कोर्ट ने उनके इस जवाब पर आश्चर्य जताते हुए मौखिक कहा कि झारखंड में नर्सिंग होम के निकट सड़कों पर मेडिकल वेस्ट फेके रहते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल नहीं होता है।

साइबर ठगी के पांच दोषियों को पांच पांच साल की सजा और जुमार्ना

RANCHI : पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने मंगलवार को बैंक अधिकारी बनकर करोड़ों की साइबर ठगी करने के पांच दोषियों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने सभी पर ढाई-ढाई लाख रुपये का जुमार्ना लगाया है। अदालत में पांचों को बीते शनिवार को दोषी करार दिया था। दोषियों में गणेश मंडल, प्रदीप मंडल, संतोष मंडल, पिंटू मंडल और अंकुश कुमार मंडल शामिल हैं। सभी जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के मिरगा गांव निवासी हैं इनमें चार बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में जबकि एक देवघर जेल में बंद है। सुनवाई के दौरान अंकुश को वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश किया गया था। अन्य सभी सशरीर अदालत में उपस्थित थे।मामले में ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक अतीश कुमार ने 24 गवाहों को प्रस्तुत किया। साथ ही काफी संख्या में दस्तावेज को चिन्हित कराया गया। दोषियों पर फर्जी पते पर सिम कार्ड लेने और बैंक अधिकारी बनकर लोगों को कॉल करके साइबर अपराध करने का आरोप है। सभी केवाईसी अपडेट करने के नाम पर ओटीपी पूछकर उनके खातों से पैसे निकाल लेते थे। ईडी ने साइबर अपराध के किसी मामले में पहली बार छह अगस्त, 2018 को मनी लांड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था। जांच पूरी करते हुए ईडी ने 27 मई, 2019 को पांचों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में इनके खिलाफ 13 दिसंबर, 2019 को आरोप गठित किया गया।

राज्य के सभी मंदिरों, मठों और धर्मशालाओं को

15 दिनों के भीतर पंजीयन कराने का दिया गया निर्देश

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड राज्य हिन्दू धार्मिक न्यास बोर्ड ने राज्य के सभी मंदिर, धर्मशाला, मठ, चैरिटेबल ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन कराने को कहा है। इस संबंध में बोर्ड के अध्यक्ष जय शंकर पाठक की ओर से सूचना भी जारी की गयी है। इसमें कहा गया है कि हिन्दू विधि द्वारा मान्यता प्राप्त धार्मिक, पवित्र या चैरिटेबल के लिए विद्यमान या आन्वयिक न्यास ह्यधार्मिक न्यासह्व है। इसके अंतर्गत मंदिर, मठ, धर्मशाला एवं चैरिटेबल ट्रस्ट हो सकते हैं। ऐसे सभी धार्मिक न्यासों को झारखंड राज्य हिन्दू धार्मिक न्यास बोर्ड, रांची से अधिनियम की धारा-34 (हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950) के अंतर्गत पंजीयन कराना कानूनी अनिवार्यता है। ऐसे में झारखंड में अवस्थित मंदिर, मठ, धर्मशाला एवं चेयरमैन ट्रस्ट के प्रबंधकों को आगामी 15 दिनों के अंदर इन धाराओं का अनुपालन हर हाल में करना अनिवार्य होगा। इनमें धारा-34 के तहत धार्मिक न्यास का बोर्ड से पंजीकरण कराना शामिल है। धारा-58 के आदेशों, निदेशों का पालन, धारा-59 के तहत न्यास का ब्यौरा-विवरण निर्धारित फॉर्मेट में बोर्ड को भेजना, धारा-60 के तहत न्यास के आगामी वित्त वर्ष के आय-व्यय का बजट विवरण 15 जनवरी तक बोर्ड में दाखिल करना तथा धारा-70 के तहत न्यास के सकल वार्षिक आय में 20 प्रतिशत राशि और न्यास द्वारा देय सरकारी कर राशि को घटा कर शेष शुद्ध आय का पांच प्रतिशत पर्षद शुल्क बोर्ड कार्यालय में अविलंब जमा करना शामिल है। बोर्ड के मुताबिक, अगले 15 दिनों के भीतर जारी किए गए निदेशों का पालन नहीं किए जाने पर चिह्नित धार्मिक न्यासों के प्रबंधकों, व्यवस्थापकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

झामुमो के कोल्हान प्रमंडल के पंचायत स्तरीय कार्यकताओं की बैठक आयोजित

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां जिला के पंचायत स्तरीय कार्यकताओं की बैठक रांची के हरमू स्थित सोहराई भवन के सभागार में मंगलवार को हुई। बैठक में राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार और सांगठनिक रूप से युद्ध स्तर पर कार्यक्रमों को आयोजित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही योजनाओं का लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में आए सभी कार्यकताओं को पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बोधित किया। इस दौरान सोरेन ने कार्यकताओं में उत्साह तथा ऊर्जा भरा। मौके पर गांडेय विधानसभा क्षेत्र से विधायक कल्पना सोरेन ने कार्यकताओं को योजनाओं की जानकारी के साथ-साथ संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने कार्यकताओं के मन में राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में उठ रही जिज्ञासाओं को शांत किया तथा संगठन की मजबूती के लिए बूथ स्तर पर कार्यक्रम करने की बात कही। बैठक में कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम एवं सरायकेला-खरसावां जिला के जिला समिति के सभी पदाधिकारी, वर्ग संगठनों के अध्यक्ष एवं सचिव, नगर, महानगर समिति के पदाधिकारी, प्रखंड समिति के पदाधिकारी तथा पंचायत समिति के अध्यक्ष तथा सचिव शामिल थे।

बैठक को संबोधित करते झामुमो नेता। ● फोटोन न्यूज

डीटीओ ने चलाया सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान

RANCHI : सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुकता लाने को लेकर रांची डीटीओ अखिलेश कुमार एवं सड़क सुरक्षा अभियंता गौरव कुमार के द्वारा दीपाटोली कैंप में कारगिल विजय दिवस पर हथियार तथा उपकरणों का प्रदर्शन करते हुए सड़क सुरक्षा का स्टॉल लगाया गया। इस समारोह में उपस्थित आर्मी ट्रक ड्राइवर्स तथा एनसीसी कैडिडेट का संयुक्त रूप से कॉन्फ्रेंस किया गया। जिसमें डीटीओ अखिलेश कुमार सड़क सुरक्षा अभियंता गौरव कुमार एवं आर्मी पुलिस के अधिकारी उपस्थित थे। गौरव ने टश अू३ तथा इसके उल्लंघन करने वालों पर की जाने वाली कार्रवाई के संदर्भ में बताया। सड़क दुर्घटनाओं में हिट एंड रन से संबंधित जानकारी दी। डीटीओ ने जिलेवासियों से अपील की है कि वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन जरूर करे।

सहायक पुलिसकर्मियों ने आंदोलन को और आगे बढ़ाने का किया एलान

PHOTON NEWS RANCHI : सहायक पुलिसकर्मियों ने सरकार के साथ सोमवार को बैठक में आंदोलन समाप्त करने की घोषणा के बाद मंगलवार को एक बार फिर से आंदोलन को आगे जारी रखने का ऐलान किया है।झारखंड सहायक पुलिस प्रदेश संगठन के अध्यक्ष अविनाश द्विवेदी और सचिव विवेकानंद गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ हुई वार्ता में जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है यदि वह मांग 24 तारीख को होने वाली कैबिनेट में मान ली जाती तभी वे आंदोलन समाप्त करेंगे। जब तक सरकार उनकी मांगों को कैबिनेट में नहीं ले आती है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर मौजूद सहायक पुलिसकर्मी उज्जवल कुमार ने कहा कि सोमवार को भारी मानसिक दबाव के बीच अधिकारियों और विधायकों ने उनसे वार्ता की। दबाव डालकर उनसे आंदोलन समाप्त करवाने की घोषणा कराई गई लेकिन किसी भी दबाव के आगे वो नहीं झुकेंगे और अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। सहायक पुलिसकर्मियों का आरोप है कि हर साल उनके साथ छल किया जा रहा है। वर्ष 2020 में मंत्री मिथिलेश ठाकुर और 2021 में विधायक बंधु तिर्की ने आश्वासन दिया था लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। उल्लेखनीय है कि दो जुलाई से सहायक पुलिसकर्मी रांची के मोरहाबादी मैदान में विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। बीते सोमवार को सरकार की ओर से गठित समिति के साथ हुई बैठक के बाद पांच बिंदुओं पर सहमति बनी थी। इसके बाद उन्होंने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की थी लेकिन मंगलवार को सभी सहायक पुलिस कर्मियों से सहमति बनने के बाद आंदोलन जारी रखने की बात कही जा रही है।

विश्व आदिवासी दिवस के लिए संगठनों ने शुरू कर दी तैयारी

PHOTON NEWS RANCHI : विश्व आदिवासी दिवस को लेकर केन्द्रीय सरना समिति एवम विभिन्न आदिवासी संगठनों ने अपनी ओर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसको लेकर मंगलवार को मोरहाबादी चिल्ड्रेन पार्क में एक बैठक हुई। इस बैठक नेतृत्व केन्द्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने किया इस बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को भव्य तरीके से मनाया जाएगा। आदिवासी परंपराओं के अनुसार धूमधाम से अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर विकास टोप्पो, अजीत उरांव, अनिल लिंडा,रुपचंद तिर्की, विजय कच्छप, गएना कच्छप, सचिन कच्छप, मुन्ना मिंज, जयंत कच्छप, सिता खलखो, विनिता, फूलजेनसिया लिंडा सुभानी, सुचीता, लोग उपस्थित थे।

सीईओ की मतदाताओं से अपील ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम जांच लें

PHOTON NEWS RANCHI : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि राज्य में 25 जुलाई को मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के अवसर पर सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ के द्वारा इस मतदाता सूची के प्रारूप को प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे 25 जुलाई को सुबह अपने मतदान केंद्र जाकर अपना नाम इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जरूर चेक कर लें। यदि कोई विसंगति हो तो तत्काल अपने बीएलओ को बताएं। के. रवि कुमार राज्य में चल रहे मतदाता सूची के द्वितीय विशिष्ट संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 25 जुलाई को होने वाले मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के संदर्भ में निर्वाचन सदन में मंगलवार को आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि लोग चाहें तो घर बैठे ही निर्वाचन आयोग के ऑनलाइन माध्यमों जैसे वोटर हेल्पलाइन ऐप या वोटर सर्विस पोर्टल के माध्यम से भी अपना नाम जांच सकते हैं। मतदाता मोबाइल से एसएमएस के माध्यम से भी मतदाता सूची में अपना नाम जांच सकते हैं। इसके लिए अपने नंबर से आईसीआई लिखकर फिर एक स्पेस देकर अपना मतदाता पहचान पत्र (एपिक) नंबर लिखकर 1950 पर मैसेज करने से मतदाता पंजीकरण से जुडी जानकारी मेसेज से ही उपलब्ध हो जाएगी।

राष्ट्रीय युवा शक्ति ने सड़क पर धनरोपनी कर जताया विरोध

PHOTON NEWS RANCHI : सड़क की जर्जर हालत पर राष्ट्रीय युवा शक्ति ने मंगलवार को रातू रोड गैलक्सी मॉल के समीप सड़क पर धान रोपनी कर विरोध जताया। राष्ट्रीय युवा शक्ति के केंद्रीय अध्यक्ष उत्तम यादव के नेतृत्व में धान रोपनी कार्यक्रम किया गया। मौके पर यादव ने कहा कि शास्त्री चौक से मधुकम, साई बिहार कॉलोनी, विद्यानगर, यमुनानगर, चूना भट्ठा, हरमू रोड, जाने वाले रास्ते पर काफी दिनों से बड़े-बड़े गड्ढे हैं। हर दिन घटना-दुर्घटना हो रही है। नगर निगम और रांची के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सभी गहरी नींद में सोए हुए हैं। सड़कों की स्थिति और रोजाना हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए राष्ट्रीय युवा शक्ति ने सड़क पर धान रोपनी कर विरोध जताया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मंटू वर्मा, अनिल वर्मा, बबलू टोप्पो, सोनू मेहरा, रिंकू कुमार, मंटू कुमार, बिरजू कुमार, बालेसर साहू, उमेश साहू, रंजन माथुर, आर्यन मेहता, रोहित यादव, निखिल गुप्ता, रवि सिंह, मिक्की कुमार, विशाल साहू और अजीत सहित अन्य शामिल थे।

आदर्श विद्यालय परियोजना के तहत शिक्षकों का दस दिवसीय प्रशिक्षण शुरू

24 जिलों में 439 विद्यालय बनेंगे आदर्श स्कूल

PHOTON NEWS RANCHI : मंगलवार को अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव जिला विद्यालय, रांची के सभागार में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् रांची एवं स्कूलनेट इंडिया लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में जिला शिक्षा पदाधिकारी, रांची के आदेशानुसार मुख्यमंत्री उत्कृष्ट अरळश्र एएसटीवीएस जिला विद्यालय, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट टीवीएस जगरनाथपुर, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका विद्यालय बरियातू, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट आदर्श विद्यालय काके, एवं मुख्यमंत्री उत्कृष्ट कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नामकुम के 36 शिक्षकों को कंप्यूटर विषय पर दस दिवसीय प्रशिक्षण का एएसटीवीएस जिला विद्यालय के एक्टिंग प्रिंसिपल श्रीमती मंजुला एक्का के द्वारा शुभारंभ किया गया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य आदर्श विद्यालय परियोजना और मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय परियोजना के अंतर्गत संचालित किये जा रहे विद्यालयों में तकनीकी शिक्षा को बेहतर बनाने हेतु शिक्षकों में कंप्यूटर के बारे में बुनियादी जानकारी देना और उनकी शैक्षिक दक्षता को बढ़ाना है। इस दस दिवसीय प्रशिक्षण में मुख्यतः परियोजना द्वारा लगाये गए उबंटू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में शिक्षकों का कौशल विकास करना है। साथ ही प्रशिक्षण में लिब्रे ऑफिस-राइटर, वर्ड प्रोसेसिंग, मैनेजिंग स्प्रेडशीट यूजिंग लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस के उपयोग से प्रेजेंटेशन तैयार करना, हिंदी और इंग्लिश स्क्रिप्ट टाइपिंग टेक्स्ट एवं अन्य आधारभूत चीजों के बारे में बताया जायेगा। प्रशिक्षण में झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये गए रिसोर्स के उपयोग के बारे में भी बताया जायेगा।

कार्यक्रम का उद्घाटन करतीं अतिथि। ● फोटोन न्यूज

अंग्रेजी माध्यम में बदले जा रहे विद्यालय

प्रखंड स्तर 325 विद्यालयों को आदर्श विद्यालय एवं 34 विद्यालयों को इंग्लिश मीडियम विद्यालय के तौर पर विकसित किया जा रहा है। इन विद्यालयों में कम से कम 10 कंप्यूटर एवं 20 कंप्यूटर का आई.सी.टी लैब एवं तीन डिजिटल स्मार्ट क्लास स्थापित किया जाता है जो उबंटू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित होता है। प्रशिक्षण में स्कूलनेट इंडिया लिमिटेड के डी०ई०एफ दीपक कुमार, मास्टर ट्रेनर्स आशीष कुमार पंडित, पवन कुमार एवं अबु बकर मौजूद थे।

हटिया-बर्धमान मेमू एक्स. रद्द, 30 मिनट विलंब से चलेगी धनबाद-भुवनेश्वर ट्रेन

PHOTON NEWS RANCHI : दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची मंडल में ब्लॉक करने के कारण धनबाद स्टेशन होकर चलने वाली 13504 व 13503 हटिया-बर्धमान मेमू एक्सप्रेस 23, 25 और 29 जुलाई को रद्द रहेगी। 25 और 29 जुलाई को धनबाद से चलने वाली ट्रेन संख्या 02831 धनबाद-भुवनेश्वर स्पेशल को धनबाद से 30 मिनट विलंब से चलेगी। वहीं उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल के प्रयागराज स्टेशन पर चल रहे उन्नयन कार्यों के कारण ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होने वाला है। गोमो स्टेशन होकर चलने वाली ट्रेन संख्या 18609 रांची- लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस को पं. दीन दयाल उपाध्याय-मिजार्पुर- प्रयागराज छिवकी-माणिकपुर होकर 24 जुलाई तक चलाया जाना था। इसकी अवधि में विस्तार किया गया है। अब यह ट्रेन 14 अगस्त तक इसी परिवर्तित मार्ग से चलेगी। इस दौरान प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर ट्रेन का अतिरिक्त ठहराव होगा। ट्रेन संख्या 18610 लोकमान्य तिलक-रांची एक्सप्रेस माणिकपुर-प्रयागराज छिवकी- मिजार्पुर-पंडित दीन दयाल उपाध्याय होकर 19 जुलाई तक चलाना था। लेकिन इस अवधि में विस्तार किया गया है, यह ट्रेन नौ अगस्त तक परिवर्तित मार्ग से चलेगी। इस दौरान इसका भी अतिरिक्त ठहराव प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर होगा। वहीं ट्रेन संख्या 12816 आनंद विहार- पुरी एक्सप्रेस को कानपुर- लखनऊ- पंडित दीन दयाल उपाध्याय होकर 25 जुलाई तक चलाया जाना था। अब यह ट्रेन 15 अगस्त तक परिवर्तित मार्ग से ही चलेगी। धनबाद स्टेशन होकर चलने वाली ट्रेन संख्या 12495 बीकानेर-कोलकाता एक्सप्रेस आगरा कैंट-बीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-मानिकपुर-प्रयागराज छिवकी-पंडित दीनदयाल उपाध्याय होकर 25 जुलाई तक चलना था। लेकिन अब यह ट्रेन आठ अगस्त तक परिवर्तित मार्ग से चलेगी। आगरा कैंट और प्रयागराज छिवकी पर इसका अतिरिक्त ठहराव होगा।

पूर्वी सिंहभूम में बनेगा बालिका गृह व कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल

उपायुक्त ने की बाल संरक्षण इकाई, संप्रेक्षण गृह, बाल गृह, ओल्ड एज होम की सुविधाओं की समीक्षा

PHOTON NEWS JSR:
पूर्वी सिंहभूम में बालिका गृह एवं कामकाजी महिलाओं (वर्किंग वीमेन) के लिए हॉस्टल का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए उपायुक्त अनन्य मित्तल ने प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने मंगलवार को समाहरणालय सभागार में जिला बाल संरक्षण ईकाई की समीक्षा बैठक की। इसी क्रम में उन्होंने जिले में किशोर न्याय अधिनियम एवं नियमावली तथा समाज कल्याण विभाग के जिला बाल संरक्षण इकाई अंतर्गत संचालित विभिन्न संस्थानों की गतिविधियों, कार्यक्रमों तथा योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। जिले में संचालित संप्रेक्षण गृह, बाल गृह, विशेष दत्तक ग्रहण संस्थान, ओल्ड एज होम में रह रहे बच्चों एवं बुजुर्गों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की भी उन्होंने

बैठक को संबोधित करते उपायुक्त ● फोटोन न्यूज

जानकारी ली। इसके साथ ही मिशन वात्सल्य योजना, स्पॉन्सरशिप, फोस्टर केयर आदि की समीक्षा की। उपायुक्त ने बाल संरक्षण गृहों में रह रहे बच्चों के सुचारू पठन-पाठन, उन्हें विभिन्न शारीरिक-मानसिक गतिविधियों से जोड़ने, सभी गृहों में नियमित अंतराल पर बच्चों की स्वास्थ्य जांच करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाल संरक्षण समिति यह सुनिश्चित करे कि देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले नवजात, परित्यक्ता, बेसहारा, लावारिस, कूड़ा बीनने वाले उपेक्षित बच्चे, बाल श्रमिक, बाल विवाह, बाल वेश्यावृत्ति, असाध्य रोगों से पीड़ित बच्चे एवं अन्य किसी प्रकार के शोषण से पीड़ित बच्चे जिनकी उम्र 0 से 18 वर्ष के बीच हो, उन्हें बेसहारा और उपेक्षित होने से बचाना है। समिति की बैठक नियम व सरकार के आदेश के अनुसार समय-समय पर की जानी है। बैठक में उप विकास आयुक्त मनीष कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी संध्या रानी, जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारी कर्मी उपस्थित थे।

योजना के स्थल पर विवाद हो तो दूसरा स्थान चुनें : डीडीसी

JAMSHEDPUR : उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देश पर मंगलवार को विधायक मद अंतर्गत संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं डीसी (डिटेल कंटींजेंट) विपत्र की समीक्षा बैठक हुई। उपविकास आयुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में विधानसभावार लंबित डीसी विपत्र की समीक्षा में निर्देश दिया गया कि 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 की लंबित योजना को पूर्ण करते हुए डीसी बिल जमा करें। 2024-25 में जिन योजनाओं की अनुशंसा प्राप्त है, उनका प्राक्कलन 31 जुलाई तक जिला कार्यालय में जमा करें। निर्देश दिया गया कि लंबित योजनाओं को शीघ्र पूर्ण किया जाए। स्थल विवाद के कारण कोई योजना प्रारंभ नहीं होने पर स्थानीय विधायक से अनुशंसा लेकर दूसरे स्थल का चयन कर योजना प्रारंभ करना है।

भवनों से जुड़े प्रश्नों का जवाब विस को उपलब्ध कराएं : ग्लेन गॉलस्टन

बैठक को संबोधित करते सभापति ● फोटोन न्यूज

JAMSHEDPUR : परिसदन में मंगलवार को झारखंड विधानसभा की आवास समिति के सभापति ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन की अध्यक्षता व डीडीसी मनीष कुमार समेत जिला स्तरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में समिति की समीक्षा बैठक हुई। इसमें विभाग अंतर्गत आवास एवं भवन निर्माण से संबंधित झारखंड विधानसभा में उठाए गए इस जिले से संबंधित अलग-अलग प्रश्नों पर चर्चा की गई। तत्पश्चात गॉलस्टन ने संबंधित प्रश्नों पर आधारित रिपोर्ट विधानसभा कार्यालय को उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया। बैठक में गॉलस्टन ने जिला अंतर्गत पूर्व में बनाए गए सरकारी भवनों व आवासों की मौजूदा स्थिति, अग्नि नियंत्रण व तड़ित चालक जैसे सुरक्षा मानकों, पेयजल सुविधा, की जानकारी ली।

विद्यालयों में करें बायोमीट्रिक अटेंडेंस की जांच : उपायुक्त

बैठक को संबोधित करते उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ● फोटोन न्यूज

SARAIKELA : सरायकेला-खरसावां के समाहरणालय सभागार में मंगलवार को उपायुक्त रविशंकर शुक्ला की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षा हुई। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि ऐसे विद्यालय जहां बायोमीट्रिक अटेंडेंस नहीं बन रही है, वहां प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के माध्यम से जांच कराएं तथा ऐसे बच्चे जिनका बैंक खाता नहीं खुल रहा है, उनकी सूची तैयार कर अग्रणी बैंक प्रभारी के साथ समन्वय स्थापित कर शत प्रतिशत बच्चों का बैंक खाता खोलते हुए उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान कराएं। इसके अलावा सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में लंबित नामांकन कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। इससे पूर्व उन्होंने जिला में शैक्षणिक वातावरण निर्माण के लिए सभी शिक्षक अपनी मानसिकता बदल कर पूर्ण जबाबदेही के साथ कार्य करें। उपायुक्त ने कहा कि विद्यालय में बेहतर वातावरण बनाकर खेल-खेल में बच्चों को शिक्षा प्रदान करें, ताकि बच्चों की उपस्थिति बढ़ाई जा सके। उपायुक्त ने कहा कि विभिन्न माध्यम से विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर ड्रॉपआउट बच्चों को चिह्नित करते हुए विद्यालय से जोड़ें तथा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करें। उपायुक्त ने कहा कि विभिन्न विद्यालयों में पेयजल व शौचालय तथा मरमत कार्य से संबंधित संचालित एवं लंबित कार्य का समीक्षा कर दिशा-निर्देश दिए।

जमशेदपुर से 55 हिंदू तीर्थयात्री द्वारिका-सोमनाथ हुए रवाना

यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते डीडीसी ● फोटोन न्यूज

JAMSHEDPUR : झारखंड सरकार के टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के तत्वाधान में पूर्वी सिंहभूम के 55 हिंदू तीर्थयात्री (अटेंडर सहित) मंगलवार को द्वारिका-सोमनाथ तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए। समाहरणालय परिसर से सुबह 8.30 बजे इन्हें उपविकास आयुक्त मनीष कुमार एवं जिला खेल पदाधिकारी अविनेश त्रिपाठी ने बस द्वारा रांची स्थित हटिया रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया। रांची से तीर्थ यात्रियों का दल रेल मार्ग द्वारा द्वारिका-सोमनाथ प्रस्थान करेगा। सात दिवसीय तीर्थ यात्रा 23 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जुलाई को समाप्त होगी। झारखंड सरकार द्वारा आयोजित तीर्थ स्थल दर्शन में ऐसे नागरिकों को शामिल किया गया है, जो झारखंड के निवासी हैं, उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, वे बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं ।

रेलवे अर्बन बैंक के चुनाव के लिए आज 2 बजे से होगा मतदान

JAMSHEDPUR : रेल कर्मचारियों की को-ऑपरेटिव सोसाइटी(रेलवे अर्बन बैंक) के चुनाव को लेकर कोलकाता अलीपुर कोर्ट के चुनाव रोकने के आदेश को कोलकाता हाईकोर्ट ने बदल दिया है। कोर्ट ने मामले में की गई अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि पूर्ववत चुनाव के तिथि 24 जुलाई(बुधवार) को मतदान को सुबह 8 बजे के बजाएं दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक कराया जाएं। बुधवार को सुबह 11 बजे से इसी मामले में सुनवाई करेगी। अंतः 2 बजे के बाद ही चुनावी प्रक्रिया शुरू कराई जाएं। ऐसे में रेलवे के प्रिंसिपल चीफ पर्सनल अफसर ने पत्र जारी कर कहा है कि पूर्ववत चुनावी प्रक्रिया के अनुसार रेलवे अर्बन बैंक का चुनाव होगा। बुधवार को सुबह 8 बजे के बजाएं दोपहर 2 बजे से शाम बजे तक मतदान होगा।

टाटानगर से होकर चलने वाली 13 ट्रेनों में स्लीपर व जेनरल कोच बढ़ाने का आदेश

नवंबर के अंत तक लगने लगेंगे कोच, सीटों की मारामारी होगी खत्म

PHOTON NEWS JSR:
दक्षिण-पूर्व रेलवे जोन में लंबी दूरी की ट्रेनों में जेनरल व स्लीपर कोच की संख्या बढ़ने जा रही है। लंबी दूरी की ट्रेनों में सीट को लेकर मारामारी खत्म करने के लिए जोनल स्तर पर टाटानगर और हावड़ा स्टेशन से खुलने और गुजरने वाली 13 ट्रेनों में जेनरल व स्लीपर कोच बढ़ाने का आदेश जारी हुआ है। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक टाटा-अमृतसर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस, टाटा-एनार्कुलम एक्सप्रेस, टाटा-बेंगलुरु एक्सप्रेस, टाटा-यशवंतपुर एक्सप्रेस, हावड़ा-मुंबई एक्सप्रेस, हावड़ा-जगदलपुर एक्सप्रेस, हावड़ा-मुंबई मेल, हावड़ा-अहमदाबाद एक्सप्रेस, हावड़ा-हटिया क्रिया-योगा एक्सप्रेस, शालीमार-भुज एक्सप्रेस, हावड़ा-मुंबई गीतांजलि एक्सप्रेस व हावड़ा-मुंबई एक्सप्रेस में स्लीपर और जनरल कोच लगेंगे। इससे पहले टाटानगर से गुजरने वाली पटना-बिलासपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस में कोच बढ़ाने का आदेश है।

इन ट्रेनों में बढ़ेंगे डिब्बे

- हावड़ा-जगदलपुर एक्सप्रेस -1 अक्टूबर
- पटना-बिलासपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस- 8 नवंबर
- हावड़ा-मुंबई मेल - 15 नवंबर
- हावड़ा-मुंबई एक्सप्रेस - 22 नवंबर
- हावड़ा-अहमदाबाद एक्सप्रेस - 15 दिसंबर
- हावड़ा-मुंबई गीतांजलि एक्सप्रेस -15 दिसंबर
- टाटा-बेंगलुरु एक्सप्रेस - 20 दिसंबर
- शालीमार-भुज एक्सप्रेस - 21 दिसंबर
- हावड़ा-मुंबई एक्सप्रेस - 22 दिसंबर
- टाटा-अमृतसर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस - 25 दिसंबर
- टाटा-यशवंतपुर एक्सप्रेस - 26 दिसंबर
- टाटा-एनार्कुलम एक्सप्रेस - 28 दिसंबर
- हावड़ा-हटिया क्रिया-योगा एक्सप्रेस- 28 दिसंबर

समाचार सार

परसुडीह के बावनगोड़ा में महिला ने किया सुसाइड

JAMSHEDPUR : परसुडीह थाना क्षेत्र के बावनगोड़ा में मंगलावार की सुबह गीता महतो (37) ने सुसाइड कर लिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोगों ने इसकी सूचना परसुडीह थाने पर दी। बताया जा रहा है कि गीता महतो को एक भी संतान नहीं था। संतान नहीं होने की वजह से वह काफी परेशान रहती थी। परिवार के ताने भी सह रही थी। आशंका व्यक्त की जा रही है कि इसी वजह से उसने सुसाइड किया है। घटना की सूचना पर पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

कमलपुर थाना पहुंचे एसएसपी, लिया जाएजा

JAMSHEDPUR : एसएसपी किशोर कौशल मंगलवार को पटमदा के कमलपुर थाने पर पहुंचे। यहां उन्होंने अभिलेखों की जांच करने के साथ-

साथ आपराधिक आंकड़ों को भी देखा। इसके साथ ही इसको लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिया। अभिलेखों की जांच करने के साथ-साथ एसएसपी ने थाने के सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने लंबित कांडों, वारंट और कुर्की-जब्ती का समय पर निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया।

बोल बम के नारे से गूंजा सोनारी

JAMSHEDPUR : सावन में 28 जुलाई को आयोजित होने वाले 1100 लोगों की निःशुल्क कांवर यात्रा में सोनारी के कुल 245 लोग शामिल होंगे

। सोनारी के बाबा भूतनाथ मंदिर के प्रांगण में कांवर यात्रा में शामिल होने वाले लोगों की बैठक को संबोधित करते हुए संघ के संस्थापक सदस्य विकास सिंह ने बताया कि 28 जुलाई को दोपहर 1 बजे कदमा के रंकिणी मंदिर के पास ओल्ड फार्म एरिया मैदान में सभी 11 कांवरिया एकत्रित होकर मां रंकिणी की पूजा-अर्चना कर 18 कोच बस,12 छोटी गाड़ी से सुल्तानगंज के लिए प्रस्थान करेंगे। एक परिवार के रूप में कुल 1100 शिवभक्त 8 दिन के दौरे में जमशेदपुर से सुल्तानगंज जाएंगे। यात्रा में शामिल होने वाले लोग सभी एक समान रहेंगे। सभी बाबा बैद्यनाथ के शिष्य और पुजारी बनकर जा रहे हैं ।

बिष्टुपुर में राखी मेला का समापन आज

JAMSHEDPUR : मारवाड़ी महिला मंच, जमशेदपुर शाखा द्वारा तीन दिवसीय राखी मेला (प्रदर्शनी सह बिक्री) के दूसरे दिन मंगलवार को

बिष्टुपुर स्थित तुलसी भवन में जमशेदपुर प्रखंड की बीडीओ सुधा वर्मा पहुंचीं और मेला का अवलोकन किया। उन्होंने मारवाड़ी महिला मंच की प्रशंसा करते हुए मेले से ढेर सारी खरीदारी भी की। दूसरे दिन भी खरीददारी करने वालों की भीड़ रही।

इंटरैक्ट व रोट्रैक्ट क्लब के प्रेसिडेंट और सेक्रेट्री को दिलाई गई शपथ

डीबीएमएस कॉलेज सहित विभिन्न स्कूलों के क्लब का प्रतिष्ठापन समारोह आयोजित

PHOTON NEWS JSR:
रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर फेमिना ने रोटरी फेमिना के अंतर्गत संचालित रोट्रैक्ट क्लब डीबीएमएस बीएड कॉलेज फॉर एजुकेशन और इंटरैक्ट क्लब श्रीनाथ पब्लिक स्कूल आदित्यपुर, आरएमएस हाई स्कूल बालीचेला, चिन्मया विद्यालय बिष्टुपुर का प्रतिष्ठापन समारोह मंगलवार को हुआ। बिष्टुपुर स्थित होटल बुलेवर्ड में हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉ. आर भरत ने इंटरैक्ट और रोट्रैक्ट क्लब के प्रेसिडेंट व सेक्रेटरी को रोटरी पिन देकर नए सत्र की शपथ दिलाई। रोट्रैक्ट क्लब की अध्यक्ष आफरीन

कार्यक्रम के दौरान मौजूद क्लब के सदस्य ● फोटोन न्यूज

शेख ने बताया कि इस वर्ष पर्यावरण संरक्षण पर रोट्रैक्टर्स के प्रोजेक्टस होंगे। इंटरैक्ट क्लब चिन्मया विद्यालय बिष्टुपुर के अध्यक्ष आलोक राज, आरएमएस खूंटाडीह की अध्यक्ष श्रव्या बाग और श्रीनाथ पब्लिक स्कूल आदित्यपुर के अध्यक्ष तेजस परासर ने भी अपनी योजनाओं के बारे में बताया। डॉ. आर भरत ने कहा कि ईश्वर हमें मनुष्य के रूप में धरती पर भेजता है, तो हमें यहां अच्छे काम कर ईश्वर का कर्ज अदा करना चाहिए। अध्यक्ष सीमा कुमार ने अतिथियों का स्वागत एवं कार्यक्रम का संचालन किया।

मानगो में 83 किलो गांजा प्रकरण से मो. नौशाद रिहा

JAMSHEDPUR : जमशेदपुर कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान साक्ष्य के अभाव का लाभ गांजा प्रकरण में आरोपित मोहम्मद नौशाद को मिला और उसे रिहा कर दिया गया।
मामला 10 मई 2015 का है, जब थाना प्रभारी लक्ष्मण प्रसाद ने गुप्त सूचना के आधार पर कदमा के थाना प्रभारी राजेश प्रकाश सिन्हा के साथ टीम बनाकर रोड नंबर 14 स्थित मोहम्मद नौशाद के घर पर छापामारी की थी। प्लास्टिक के दो बोरे में क्रमशः 42 और 36 किलो तथा पॉलिथीन में रखा पांच किलो, कुल 83 किलो गांजा बरामद हुआ था। मानगो पुलिस ने 30 जून 2015 को एनडीपीएस की धारा के तहत आरोप पत्र अदालत में समर्पित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से छह गवाही हुई।

आरआईटी में युवक का शव बरामद, हत्या की आशंका

SARAIKELA : सरायकेला जिले के आरआरआईटी थाना क्षेत्र अंतर्गत पार्वतीपुर गांव से मंगलवार सुबह स्थानीय 20 वर्षीय युवक का शव गांव के तालाब के पास से बरामद किया गया है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान वीर सिंह हांसदा के रूप में की गई है। वह स्थानीय कंपनी में मजदूर था। मृतक के छोटे भाई ने बताया कि वह सोमवार की दोपहर से लापता था। काफी खोजबीन के बाद भी पता नहीं चल सका था। इस बीच मंगलवार की सुबह गांव के तालाब के पास से उसका शव बरामद हुआ।
मृतक वीर सिंह हांसदा के छोटे भाई विश्वनाथ हांसदा ने बताया कि भाई के मृत शरीर पर कई गंभीर चोट के निशान हैं। आंख को भी कुचल दिया गया है। शव देखने से प्रतीत होता है कि पत्थर से कूचकर निर्मम हत्या की गई है। इधर घटना की जानकारी होने पर आरआईटी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज कर जांच शुरू कर दी है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के विभिन्न संयंत्रों से आए एक्जीक्यूटिव ट्रेनी

एनएमएल में चार दिवसीय कॉरपोरेट प्रशिक्षण एमसीबीए आरंभ

PHOTON NEWS JSR:
बमार्माइंस स्थित सीएसआईआर-एनएमएल (राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला) में खनिज प्रसंस्करण विभाग की ओर से चार दिवसीय कॉरपोरेट प्रशिक्षण (एमसीबीए-2024) मिनरल कैरैक्टराईजेशन बेनिफिसियेशन एवं एग्लोमोरेशन विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया। इस मौके पर संस्थान के निदेशक डॉ. संदीप घोष चौधुरी ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के विभिन्न संयंत्रों से आए एक्जीक्यूटिव ट्रेनी का स्वागत किया और कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों से उद्योग जगत में नई सृजनात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण गतिविधियों को बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। पर्यावरण क्षेत्र में खनिज प्रसंस्करण का अहम योगदान रहा है, जिसमें मिनरल क्षेत्र में रिकवरी

कार्यक्रम को संबोधित करते निदेशक व उपस्थित प्रतिभागी ● फोटोन न्यूज

एवं रिप्रोड्यूस करने में नई तकनीक का उपयोग अहम सिद्ध होगा। मानव संसाधन, प्रमुख डॉ. शिवा प्रसाद ने प्रतिभाग्रियों से कहा कि खनिज प्रसंस्करण क्षेत्र में नई तकनीकी सहयोग एवं आपसी औद्योगिक साझेदारी से तकनीकी विकास में नई दिशा मिलेगी। खनिज प्रसंस्करण विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. शोभना डे ने कहा कि विज्ञान के बिना उद्योग और उद्योग के बिना विज्ञान अधूरा है। कार्यक्रम संयोजक डॉ. रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 23 जुलाई से 26 जुलाई तक प्रतिदिन दो सत्र में आयोजित किया जाएगा। प्रथम सत्र में हमारे वैज्ञानिक द्वारा संबंधित विषय पर व्याख्यान दिया जाएगा तथा दूसरे सत्र में वृहद स्तरीय प्रायोगिक संयंत्र (पायलट प्लांट) में डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम के सफल आयोजन में खनिज प्रसंस्करण विभाग के वैज्ञानिक डॉ. मनोज कुमार मोहन्ता, डॉ. राजेंद्र कुमार रथ, डॉ. अरी विद्याधर, अजित स्वाईं, डॉ. गणेश चालवाडी, अभिषेक कुमार सहित अनेक लोगों का योगदान रहा।

शबरी का रूप धरकर आभा गोराई व इशिता ने मोहा मन

PHOTON NEWS JSR:
सिंहभूम जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन, तुलसी भवन संस्थान के तत्वावधान में चल रहे तुलसी जयंती समारोह के तहत 13 जुलाई को संपन्न कक्षा 1 से 3 तथा 4 से 6 तक की छात्राओं के लिए 'माता शबरी रूप सज्जा प्रतियोगिता' का आयोजन किया गया। दो वर्गों में विभक्त प्रतियोगिता में शहर के 27 विद्यालयों से 142 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
ये रहे विजेता : वर्ग-अ (कक्षा 1 से 3) : प्रथम-आभा महेश गोराई (एआईडब्ल्यूसी सेंटर फॉर एक्सीलेंस), द्वितीय-प्रगीता शरण

प्रतियोगिता में शामिल बच्चे

(एसडीएसएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस), अमायरा सिंह (विद्या भारती चिन्मया विद्यालय, टेल्को), तृतीय-तनुश्री कुमारी (आरवीएस एकेडमी, मानगो), प्रोत्साहन पुरस्कार-वेदिका राय (गम्हरिया हाई स्कूल)। वर्ग-ब (कक्षा - 4 से 6) : प्रथम- इशिता (चिन्मया विद्यालय, साउथ पार्क, बिष्टुपुर), द्वितीय-मंदिरा साहु खां (एसडीएसएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, सिदगोड़ा), आरुषि सोना (गुरु गोविन्द सिंह हाई स्कूल, टेल्को), तृतीय-वंशिका कुमार (एसएस एकेडमी, बालीगुमा, मानगो), रागिनी कुमारी (मध्य एवं उच्च विद्यालय, लक्ष्मीनगर, टेल्को), प्रोत्साहन पुरस्कार- भव्या वर्मा, शिखा कनौजिया (दोनों एसबीएम, मानगो), संचिता नायर (प्रगति सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, बिरसानगर), ममता कुमारी, (मध्य एवं उच्च विद्यालय, लक्ष्मीनगर, टेल्को)।

जेकेएस कॉलेज में विद्यार्थियों को मानवाधिकार से कराया अवगत

कार्यक्रम में मौजूद विद्यार्थी ● फोटोन न्यूज

JAMSHEDPUR : मानगो स्थित जेकेएस कॉलेज में मंगलवार को 'आपका अधिकार आपकी शक्ति' थीम पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दल ने सुचित्रा सिन्हा की अध्यक्षता में छात्र-छात्राओं को जागरूक किया।
सिन्हा ने बताया कि मानवाधिकार मानव की शक्ति का परिचय है। यह मनुष्य को गरिमामय जीवन जीने के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। उन्होंने बताया कि मनुष्य को जन्म के पश्चात ही ये अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, जो उनकी मृत्यु तक उनके साथ रहते हैं। यहां तक कि शवो की अंतिम क्रिया भी गरिमा के साथ हो, यह मानवाधिकार है। अगर छात्र सशक्त होंगे तो वे अपनी रक्षा के साथ-साथ समाज के अन्य लोगों की रक्षा कर सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। उन्होंनें जेल संप्रेक्षण गृहों, आदिवासी आवासीय विधालय अनुसूचित जाति आवासीय विधालयों, कस्तूरबा गांधी आवासीय विधालयों में किस तरह मनवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा हैं, इसकी फोटो-वीडियो के साथ जानकारी दी।

शिष्यों में अर्जुन तत्व जगाने का समय

हमारे अद्भुत राष्ट्र भारत में धार्मिक और आध्यात्मिक गुरुओं का समृद्ध इतिहास है। उन्होंने वर्षों से लाखों हिंदुओं को पवित्र मार्ग दिखाया है, इसलिए हिंदू या भारतीय संस्कृति में गुरु तत्व का विशेष महत्व है। हालाँकि, धार्मिक और आध्यात्मिक गुरुओं के रूप में इस महान गुरु तत्व को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और इस तरह से सोचना चाहिए कि उनके लाखों अनुयायी राष्ट्र या भारत माता को खुद से ऊपर रखें। प्रत्येक गुरु को जातिगत भेदभाव और स्वार्थी प्रवृत्तियों को दूर करके हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास करना चाहिए। भले ही हमारे पास गुरुओं की एक लंबी और शक्तिशाली विरासत हो, लेकिन इस्लामी और ईसाई आक्रमणकारियों ने हम पर शासन और शोषण क्यों किया? इतना व्यापक धार्मिक रूपांतरण क्यों है? हर कोई, अमीर या गरीब, शांति और खुशहाल जीवन चाहता है, और धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु अपने अनुयायियों को शांतिपूर्ण रहने और खुशी और नैतिक रूप से जीने का तरीका सिखाने का हर संभव प्रयास करते हैं। हालाँकि, अगर आसपास का माहौल शांत और नैतिक नहीं है, सनातन धर्म के प्रति तीव्र तिरस्कार है, तो सनातनी और सनातन धर्म कैसे जीवित रह सकते हैं? धर्म परिवर्तन की वर्तमान दर के साथ सनातन धर्म कैसे टिक पाएगा? परिणामस्वरूप, प्रत्येक गुरु को राष्ट्र प्रथम सिद्धांत पर विचार करना चाहिए; अन्यथा, धर्म के दुश्मन मानवता को नष्ट करने के लिए अपनी शक्ति से सब कुछ बर्बाद करेंगे। गुरु पूर्णिमा, आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद और आचार्य चाणक्य को याद करने और सनातन धर्म और मानवता को बचाने के लिए उनके पदचिह्नों पर चलने का दिन है। अर्जुन तत्व का जागरण परम आवश्यक है। रामचरित मानस में गोस्वामी जी ने गुरु के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने अपनी चौपाई में कहा है कि-बंदउ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि।महामोह तम पुंज जासु बचन रबि कर निकर। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो दया के सागर हैं और मानव रूप में श्री हरि हैं, तथा जिनके वचन लोभ और स्वार्थ के घने अंधकार को नष्ट करने वाले सूर्य किरणों के समूह के समान हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार गुरु वह होता है, जिसके वचनों के अनुरूप कर्म होते हैं। क्या गुरु-शिष्य का रिश्ता किसी अन्य रिश्ते में हो सकता है? क्या अलग-अलग रिश्ते गुरुमय हो सकते हैं? हिंदू शास्त्रों के अनुसार, कृष्ण और अर्जुन दोनों मित्र और जिजा साले भी हैं। वे हमेशा साथ रहे और एक बंधन बनाया। वे मित्र बन गए, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में, जब अर्जुन ने दावा किया कि वह एक शिष्य की भावना से पूछ रहा था, तो कृष्ण ने एक गुरु की भावना से बात की, और ज्ञान का अमृत, गीता, उनके होठों से बरसा। जब अर्जुन गुरु तत्व में दृढ़ हो गया, तो श्री कृष्ण ने हर समय उसकी रक्षा की। प्रत्येक गुरु को अपने शिष्यों में अर्जुन को जगाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की तरह सोचने और कार्य करने का समय है। अर्जुन को जगाना महत्वपूर्ण है, अन्यथा महान धर्म नष्ट हो जाएगा। हम पहले ही कई सदियाँ खो चुके हैं, लेकिन हमारे पास सनातन धर्म या मानवता के विनाश को रोकने के लिए बहुत कम समय है। दुनिया तभी समृद्ध होगी जब सनातन धर्म सभी बाधाओं के बावजूद दृढ़ रहेगा, वैश्विक शांति, सद्भाव, सामाजिक-आर्थिक प्रगति और समभाव का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह तभी संभव हो सकता है जब हजारों गुरु हिंदुओं को एकजुट करने, अपने लाखों अनुयायियों में ₹राष्ट्र प्रथम₹ का दृष्टिकोण पैदा करने और उन्हें आवश्यक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक गुणों और आयामों से मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आधुनिक शंकराचार्य, धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु आदि शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद का अनुसरण क्यों करें? जब कोई हिंदू किसी धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेता है या पूजा करने के लिए मंदिर जाता है, तो वह हिंदू की तरह व्यवहार करता है। हालाँकि, जब हिंदू मंदिर के बाहर आते हैं और भौतिकवादी दुनिया में प्रवेश करते हैं, तो उनमें से कई लोग जातिगत भेदभाव, संप्रदाय, जिस राजनीतिक दल का वे समर्थन करते हैं, और कई ऐसे तत्वों का समर्थन करते हैं जो सनातन धर्म और भारत के संस्कृती का विरोध करते हैं। कई हिंदू इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि वे भूल जाते हैं कि उनका अस्तित्व सनातन धर्म और भारत के कारण है। ऐसा स्वार्थ न केवल हिंदुओं के लिए बल्कि महान राष्ट्र भारत के लिए भी हानिकारक है। व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ने और भारत को फिर से विश्वगुरु बनाने के लिए, प्रत्येक हिंदू को सनातन धर्म के सिद्धांतों को पूरी तरह से अपनाना होगा, वेदों, उपनिषदों और गीता से सभी वैज्ञानिक, प्रबंधन और जीवन कौशल का अध्ययन करना होगा और एक एकजुट हिंदू के रूप में समाज में आगे बढ़ना और काम करना होगा। मानवता के लिए काम करना और देश को सभी पहलुओं में शीर्ष पर वापस लाना। आदि शंकराचार्य और स्वामी विवेकानन्द ने सनातन और वैदिक सिद्धांतों के आधार पर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। आज, यह महत्वपूर्ण है कि धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु अपने अनुयायियों को न केवल अनुष्ठान करना सिखाएं, बल्कि सनातन सिद्धांतों का उपयोग करके ₹हिंदुत्व₹ के लिए काम करें और अनुयायियों को यह समझने में मदद करें कि वैज्ञानिक, सामाजिक आर्थिक, प्रबंधन तकनीक, जीवन कौशल का व्यावहारिक अनुप्रयोग कैसे किया जाता है, वैसे ही रक्षा तकनीक और शत्रुबोध जीवन का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि यह वैदिक सिद्धांतों के अनुरूप है।

डिजिटल के खंभे से टिकी दुनिया ने झेले सर्वर के झटके

ANALYSIS

डॉ. रमेश ठाकुर

कुलमिलाकर उनका जीवन भी डिजिटल हो चुका है। पर, युवा पीढ़ी गुजरे जमाने से अनभिज्ञ है, वो बिना आधुनिक सुविधाओं के रह ही नहीं सकती। निश्चित रूप से संपूर्ण संसार ने विकास की नई गाथा लिखी है। इंसान धरती से चांद तक पहुंच गया। लेकिन सच ये भी है विकास ही विनाश को जन्म देता है। सर्वाधिक सुविधाएं ही संसार में सन्नाटा पैदा करती हैं। जरा सोचिए, अगर माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर एकाध दिनों तक फेल हो जाए, तो मानव जीवन का क्या होगा? कल्पना करने मात्र से रूह कांप उठती है। बिना इंटरनेट के इंसान निश्चित रूप से अपंग हो जाएगा। क्योंकि उसकी जान ई-तंत्र में जो फंसी है। कहने में कोई हर्ज नहीं है कि आधुनिक युग की डिजिटल निर्भरता ने इंसान को पंगु बनाकर कहीं का भी नहीं छोड़ा। इंसान की लगाम, उसकी गति छोटे से कंप्यूटर रूपी डिब्बे में समा गई है। डिजिटल, इंटरनेट व सर्वर के बिना हम कितने अपाहिज हैं जिसकी तस्वीर हमने 19 जुलाई को खुली आंखों से देखी, इस समस्या पर इंसानी बस भी नहीं चलता।

डिजिटल की आदी हो चुकी दुनिया को माइक्रोसॉफ्ट के ठप हुए सर्वर ने ऐसा झटका दिया, जिसे कुछ क्षणों के लिए उनको गुजरा जमाना याद आ गया। सर्वर की तकनीकी खराबी ने तबाही मचा दी। चारों ओर कोहराम मच गया। दुनिया थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर हो गई। महानगरीय लोग भी देशी तरीकों से बड़े चाव और खुशहाल जीवन जी लेते थे। ग्रामीण आबादी तो बिना सुविधाओं के बिना हारी-बीमारी और अभावों में ही अच्छा जीवन जिया करते थे। हालांकि अब ग्रामीण अंचल भी सुविधा संपन्न हैं। महानगरों जैसी सुविधाएं गांव-देहातों में पहुंच चुकी हैं। इंटरनेट, एटीएम, पेटीएम, क्यूआरकोड, फिल्पकार्ड, एमोजोन, ओटीटी से सभी वाकिफ हैं। कुलमिलाकर उनका जीवन भी डिजिटल हो चुका है। पर, युवा पीढ़ी गुजरे जमाने से अनभिज्ञ है, वो बिना आधुनिक सुविधाओं के रह ही नहीं सकती। निश्चित रूप से संपूर्ण संसार ने विकास की नई गाथा लिखी है। इंसान धरती से चांद तक पहुंच गया। लेकिन सच ये भी है विकास ही विनाश को जन्म देता है। सर्वाधिक सुविधाएं ही संसार में सन्नाटा पैदा करती हैं। जरा सोचिए, अगर माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर एकाध दिनों तक फेल हो जाए, तो मानव जीवन का क्या होगा? कल्पना करने मात्र से रूह कांप उठती है। बिना इंटरनेट के इंसान निश्चित रूप से अपंग हो जाएगा। क्योंकि उसकी जान ई-तंत्र में जो फंसी है। कहने में कोई हर्ज नहीं है कि आधुनिक युग की डिजिटल निर्भरता ने इंसान को पंगु बनाकर कहीं का भी नहीं छोड़ा। इंसान की लगाम, उसकी गति छोटे से कंप्यूटर रूपी डिब्बे में समा गई है। डिजिटल, इंटरनेट व सर्वर के बिना हम कितने अपाहिज हैं

जिसकी तस्वीर हमने 19 जुलाई को खुली आंखों से देखी, इस समस्या पर इंसानी बस भी नहीं चलता। इंसान का प्रत्येक कार्य अब डिजिटल है। बैंकों में जमा पैसा भी डिजिटलाइट है। वो भी बिना सर्वर चले नहीं निकल सकता। क्योंकि बैंकों अब मैन्युअल कार्यों तक तालाबंदी हो चुकी है। ग्राहकों की चाहें कितनी भी जरूरत पैसे के वजह से क्यों न रुकी हो। अस्पताल में मरीज भर्ती हों या बच्चों की स्कूलों में फीस भरनी हो। बैंक पैसा तभी रिलीज करेंगी, जब उसका कंप्यूटर चलेगा। दुनिया मैन्युअल सिस्टम से कहीं आगे जा चुकी है। इसलिए इंसान डिजिटल लत के चलते दिव्यांग हो गया है। उसकी जान कंप्यूटर में घुसी है। पारंपरिक दुनिया हमसे कितनी पीछे छूट गई है और ई-व्यवस्था हम पर कितनी निर्भर हो गई जिसकी हल्की-सी झलक कुछ घंटों के माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के फेलियर से पता चल गई। ये तय तारीख हमें गंभीरता से सोचने पर विवश करती है। तारीख 19 जुलाई, दिन शुक्रवार समय सुबह 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक समूची दुनिया मानो थम गई। चालू व्यवस्था पर ब्रेक लग गया, पूरा जगत ठहर सा गया। अमेरिका से लेकर भारत तक हजारों विमान बिना उड़े बिना रनवे पर खड़े रहे। इसके अलावा बैंकिंग से लेकर मीडिया, रेलवे, टेलिकास्ट विंग, स्टॉक एक्सचेंज, कॉरपोरेट जगत व विभिन कंपनियों के कामकाज भी ठप हुए। शेयर बाजार एकदम धड़ाम से नीचे गिरा। क्या हिंदुस्तान, क्या अमेरिका, पूरी दुनिया में अफरातफरी का माहौल बन गया। सर्वर की गड़बड़ी की शुरूआती जांच में अमेरिकी एंटी-वायरस को बताया गया। जिसका प्रभाव सबसे पहले एयरलाइंस के संचालनों पर पड़ा, उनका सॉफ्टवेयर अचानक डाउन हो गया। कर्मचारी काफी देर तक अपने सिस्टमों को रिस्टार्ट और ऑन-ऑफ करते रहे, घंटों कोई रिस्पांस नहीं मिला। अमेरिका के अलावा कई देशों में आपात बैठकें बुलाई गईं। हमारी केंद्र सरकार में भी खलबली मची, एयर अथॉरिटी को सफाई देनी पड़ी। पर, स्थिति को जैसे-जैसे काबू में किया गया। कुछ घंटों बाद जब पता चला कि दुनिया का मुख्य क्राउडस्ट्राइक सॉफ्टवेयर ही डाउन हो गया तो सुनकर सभी के होश उड़ गए। आईटी कंपनियों के कार्यालयों में तो भगदड़ जैसे हालात हो गए। आईटी एमएनसी कंपनियां तो टोटली डिजिटल हैं। डिजिटल जंजाल में फंस चुकी दुनिया अब बाहर भी नहीं निकल सकती। क्योंकि दुनिया की आदत हो चुकी है। मैन्युअल कामों से इंसानों ने तौबा कर लिया। मार्डन जमाने में ई-व्यवस्था का नशा मनुष्य के सिर चढ़कर बोल रहा है। सर्वर खराबी के कारण बेशक खोज लिए गए हां, लेकिन करीब 15 घंटे तक दुनिया की सांसे थमी रहीं। क्राउडस्ट्राइक एक अग्रणी साइबर सुरक्षा कंपनी है जो उन्नत खतरे की खुफिया जानकारी और एंडपॉइंट सुरक्षा प्रदान करती है। उनके सॉफ्टवेयर समाधान संगठनों को वास्तविक समय में साइबर खतरों का पता लगाने, रोकने और उनका जवाब देने में मदद करते हैं, जिससे मजबूत सुरक्षा और मन की शांति सुनिश्चित होती है। खुदा न खास्ता अगर ये जाम हो जाए यानी सर्वर डाउन, तो पूरा सिस्टम हैंग हो जाता है, जो उस दिन हुआ। माइक्रोसॉफ्ट के फेलियर से भारत की बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह चरमराई थीं जिससे कंपनियां और आम ग्राहकों को अनगिनत वित्तीय नुकसान हुआ। हालांकि, भारत के निजी बैंक क्राउडस्ट्राइक सिस्टम का प्रयोग नहीं करते? सिर्फ आरबीआई और अन्य 10 बैंकें इसका इस्तेमाल करती हैं। वरना, स्थिति और खराब हो जाती। ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह डिजिटल के गिरफत में है। लोगों के यातायात के साधन अब बैलगाड़ी या सामान्य मोटरवाहन नहीं रहे। संपन्न आबादी समय की बचत को ध्यान में रखकर ज्यादा हवाई आवाजाही करते हैं। गनीमत रही कि सर्वर खराबी के बाद सुबह के शिड्यूल में लगी सभी फ्लाइटें रोकी गईं। एयरलाइंस यात्री एयरपोर्ट में भी नहीं घुस पाए, इसके लिए उन्होंने हंगामा काटा। हंगामा देख एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्रियों को मैन्युअल चेक इन से बोर्डिंग कराई। लेकिन अंदर जाकर भी उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा। विमानन सेवाएं सुबह 10 बजे से ठप रहीं। सर्वर डाउन होने से विमानों को तत्काल प्रभाव से उड़ने से रोका गया। क्योंकि एयरलाइंस सिस्टम पूरी तरह से क्राउडस्ट्राइक साफ्टवेयर पर निर्भर हैं। एयरलाइंस के टिकटों की बुकिंग और चेक इन सर्विस कंप्यूटर आधारित होते हैं। ऐसे में उड़ चुका विमान तो सिर्फ ईश्वर भरोसे ही होता है। ऐसे स्थिति दोबारा भविष्य में न हो, इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट निमार्ताओं को सुनिश्चित करना चाहिए।

लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।

पौधारोपण करें जरूर, निगरानी करना न भूलें

पौधरोपण परियोजनाएं जलवायु परिवर्तन से निपटने और बिगड़े हुए पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए व्यापक रूप से समर्थित रणनीति के रूप में उभरी हैं। हालांकि, उनकी लोकप्रियता और उनके द्वारा उत्पन्न सद्भावना के बावजूद, इन योजनाओं को कई गंभीर मुद्दों का सामना करना पड़ता है जो उनकी प्रभावशीलता को कमजोर करते हैं। पेड़ वातावरण से कार्बन डाई ऑक्साइड को संग्रहीत और हटाकर जैविक कार्बन पृथक्करण में मदद करते हैं। बड़े पैमाने पर पौधरोपण को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण समाधान के रूप में देखा जाता है, जिसमें सरकारें, गैर सरकारी संगठन और व्यक्ति शामिल होते हैं। 1950 में, भारतीय कृषिमंत्री ने वन महोत्सव ('पेड़ों का त्यौहार') कार्यक्रम शुरू किया, जिसे हर साल जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2021-2030 को पारिस्थितिकी तंत्र बहाली का दशक घोषित किया है। 350 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल करना, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में $9 ट्रिलियन का उत्पादन करना और अतिरिक्त 13-26 गीगाटन ग्रीनहाउस गैसों को अलग करना। विभिन्न भारतीय राज्यों में एक दिन में पौधे लगाने के अभियान। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 'एक ट्रिलियन परियोजना'। 'चीन की महान हरित दीवार'। पाकिस्तान की '10 बिलियन ट्री सुनामी'। 'बॉन चैलेंज' 2020 तक 150 मिलियन हेक्टेयर और 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि को बहाल करने के लिए। आकर्षक नारे, आकर्षक अभियान और सुर्खियां बटोरने वाले अभियान मीडिया का ध्यान और सार्वजनिक भागीदारी आकर्षित करते हैं। पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ संयुक्त संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि भारत एकमात्र जी 20 देश है जिसने पेरिस समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा किया है। 2024 के राज्यसभा संबोधन में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री ने घोषणा की है कि भारत ने 1।97 बिलियन टन उड2 समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक हासिल किया है। शहरी वनों को विकसित करने के उद्देश्य से एक पहल। वन प्रबंधन और संरक्षण के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। वन/वृक्ष आवरण को बढ़ाने और पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने पर ध्यान केंद्रित करता है। वन अग्नि की रोकथाम और प्रबंधन को संबोधित करता है। वन भूमि को गैर-वन उपयोगों के लिए मोड़ने के लिए वनीकरण और पुनर्जनन गतिविधियों के लिए धन प्रदान करता है। वनों में कम से कम 10 फीसद छत्र आवरण होना चाहिए, पेड़ों की न्यूनतम ऊंचाई 5 मीटर होनी चाहिए और क्षेत्रफल कम से कम 5 हेक्टेयर होना चाहिए। इस परिभाषा के तहत ऐसे क्षेत्र जहाँ कृषि प्रमुख भूमि उपयोग है, उन्हें वन नहीं माना जाता है। वनों में 10-30 फीसद छत्र आवरण होना चाहिए, पेड़ों की ऊंचाई 2-5 मीटर के बीच होनी चाहिए और क्षेत्रफल कम से कम एक हेक्टेयर होना चाहिए। जलवायु से संबंधित संकटों और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए पौधरोपण एक लोकप्रिय और प्रभावी तरीका है। स्थानीय समुदायों की सीमित भागीदारी। पर्याप्त अनुवर्ती देखभाल और मोनोकल्चर को बढ़ावा देने की कमी। स्थानीय पारिस्थितिक संदर्भों और लोगों की भागीदारी की उपेक्षा। घास के मैदानों और जानवरों के आवासों जैसे कुछ स्थानों पर पेड़ लगाने से पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है, जंगल की आग की तीव्रता बढ़ सकती है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकती है। घास के मैदानों को पेड़ लगाने के लिए वनों की कटाई या क्षरित भूमि नहीं माना जाना चाहिए। ये भूमि अत्यधिक उत्पादक और जैव विविधता वाली हैं, जो पशुधन और लोगों का भरण-पोषण करती हैं। अकेले पौध लगाना हमेशा अन्य तरीकों, जैसे कि पेड़ों के द्वीप (छोटे-छोटे टुकड़ों में पौधे लगाना) की तुलना में लागत-प्रभावी जलवायु समाधान नहीं होता है। भारत के हालिया नीतिगत बदलावों में अंतर्निहित चुनौतियों का समाधान करने के लिए आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। रणनीतियों में पर्याप्त वित्त, सक्रिय सामुदायिक भागीदारी और तकनीकी विचारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अभियान, सोशल मीडिया और प्रोत्साहित सामुदायिक भागीदारी वन पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव लाने में मदद कर सकती है। प्रयासों का उद्देश्य विविध क्षमताओं और क्षमताओं वाले लचीले वन बनाना होना चाहिए। जबकि पौधरोपण पर्यावरण बहाली प्रयासों का एक महत्वपूर्ण घटक है, यह एक अकेला समाधान नहीं है। प्रभावी वन बहाली के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जिसमें सामुदायिक भागीदारी, तकनीकी विशेषज्ञता और निरंतर निगरानी शामिल हो। इन कारकों को संबोधित करके, हम पुनर्वनीकरण पहल की सफलता को बढ़ा सकते हैं और एक अधिक टिकाऊ और लचीली पारिस्थितिकी प्रणाली में योगदान दे सकते हैं। पेड़ों में अपने स्थानीय आवास बदलने की क्षमता रखते हैं। वे नमी के स्तर बढ़ाने का काम करते हैं और वायुमडंल में ऑक्सीजन की मात्रा भी। पुराने पेड़ विशेष तौर पर अहम माने जाते हैं फिर भी वे तेजी से खत्म हो रहे हैं। अध्ययन में इस बात पर जोर दिया गया इस खतरनाक स्थिति के लिए ज्यादा निगरानी की जरूरत है। पुराने जंगलों और उनके पुराने पेड़ों की मैपिंग और निगरानी करने से संरक्षित क्षेत्रों की प्रभावशीलता और संधारणीयता का सीधा आकलन हो सकता है। आज हमें पौधे लगाने के बाद उन्हें बचाने की ज्यादा जरूरत है। सोचना होगा कहीं हम नर्सरी में पल रहे शिशु पौधों की जान तो नहीं ले रहें। पौधरोपण पर्यावरण बहाली प्रयासों का एक महत्वपूर्ण घटक है, यह एक अकेला समाधान नहीं है।

Social Media Corner

सच के हक में...

महान चन्द्रशेखर आजाद की जयंती पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वह एक निडर नायक थे, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए अटूट साहस और प्रतिबद्धता से संपन्न थे। उनके आदर्श और विचार लाखों लोगों, विशेषकर युवाओं के दिल और दिमाग में गूंजते रहते हैं।

(प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'एक्स' पर पोस्ट)

प्रोजेक्ट भवन में विभिन्न विभागों में सहायक नगर निवेशक, कनीय अभियंता, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर, पाइपलाइन इंस्पेक्टर, खान निरीक्षक एवं मोटरयान निरीक्षक हेतु नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुआ। सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार।

(सीएम हेमंत सोरेन का 'एक्स' पर पोस्ट)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुरूआत की जाएगी, जिसके तहत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें उपलब्ध कराई जाएंगी।

(पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी का 'एक्स' पर पोस्ट)

उपभोक्ता हित में है योगी सरकार का आदेश

योगी आदित्यनाथ व उत्तराखंड सरकार के हालिया आदेश कि कांवड़ मार्ग का प्रत्येक दुकानदार अपनी दुकानों पर अपने नाम का बोर्ड लगाये, इस समय काफी बवाल मचाए है। इसे विपक्षी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार का हनन बता रहे हैं। किन्तु प्रश्न है कि संवैधानिक अधिकार किसका बचाया जाए? उन व्यापारियों का, जो छद्म व्यापार में लिप्त हैं, अथवा उन उपभोक्ताओं का, जो इस छद्मता का शिकार बनते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एक उपभोक्ता को ऐसे माल, उत्पाद या सेवाओं से संरक्षित किए जाने का अधिकार देता है जो जीवन और सम्पत्ति के लिए परिसंकटमय हों। साथ ही वह उपभोक्ताओं को क्रय किये जा रहे मालों, उत्पादों या सेवाओं की क्वालिटी, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक और कीमत के विषय में सूचित किए जाने का अधिकार देता है। साथ ही उसे अनुचित व्यापार व्यवहार के विरुद्ध अनुतोष पाने का अधिकार भी देता है। विशेष यह कि यह सभी अधिकार उसे योगी या भाजपा सरकार ने नहीं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के स्थापित होने के समय से ही मिले हुए हैं। किसी माल की क्वालिटी जहां उपभोक्ता को अच्छी क्वालिटी के चयन का अधिकार देती है, वहीं शुद्धता जहां वस्तु में उपलब्ध अवयवों की शुद्धता से ही सम्बन्धित नहीं है, उपभोक्ता के विश्वास की शुद्धता से सम्बन्धित है। इसी विश्वास की शुद्धता का ही दूसरा नाम पवित्रता है। एक कांवड़ यात्री अपने पांथिक विश्वास के अनुरूप लिए गए पवित्र संकल्प व आस्था के कारण ही अपने कांधे पर कांवड़ में गंगाजल लाकर अपने देव महादेव का अभिषेक करता है। इस कांवड़ यात्रा के अपने नियम होते हैं। एक कांवड़िया को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। ऐसे में जबकि उसकी यात्रा की पवित्रता इतनी महत्वपूर्ण होती हो कि कांवड़ या स्वयं कांवड़िया के किसी के छू जाने मात्र से ही खंडित हो जाती हो, वैष्णव, पवित्र, शाकाहारी आदि नाम से चल रहे भोजनालयों में अंडा या मांस का प्रयोग उन्हीं बरतनों में किए जाने, जिनमें उसे भोजन परोसा जाना है, या उसे सामिष भोजन परोसने अथवा भोजन में सामिष भोजन के तत्व डालने से खंडित नहीं होगी, ऐसा विश्वास करनेवाले यह कभी नहीं बताते कि वे इसे किस प्रकार भोजन की वैष्णव पद्धति, पवित्रता या शाकाहार में परिभाषित करेंगे। ऐसे दुकानदारों का यह छलावा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में छद्म विज्ञापन की श्रेणी का मामला भी बनाता है, जो स्वयं अपने आप में आपराधिक कृत्य है। योगी आदित्यनाथ के इस आदेश को पहचान बताने को बाध्य करने वाला आदेश बताने वालों से एक प्रश्न यह भी है कि ऐसी क्या विवशता है, जिसके कारण वे अपनी पहचान छिपाना चाहते हैं? साथ ही क्या इस उचित आदेश पर उनका भड़कना यह सिद्ध नहीं करता कि उनका छद्म नाम से किया जानेवाला यह व्यापार सोदेश्य है तथा यह किसी बड़े षड्यन्त्र का भाग होना भी संभव है। सोशल मीडिया पर प्रायः ऐसे वीडियो आते हैं, जिनमें कोई गटर में सब्जियां व फल साफ करता दिखाया जाता है तो कोई भोजन में थूकता नजर आता है। कई मौलवी इन कृत्यों की यह कहकर वकालत करते भी नजर आते हैं कि यह उनकी पांथिक परम्परा है। खाद्य सुरक्ष अधिनियम-2006 में खाद्य पदार्थ के बेचने वालों को न सिर्फ अपने कारोबार का पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया है, वरन् उन्हें पंजीयन संख्या सहित अनुज्ञप्तिधारी का नाम अपनी दुकान पर इतने बड़े अक्षरों में प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है कि उपभोक्ता उसे आसानी से पढ़ सके तथा विश्वास कर सके कि उसके द्वारा की जानेवाली खरीद खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने वाले पंजीकृत विक्रेता से ही की जा रही है, किसी अमानक, अपंजीकृत या साजिश करनेवाले दुकानदार से नहीं।

कांवड़ और न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने पक्ष-विपक्ष में तर्क सुनने के बाद उस विवादास्पद आदेश पर शुक्रवार तक रोक लगा दी है, जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजनालयों को मालिकों व कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने साफ कर दिया है कि खाद्य विक्रेताओं को मालिक, कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस भी दिया है। तय है, याचिकाकर्ता ने अपनी मजबूत दलीलों से सर्वोच्च न्यायालय से अपने अनुकूल अंतरिम आदेश प्राप्त कर लिया है और अब गेंद इन सरकारों के पाले में है, उन्हें अपने आदेश के बचाव में अकाट्य तर्क के साथ पेश होना पड़ेगा। दुकानों-ठेलों पर मालिक को नाम लिखने के लिए बाध्य करने वाला यह आदेश व्यापक है और इससे समाज में एक बड़े बदलाव की शुरूआत हो सकती है। अतः संविधान की रोशनी में आगे बढ़ना चाहिए। यह अच्छी बात है कि न्यायालय अपने अंतरिम आदेश में भी सतर्क है। न्यायालय की भी यही मर्जी है कि कांवड़ियों (तीर्थयात्रियों) को उनकी प्राथमिकताओं के अनुरूप शाकाहारी भोजन परोसा जाए और स्वच्छता के मानकों को बनाए रखा जाए। न्यायालय को प्रथम दृष्टया भारतीय गणराज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र की चिंता है और याचिकाकर्ता भी इस मोर्चे पर अपनी आशंकाओं का समाधान चाहते हैं। एक तर्क यह भी है कि केवल नाम या पते के प्रदर्शन से शुचिता या पवित्रता बहाल नहीं होगी और न इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति होगी। याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया है कि आप किसी रेस्तरां में व्यंजन सूची के आधार पर जाते हैं, न कि कौन परोस रहा है। यदि किसी दुकानदार का नाम-मजहब स्पष्ट हो जाएगा, तो पहचान के आधार पर बहिष्कार की आशंका है।

Printed and Published by Fahim Akhtar on behalf of MAA MEDIA VENTURE and Printed at SHIVA SAI PUBLICATION PVT.LTD, Ratu, Kathitand, Near Tender Bagicha, H.P. Petrol Pump P.O.+P.S.- Ratu, Dist.-Ranchi, 835222, Jharkhand And Published at Roshpa Tower, 5th Floor, Main Road, Ranchi, Jharkhand-834001. R.N.I Number - JHABIL/2022/85899, Editor- Fahim Akhtar. Mob - 9431311669, E-mail : thephotonnewsjharkhand@gmail.com

ICJ, Knesset and the rules-based order

Two significant developments within the space of less than 24 hours have brought much-needed clarity on the vexed issue of Israel's ongoing occupation of Palestinian territories.In response to a request from the UN General Assembly for an advisory opinion on the subject, the 15-judge Bench of the International Court of Justice (ICJ) in The Hague began deliberations in January 2023. As many as 57 countries submitted their opinions on the case, which is distinct from the one on South Africa's submission that Israel is committing genocide in the Gaza Strip.

Treating the West Bank, East Jerusalem and the Gaza Strip as a contiguous territory, the court provided a stunning, unequivocal opinion on Friday (July 19). It ruled that Israel's presence in the Occupied Palestinian Territories is illegal; that Israel must end its unlawful presence as rapidly as possible; that it must cease immediately all new settlement activities and evacuate all settlers; that Israel has the obligation to make reparations for the damage caused by the occupation; and that all states/nations, the UN and international organisations have an obligation to recognise the occupation as illegal.Israel, led by President Isaac Herzog and Prime Minister Benjamin Netanyahu, has predictably lashed out at the judgment, but its usual efforts to describe any criticism as anti-Semitism would stand on tenuous ground. Key elements of the opinion were passed by a majority of 14 to 1. Uganda's Judge Julia Sebutinde was the solitary voice in opposition, while the majority opinion included judges from the US, Japan, Germany, Brazil, Australia, China, Mexico, South Africa and Justice Dalveer Bhandari from India.In a perverse way, the resolution passed by the Knesset just a day earlier (July 18) also brings an end to the ambiguity and obfuscation that have characterised Israel's position on the Occupied Territories since the Six-Day War in June 1967. Sixty-eight members supported the resolution opposing the establishment of a Palestinian state and describing it as "an existential threat to the State of Israel and its citizens", while only the nine Arab members of Knesset opposed it. Others, including centre-left groups and Labour, chose to sit out rather than stand up and be counted in opposition to the resolution.The tenor of the Knesset resolution, at one level, reflects the marked hardening of public opinion in Israel following the brutal massacre by the Hamas on October 7, 2023, that left some 1,100 Israelis dead. But it also comes at a time when Israel's horrific war on Gaza has left close to 40,000 Palestinians dead and some 90,000 wounded. In the context of the ICJ ruling, it poses a serious challenge to the international community and especially to the US and others which invoke international law and a rules-based order at the drop of a hat.The obfuscation about the Occupied Territories began in 1967 itself, when British diplomats started drafting UN Security Council Resolution 242 that was eventually adopted in November that year. It called for the "withdrawal of Israeli armed forces from territories occupied in the recent conflict". Or was it the territories? Didn't it mean all of the occupied territories, barring minor reciprocal adjustments to cater to considerations of demographics and territorial contiguity? English and French were the only two working languages of the Security Council and the French version was unambiguous. "Retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés lors du récent conflit," it said in its reference to "the occupied territories".There was no ambiguity in the mind of the Indian representative at the UNSC, who said that the UNSCR 242 would commit Israel to "total withdrawal of Israel forces from all the territories — I repeat, all the territories — occupied by Israel as a result of the conflict which began on June 5, 1967".

The Oslo Accords of 1993 and 1995, signed between Yasser Arafat and then Israeli PM Yitzhak Rabin, led to the establishment of the Palestine Authority, initially with limited self-rule over the West Bank and Gaza and the promise of a transition to full statehood within a five-year period. Oslo II divided the West Bank into three zones: Zone A (18 per cent of the area) under full Palestinian civil and security control; Zone B (22 per cent) under Palestinian civil control and joint security control; and Zone C (60 per cent) under full civilian and security control of Israel.

Holistic outlook a must for successful energy transition

India plans to achieve net-zero carbon emissions by 2070. This is challenging, though its current annual per capita emissions are only one-third of the global average.

Energy transition has become a buzzword among energy planners around the world. And rightly so, as the alarm bells are ringing loud and clear about the urgent need to reduce greenhouse gas (GHG) emissions from energy-related activities. Some recent reports contain ample evidence of how GHG emissions emanating from burning fossil fuels are leading to devastating climate change impacts. These include record-breaking heatwaves, extreme rainfall events, droughts, an accelerated rise of the sea level, ocean warming and a dramatic decline in ice sheets. Therefore, combating these adverse effects is now a priority for governments worldwide.India is committed to achieving net-zero carbon emissions by 2070. This is a challenging task, though the country's current annual per capita emissions are only one-third of the global average. This is because energy consumption is increasing at a rapid pace, triggered by economic growth and the government's commitment to meeting the aspirations of the public. This can lead to a rise in GHG emissions. Energy usage varies across different sectors. Various organisations have been working towards sector-specific road maps. Are we following a holistic approach in these studies? And how well are the different sector blueprints coordinated? An introspection of the approach we are following would be desirable at this juncture.

Let us take the example of the power sector, which is the highest emitter of carbon dioxide. A key component of the country's strategy for achieving net-zero emissions has been the use of renewable energy (RE) in all productive activities while cutting down on the use of fossil fuels. The road maps have also tried to work out the type and quantum of energy storage systems like batteries and pumped storage hydropower plants required to manage the variability and intermittency of RE sources like the sun and wind. Of late, the road maps have been looking at the use of green hydrogen derived from renewable sources. Expanding nuclear power generation utilising the country's rich thorium reserves is yet another supply-side option being considered as a source, which can provide reliable baseload power and help the integration of RE into the grid. It is, however, noted that the main objective of most studies has been to maximise the use of RE while achieving a demand-supply balance at a minimal cost.It is necessary to lay greater emphasis on demand-side factors in the ongoing studies, particularly when considering longer time frames, such as 2050 and 2070. These factors play a crucial role in the energy transition. As we are aware, grid-level demand growth and patterns are dynamic, particularly in the context of aggressive demand-side management measures, the growth of distributed energy resources, electric vehicle usage in G2V and V2G modes, fuel substitution in end-use sectors, and other initiatives that impact energy consumption and greenhouse gas emissions. Exploiting demand-side flexibility through tariff-linked regulatory measures and demand response programmes would also need to be evaluated as options for minimising the transition costs. A scenario-based approach considering different feasible demand-side options could be a solution in this regard.Furthermore, the requirement for grid infrastructure is a critical aspect that could significantly influence energy transition action plans. It would impact both the overall system cost and supply reliability, necessitating a detailed power system stability analysis. A pragmatic study is also required on the constraints of Right of Way issues in building the infrastructure, as this could impact the transition target dates.

Yet another key objective of any action plan would be to look at how the transition would influence the lives of the people. It is widely recognised that a people-centric approach is crucial for the smooth implementation of net-zero pathways. Therefore, road maps for net-zero emissions should strive to incorporate findings from ongoing studies on 'just transition'.'Net zero' means balancing the amount of greenhouse gases released with the same amount stored or offset so that the temperature has no effect at all. This underscores the need to consider carbon capture and storage technologies, planting trees, restoring forests, and other biological options that can absorb the carbon dioxide released into the atmosphere as part of the overall strategy to control temperature changes.It is also debatable whether we are taking a narrow view by focusing primarily on the power sector, while the majority of energy use occurs in industrial heating and cooling processes. According to the International Renewable Energy Agency, "heating and cooling consume approximately half of the world's final energy, making it the largest energy end-use sector, surpassing both electricity (20 per cent) and transport (30 per cent). This sector is also responsible for over 40 per cent of global energy-related carbon dioxide emissions." Net-zero reports must adopt a holistic approach, considering the decarbonisation opportunities within the heating and cooling demands of each sector.

A successful energy transition necessitates a comprehensive approach encompassing supply-side measures, demand-side management, grid modernisation, energy security and a just transition for the affected communities. The transition must extend beyond the power sector to include decarbonisation of the heating, cooling and transportation sectors. There is an urgent need to develop a framework for such integrated studies.

Bail under UAPA

SC relief for undertrials languishing in jails

IN a landmark decision, the Supreme Court has granted bail to a person who was booked under the Unlawful Activities Prevention Act (UAPA), 1967, and was languishing in jail for nine years due to the slow pace of the wheels of justice. The ruling reiterates the judicial principle that "bail, not jail, is the basic rule". It comes as a relief in a legal landscape where the reluctance to grant bail has led to prolonged incarceration and significant human rights concerns. The higher judiciary has been grappling with an overwhelming number of bail applications, highlighting a troubling trend of reluctance at lower judicial levels to grant bail. Prolonged detention often infringes on the personal liberties of the accused, even as their trials progress at a snail's pace.Several recent cases exemplify the shift towards upholding personal liberty through the granting of bail in stringent cases. In 2021, the Delhi High Court granted bail to student activists Natasha Narwal, Devangana Kalita and Asif Iqbal Tanha, all accused under UAPA in connection with the 2020 Delhi riots. The court criticised the misuse of anti-terror laws to stifle dissent.

The SC decision clarifies that no statute, including UAPA, inherently precludes the granting of bail. This distinction is crucial as it reinforces that legal principles must not be overshadowed by rigid interpretations that compromise individual freedoms. The matter of bail should not be complicated or politically charged. It is a straightforward judicial procedure intended to balance the rights of the accused with the interests of justice. However, the continued denial of bail has disproportionately affected ordinary citizens, especially the poor, who languish in jail awaiting trial. This decision marks a step towards rectifying the imbalance and ensuring that justice is not only done but seen to have been done.

From Kargil to Jammu, a saga of intel lapses

Successive governments have chosen not to initiate much-needed intelligence reforms.

Kargil Vijay Diwas will be celebrated on July 26 to honour the memory of the 527 bravehearts who lost their lives in Operation Vijay. And this year is special, since it marks the 25th anniversary of that brief but bloody war. An audacious and stealthy operation by the Pakistan army that was conceived by then army chief Gen Pervez Musharraf was foiled and the intruders pushed back — but at a heavy cost. On July 26, 1999, the Kargil War came to a formal end.

An emotive national recall is on the cards, and it is appropriate that families who lost their loved ones and soldiers grievously injured are acknowledged and comforted in an empathetic and appropriate manner. It is an unfortunate tenet of history since time immemorial that those who pay the heaviest price on the battlefield are soon forgotten. But deeply embedded and glossed-over institutional omissions of that war merit scrutiny.

This author dwelt on some aspects of the Kargil War last fortnight (July 8), but certain developments compel this revisit. Gen NC Vij (retd), who was the DGMO (Director General, Military Operations) during that war and later served as the Army Chief, has made significant observations in his soon-to-be-released book, Alone in the Ring, about the Kargil intelligence fiasco. However, it is reported that the book is now 'on hold', awaiting government clearance, and this is a poor reflection on how the narrative and history of the war is being shaped. Another development pertains to allegations made by a former Major about command failure.

In excerpts published in the media, Gen Vij notes that the Pakistan army had the element of surprise in the early stages and that India was caught unawares due to an intelligence failure. He adds: "Not only was the intrusion detected late, but also our intelligence agencies were unable to assess if the intrusion was by militants or the Pakistan army." This observation is not a new revelation; much the same had been said in the preliminary reviews and assessment of the Kargil intrusion.However, it draws attention to an abiding and tenacious structural inadequacy in India's higher defence management — that of intelligence-gathering and effective assessment. This entails a continuous, multi-layered activity of seeking and collating disparate information inputs, analysing them and then distilling that which is relevant into actionable operational inputs during a war or similar challenges to national security and integrity.

India's track record in this domain has been below par. From the October 1962 border war with China to Kargil (1999), Mumbai terror attacks (2008), Galwan clash (2020) and, most recently, the terror attacks in the Jammu region, systemic intelligence failures are a recurring feature. External intel inputs are provided by R&AW (Research and Analysis Wing), and the dominant Kargil narrative is that actionable inputs were not provided to the Indian military in a timely manner.In the Kargil case, Gen Vij writes: "The assessment of R&AW was categorically that 'there was no possibility of a war with Pakistan in the current year'. This inaccurate assessment resulted in a strategic failure."As is the case in any post-event review, there is a different appreciation of the Kargil fiasco by other actors and the intelligence community has argued over the years that specific intel inputs were provided to the Army well in advance and that it was the inability of the fauj to acknowledge and assess the inputs that led to the setback.An alternative narrative that challenges the current received wisdom (the Gen Vij version) was highlighted in an unhappy development. In early July, a junior Army officer on active duty in Kargil served a legal notice on Gen VP Malik (retd), who was the Army Chief during the war. Major Manish Bhatnagar, Company Commander (5 Para) during the war, was court-martialled and dismissed from service in 2001. While he was deemed to be guilty of "acts prejudicial to good order and military discipline", the more serious charge was that he did not obey orders to carry out an attack. This charge, however, could not be proved during the court martial, but he was still dismissed from service by citing another transgression.The immediate trigger for the legal notice against Gen Malik was a statement given on TV, where the former Chief asserted that a lack of intelligence inputs and surveillance gaps led to the Kargil intrusions. Bhatnagar challenged this assertion by claiming that he had reported the Pakistani intrusions well before they were discovered in May 1999 and added that his warnings had been ignored by his superiors in the chain of command.This is a jarring intrusion in the run-up to the 25th anniversary of Kargil Vijay Diwas but it draws attention to the institutional inadequacy in the Army's intel domain. First-person accounts by those who had served in Kargil at that time support the Bhatnagar contention that the Army at the brigade level had received these inputs of intrusions, but the enormity of the occupation of the peaks in the Indian territory, the identity of the intruders (Pakistan army soldiers) and the firepower they had amassed were a huge surprise when it was revealed.Twenty-five years after the war, the intelligence reforms that had been mooted by the Kargil Review Committee remain dormant. It is instructive that successive governments — led by Vajpayee, Manmohan Singh and Modi — have chosen not to touch this matter and initiate the much-needed reforms.In a pithy comment, BB Nandy, a doyen of the Indian intel community, warned in 2004 that an overhaul of the 'Intelligence Leviathan' would be arduous and that the default position of successive governments was to perpetuate "a tradition of bungling". His lament — who will bell the cat? — still falls on deaf ears.Hopefully, the book by Gen Vij will be in the public domain soon and other inputs regarding glossed-over omissions of the Kargil War will encourage the Modi government to embark on the much-needed intelligence domain reforms and deliberate on the matter in Parliament. Concurrently, the Army ought to carry out its own internal review in the light of recent disclosures and accept the onus for command lapses, if these are established.

There should not be a repeat of Kargil in any form, wherein the supreme sacrifice of young officers and soldiers redeemed the failures of their superiors.

Budget proposes interest subsidy scheme to facilitate loans for urban housing segment

NEW DELHI. The government on Tuesday proposed a central assistance of Rs 2.2 lakh crore for urban housing over the next five years as well as an interest subsidy scheme to facilitate loans at affordable rates for urban housing works.The announcements were made by Finance Minister Nirmala Sitharaman in the Union Budget 2024-25.She also said the government will put in place measures for an efficient and transparent rental housing market with enhanced availability.

Among others, the minister has proposed transit-oriented development plans for large cities having a population of over 30 lakh and a scheme to support the development of 100 weekly haats in five years.

Also, the government will develop digital public infra applications in seven areas, including those related to credit and MSME service delivery.

Budget 2024: Govt announces loans up to Rs 10 lakh for higher education in domestic institutions

NEW DELHI: The government will provide financial support for loans up to Rs 10 lakh for higher education in domestic institutions, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman announced on Tuesday.

Presenting the budget for 2024-25, she said e-vouchers for this purpose will be given directly to one lakh students every year with interest subvention of 3 per cent of the loan amount.Upgrading 1,000 Industrial Training Institutes (ITIs) in the hub and spoke model, aligning course content with the skill needs of industry and revision of model skill loan scheme, are among the measures announced by the Finance Minister for the Skill Development sector."For helping our youth who have not been eligible for any benefit under govt schemes and policies government will provide financial support for loans up to Rs 10 lakh for higher education in domestic institutions. E-vouchers for this purpose will be given directly to one lakh students every year with interest subvention of 3 per cent of the loan amount," Sitharaman said.The Union Budget for 2024-25 will provide Rs 1.48 lakh crore for education, employment and skilling in the country.

She said, "1,000 ITIs will be upgraded in a hub and spoke model, course content and design will be aligned to the skill needs of industry and new courses will be introduced for emerging needs. I am happy to announce a new centrally sponsored scheme for skill development in which 20 lakh youth will be skilled over a period of 5 years".

"The model skill loan scheme will be revised to facilitate loans up to RS 7.5 lakh with a guarantee from government promoted fund..this measure is expected to help 25,000 students every year," she added.

Gold, silver prices fall by up to Rs 4,000 after budget cuts custom duty

NEW DELHI. Finance Minister Nirmala Sitharaman announced a substantial reduction in the customs duty on gold and silver while pressenting the Budget on Tuesday.This cut has led to a sharp decline in prices, benefiting consumers and boosting demand in the market. However, broader market conditions and geopolitical tensions could influence future trends.

The Finance Minister has reduced the import duty on gold and silver from 15% to 6%. This includes a decrease in the Basic Customs Duty (BCD) from 10% to 5% and the Agricultural Infrastructure Development Cess (AIDC) from 5% to 1%. Hareesh V, Head of Commodities at Geojit Financial Services, said, "The reduction in customs duty from 15% to 6% may lead to lower domestic prices and potentially increase demand. Previously, the duty consisted of 10% BCD and 5% AIDC."

'In their trademark style': Jairam Ramesh accuses FM of borrowing internship program from Cong's Nyay Patra

NEW DELHI. The Congress on Tuesday said that finance minister Nirmala Sitharaman has drawn inspiration from its 2024 Lok Sabha manifesto by announcing an internship program in the Union Budget of 2024-25.

This program aims to offer internship opportunities to 1 crore youth in 500 top companies over five years. However, Congress argued that the scheme is designed to "grab headlines with arbitrary targets."Congress general secretary in-charge of communications, Jairam Ramesh, claimed that the internship initiative is modeled after the Congress's proposed Apprenticeship Program, named Pehli Naukri Pakki, which was detailed in their 2024 Lok Sabha manifesto."The finance minister has taken a leaf out of the INC's Nyay Patra 2024, with its internship program clearly modelled on the INC's proposed Apprenticeship Program that was called Pehli Naukri Pakki," Ramesh said.He further criticized the scheme's design, stating, "However, in their trademark style, the scheme has been designed to grab headlines, with arbitrary targets (1 crore internships) rather than a programmatic guarantee for all diploma holders and graduates, like the Indian National Congress had envisioned."Ramesh also highlighted the government's shift in acknowledging unemployment as a critical issue after years of neglect. He remarked, "It's far too late, and as it turns out, far too little - the Budget speech is more focused on posturing than action."Regarding job creation, Ramesh commented, "After ten years of denial -- where neither the non-biological PM nor his party's Lok Sabha Elections Manifesto would even mention jobs -- the Union Government seems to have finally come around to tacitly admitting that mass unemployment is a national crisis that requires urgent attention.

What is 'Angel tax' that was scrapped in Budget 2024

Earlier this year, in the interim budget presented in February, the government proposed extending tax incentives for startups and investments backed by sovereign wealth or pension funds until March 2025.

NEW DELHI. Finnace Minister Nirmala Sitharman on Tuesday scrapped the angel tax in a bid to strengthen the startup ecosystem and to support innovation in the country.

"Government abolishes Angel tax for all classes of investors in startups," said the finance minister, highlighting the government's commitment to supporting new businesses.Earlier this year, in the interim budget presented in February, the government proposed extending tax incentives for startups and investments backed by sovereign wealth or pension funds until March 2025. This step was intended to give more time for these investments to benefit from tax relief. The angel tax, formally known as Section 56(2)(viib) of the Income Tax Act (ITA), was introduced in 2012. It targeted investments made by unlisted companies through the issuance of shares. This tax was imposed on any premium paid by investors above the fair market value of the shares, classifying it as "income from other sources" and subjecting it to taxation.The Finance Act of 2012 added this provision to the ITA to address concerns related to money laundering and the flow of unaccounted funds. However, it became a point of contention among startups and investors, who felt it was a barrier to innovation and fundraising.

Key issues with the angel tax included its impact on the valuation of shares, the treatment of estimated figures in the discounted cash flow (DCF) method, and scrutiny of funding sources and investor credibility. The retrospective application of the tax and its effect on the conversion of convertible instruments into equity were also points of dispute.

According to Rahul Charkha, Partner at Economic Laws Practice, the removal of this tax is a significant move towards providing clarity and avoiding unintended negative consequences on foreign investments.

"This decision is a welcome step towards providing tax certainty, preventing unintended consequences on foreign investments, and supporting startups," Charkha noted.Despite the removal of the tax, there remains a need to fully understand the implications of this change. Ankur Mittal, Co-founder of Inflection Point Ventures, remarked that while the full details of the abolition need to be reviewed, it is expected to bring much-needed regulatory clarity.

"This action has the ability to bring a lot of regulatory clarity, which is generally appreciated by the investor communities across the world. This should help founders looking to raise capital both in domestic and international markets," Mittal said.

The scrapping of the angel tax is seen as a positive development for the startup community, which has long advocated for a more supportive and less restrictive environment for fundraising.

With this change, the government aims to create a more favourable atmosphere for innovation and investment in India.

Budget 2024: Nuclear energy will form crucial part of Viksit Bharat's energy mix: Finance Minister

The R&D funding announced in the interim budget will be made available for this sector.

NEW DELHI. Nuclear energy is expected to form a crucial part of the energy mix of Viksit Bharat, the government said on Tuesday, and added that it will partner with private firms to develop small and modular nuclear reactors and conduct research on newer technologies.

The R&D funding announced in the interim budget will be made available for this sector also, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said during her Budget speech.

"Nuclear energy is expected to form a very significant part of the energy mix of Viksit Bharat," she said."Towards that pursuit, our government will partner with private firms for setting up of Bharat Small Reactors, conduct research and development on Bharat Small Modular Reactor and newer technologies for nuclear energy," the Finance Minister added.

Budget 2024: Changes will be made to IBC to strengthen tribunals: Finance Minister

The Finance Minister also proposed an integrated technology platform for improving outcomes under the Code, besides additional debt recovery tribunals to be set up in the country.

NEW DELHI. Finance Minister Nirmala Sitharaman on Tuesday said appropriate changes will be made to the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) and steps will be taken to strengthen tribunals in the country.

She also proposed an integrated technology platform for improving outcomes under the Code, besides additional debt recovery tribunals to be set up in the country.While presenting the Union Budget for 2024-25, she proposed the development of digital public infra application for productivity gains, business opportunities and innovation by the private sector.

She informed that the IBC has resolved more than 1,000 cases, which has resulted in a realisation of Rs 3.3 lakh crore to creditors.Defaults worth Rs 10.2 lakh crore have been settled at the stage of pre-admission of insolvency cases since the inception of IBC in 2016, and more than one-fifth of the companies undergoing the resolution process are from the real estate space, the Economic Survey said on Monday.Since FY18, the IBC has enabled over Rs 3 lakh crore recovery for banks, which was much more than what lenders recovered through previous mechanisms of Lok Adalats, DRTs, and the SARFAESI Act, it said.Since the implementation of IBC in 2016, a total of 31,394 corporate debtor cases "involving a value of Rs 13.9 lakh crore" have been disposed of (including pre-admission case disposals) as of March 2024.

Budget 2024: Markets show high volatility amid Union Budget Presentation

MUMBAI. Stock markets turned highly volatile amid the Union Budget presentation on Tuesday.The 30-share BSE Sensex jumped as soon as Finance Minister Nirmala Sitharaman began presenting the Budget for 2024-25. However, within minutes, it slipped into the red and later traded flat, down 38.17 points at 80,457.02 at 11:41 hrs.

The NSE Nifty also ticked higher as the Finance Minister began the presentation of her seventh Union Budget in the Lok Sabha. However, volatile trends soon emerged, and the benchmark traded 18.25 points lower at 24,491. The BSE benchmark had climbed 264.33 points to 80,766.41 in early trade, while the Nifty went up 73.3 points to 24,582.55.

This is the first Budget during Prime Minister Narendra Modi-led government's third term in office. "India's economic growth continues to shine while the global economy is still in the grip of policy uncertainty," Sitharaman said. She

noted that the country's inflation continues to be stable and is moving towards 4 percent, with core inflation standing at 3.1 percent.

Among the Sensex pack, Power Grid, Reliance Industries, Bajaj Finance, JSW Steel, Bharti Airtel, and Bajaj Finserv were the major laggards. In contrast, ITC, Hindustan Unilever, Adani Ports, and UltraTech Cement were among the biggest gainers.

Foreign Institutional Investors (FIIs) bought equities worth Rs 3,444.06 crore on Monday, according to exchange data.In Asian markets, Seoul and Tokyo traded higher, while Shanghai and Hong Kong quoted lower. The US markets ended in positive territory on Monday. Global oil benchmark Brent crude traded marginally lower by 0.07 percent to USD 82.34 a barrel.Falling for the second day in a row, the BSE benchmark fell 102.57 points or 0.13 percent to settle at 80,502.08 on Monday. The NSE Nifty dipped 21.65 points or 0.09 percent to 24,509.25.

Budget 2024: Top 8 numbers from FM Nirmala Sitharaman's speech you shouldn't miss watching out for

NEW DELHI. Finance Minister Nirmala Sitharaman will deliver her seventh consecutive Budget on Tuesday, outlining a plan for India's development by 2047 and showcasing the government's performance over the past decade. The market anticipates potential tax relief for the middle class, leaving more disposable income in their hands, given the current tax buoyancy.

Additionally, there are expectations for the government to adhere to the fiscal consolidation path, aiming to reduce the fiscal deficit to 4.5% of GDP by 2025-26, says a PTI report.

Here are the key numbers to watch out for the first full Budget of Modi 3.0:

1. Nominal GDP: India's nominal GDP growth (real GDP plus inflation) in the current fiscal year is estimated to be 10.5% to Rs 327.7 trillion as per the Interim Budget. In view of expected normal monsoon, improvement in revenue collections and pick up in rural consumption, it is expected that there could be upward revision in growth estimate. Real GDP growth in current fiscal is projected at 7.2%, as per the RBI.

Also Check | Budget 2024 Live Updates: Record capex for rail, roads & income tax relief likely from FM Nirmala Sitharaman's Union Budget

2. Tax Revenue: The Interim Budget had pegged gross tax revenue at Rs 38.31 lakh crore for 2024-25, an 11.46% growth over the last fiscal. This includes Rs 21.99 lakh crore estimated to come from direct taxes (personal income tax + corporate tax), and Rs 16.22 lakh crore from indirect taxes (customs + excise duty + GST)3. Fiscal Deficit: The budgeted fiscal deficit, which is the difference between the government expenditure and income, for the current fiscal is 5.1% as projected in the Interim Budget in February, against 5.8% in the last fiscal year. The full Budget is expected to provide better-than-earlier projections as there has been tax buoyancy. The government has projected a fiscal deficit at 4.5% of the GDP in FY264.4. Capital Expenditure: The government's planned capital expenditure for this fiscal year is budgeted at Rs 11.1 lakh crore, higher than Rs 9.5 lakh crore in the last fiscal year. The government has been pushing infrastructure creation and also incentivising states to step up capex.

Also Check | Income Tax Slabs 2024-25 Budget 2024 Live Updates: New income tax regime tweaks, standard deduction hike and income tax relief on the cards?

5. GST: Goods and Services Tax (GST) collection in 2024-25 is estimated to rise to Rs 10.68 lakh crore, an increase of 11.6 per cent. The tax revenue figures will have to be watched out for in the final Budget for the 2024-25 fiscal year.
6. Borrowing: The government's gross borrowing Budget was Rs 14.13 lakh crore in the current financial year as per the Interim Budget. The government borrows from the market to fund its fiscal deficit. The borrowing number will be watched by the market, especially on the back of more-than-expected dividend from the RBI and financial institutions.
7. Dividend: The interim Budget had projected Rs 1.02 lakh crore from RBI and financial institutions. This will be revised upwards as the RBI has already made surplus transfer of Rs 2.11 lakh crore earlier in May. At the same time, Rs 43,000 crore expected to be garnered from CPSEs.8. The Budget will also focus on expenditure for key schemes like NREGA and crucial sectors such as health and education.

Sitharaman, who has been presenting the Budget since 2019, had replaced the traditional leather briefcase with a 'bahi-khata' wrapped in red cloth in her first Budget. This year's Budget will be paperless, as it has been for the past three years.

The NEET Question That Supreme Court Asked IIT To Solve, And What They Answered

The Supreme Court had asked the Director of the Indian Institute of Technology, Delhi to set up a team of three experts to go into the particular question of Physics asked in NEET-UG 2024.

New Delhi: The Supreme Court on Monday asked the Director of the Indian Institute of Technology, Delhi to set up a team of three experts to go into the particular question of Physics asked in the medical entrance exam, National Eligibility-cum-Entrance Test-Undergraduate (NEET-UG 2024), the results of which were released last month and have been marred by leaked questions and the award of 'grace marks', or preferntial marking.

A bench comprisin Chief Justice DY Chandrachud and Justice JB Pardiwala was hearing a clutch of pleas, including those that are seeking a re-test of the controversy-ridden NEET-UG and asked the IIT-Delhi to submit a report o the correct answer by Tuesday noon.The three experts confirmed there was only one correct answer to the question and that the answer was the same as provided in the answer key issued by the National Testing Agency (NTA), the exam body that conducts NEET.How Controversy Over Question In NEET-UG Began The controversy started after the claims that question number 29 in the May 5 NEET-UG had two possible correct answers.

The petitioner in the Supreme Court argued that the ambiguity had significant implications for the exam results. At least 44 students, who chose the alternative answer, received "grace marks" and achieved a perfect score of 720/720.However, the petitioner chose not to answer the question and scored 711/720.The petitioner said she didn't answer the question because it had two possible correct answers, and she didn't want to risk losing marks due to negative marking. She said it was logical to assume that only one answer could be correct.Lawyers pointed out that the ambiguous question affected students in three ways. Some students answered correctly but got minus five marks. Others chose a different correct answer and got four marks. The third group consisted of those who skipped the question for fear of getting negative marks.This situation could significantly impact the merit list, the Supreme Court was told, as per PTI.

The NEET-UG Question In "Question"

Here's the NEET-UG question in "question":

Given below are two statements:Statement I: Atoms are electrically neutral as they contain an equal number of positive and negative charges.Statement II: Atoms of each element

are stable and emit their characteristic spectrum.

The Answer

Chief Justice Chandrachud reported that the expert panel from IIT-Delhi reviewed the question thoroughly and concluded that "option four" was the correct answer, which states: "Statement I is correct but Statement II is incorrect."Naveen Gaur, an Associate Professor from Delhi University, also supported the IIT panel's finding, stating that option four was the only correct answer.The top court then asked the NTA why they gave marks for both answers, to which the exam body said both were "possible answers".The petitioner disagreed, saying te two options can't be correct. She pointed out that the old textbook supports one answer, while the new textbook supports the other.

The NTA said students were expected to follow the new textbook, which makes one of the options the correct answer. Despite this, over 4.2 lakh students chose the other option and got extra marks.The NEET-UG is conducted by the NTA for admissions to MBBS, BDS, AYUSH and other related courses in government and private institutions across the country. More than 23.33 lakh students took the test this year, which was conducted at 4,750 centres in 571 cities, including 14 overseas.

Woman uses forged documents to travel to Pakistan, case filed

New Delhi:A 23-year-old woman in Maharashtra is in legal trouble for allegedly travelling to Pakistan with a fake passport and visa.The woman, identified as Nagma Noor Maksood Ali alias Sanam Khan from Thane, allegedly changed her name and got Aadhaar card, PAN card and her daughter's birth certificate from Lokmanya Nagar in Thane, as per a report by news agency PTI.She then submitted these forged

documents with the passport application, police said, adding that she got a fake passport based on the documents.The woman managed to obtain a passport on the basis of the forged document and travelled to Pakistan.The incident took place between May 2023 and May this year.

A case has now been filed against the woman. The police have also booked an unidentified man in connection with the case.Both of them were booked under the Indian Passports Act and further investigation is on, police said.

Government Expands Financial Support For Flood Mitigation, Irrigation Projects

New Delhi: Finance Minister Nirmala Sitharaman on Tuesday announced a comprehensive financial support plan of 11,500 crore to enhance flood control measures and irrigation projects across several states.

Presenting the Budget in the Lok Sabha, Sitharaman highlighted that the government, through the Accelerated Irrigation Benefit Program and other sources, will provide financial support for various projects.These projects include the Kosi-Mechi intra-state link and 20 other ongoing schemes, encompassing barrages, river pollution abatement, and irrigation projects. Additionally, survey and investigation of Kosi-related flood mitigation and irrigation will be undertaken.

Bihar has frequently suffered from floods, many of them originating outside the country. Plans to build flood control structures in Nepal are yet to progress,"

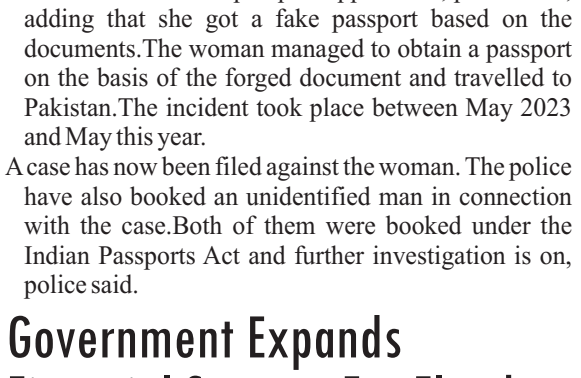

Sitharaman said.Assam, which grapples with annual floods caused by the Brahmaputra and its tributaries originating outside India, will also receive assistance for flood management and related projects, she said.

"We will provide assistance to Assam for flood management and related projects," Sitharaman said.

Highlighting the extensive losses suffered by Himachal Pradesh last year, Sitharaman said, "Our government will provide assistance for reconstruction and rehabilitation through multilateral development assistance." Similar support was promised to Uttarakhand, which faced significant losses due to cloudbursts and massive landslides.Recently, Sikkim witnessed devastating floods that wreaked havoc across the state.The Finance Minister added that the government will extend its assistance to Sikkim as well.

Budget 2024: Nirmala Sitharaman Announces 1,000 Crore For Space Tech

New Delhi: Riding high on the success of the Chandrayaan-3 mission, Finance Minister Nirmala Sitharaman on Tuesday announced a fund of ? 1,000 crore to encourage space technology development.

The announcement came in her Union Budget 2024 speech in the Parliament and is expected to assist more than 180 government-recognized space technology startups in India."With our continued emphasis on expanding the space economy by five times in the next 10 years, a venture capital fund of ? 1,000 crore will be set up," she said.

The announcement came after the Economic Survey 2023-24, tabled in Parliament by Ms Sitharaman on Monday, said the space sector, over the last few years, had seen remarkable progress in the buildup of rockets, satellites and spacecraft used for space exploration, and ground

infrastructure."Presently, India has 55 active space assets which include 18 communication satellites, nine navigation satellites, five scientific satellites, three Meteorological Satellites, and 20 Earth Observation satellites," the survey said.It also said the New Space India Limited (NSIL) has successfully executed its contract to launch 72 satellites of OneWeb to Low Earth Orbit through LVM3, M2 and M3 missions, establishing LVM3 as a reliable Launch Vehicle in the global commercial launch services market.The Economic Survey 2023-24 said the Indian National Space Promotion and Authorisation Centre (IN-SPACe) -- a single window agency to promote and authorise space activities -- has received 440 applications as on January 1, from more than 300 Indian entities pertaining to authorisation, handholding, facility support and consultancy, technology transfer, and facility usage.

"Budget 2024 Based On PM Modi's Mantra Sabka Saath Sabka Vikas": Pankaj Chaudhary

New Delhi: Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary said that the first Union Budget of the third Modi government will be based on his mantra of "Sabka Saath Sabka Vikas." Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the full budget for 2024-25 on Tuesday."This budget is based on PM Modi's mantra of Sabka Saath Sabka Vikas," MoS Chaudhary said.haudhary was among the first members of FM Nirmala Sitharaman's team to reach the North Block offices of the Finance Ministry ahead of the budget presentation. Vivek Joshi, Secretary of the Department of Financial Services, and Chief Economic Advisor V. Anantha Nageswaran have also reached the ministry ahead of FM Sitharaman.

Minister Sitharaman is set to present the Union Budget 2024 in Parliament today, marking her seventh consecutive budget and eclipsing the late Moraji Desai's record of six consecutive budgets, which is likely to focus on changes in the income tax structure and improving the ease of doing business in India. Sitharaman tabled the Economic Survey 2023-24 along with the statistical appendix on Monday.itharaman will lay on the table a statement (in English and Hindi) of the estimated receipts and expenditures of the government for the year 2024-25 in the Rajya Sabha.She will table the budget one hour after the conclusion of the presentation of the Union Budget 2024-25 in the Lok Sabha.

The Finance Minister also laid on the table, under subsection (1) of Section 3 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003, a copy each (in English and Hindi) of the following papers: medium-term fiscal policy strategy statement and macro-economic framework statement. The Finance Minister will further lay on the table statements (in English and Hindi) of the estimated receipts and expenditures (2024-25) of the Union Territory of Jammu and Kashmir (with the legislature).With this upcoming budget presentation, Finance Minister Nirmala Sitharaman will surpass the record set by former Prime Minister Morarji Desai, who presented five annual budgets and one interim budget between 1959 and 1964 as finance minister. The budget session of Parliament began on July 22 and, according to schedule, will end on August 12.

Delhi Police Implements Extensive Safety And Security Measures In View Of Kanwar Yatra

New Delhi: With the commencement of the Kanwar Yatra, the Delhi Police has implemented extensive safety and security measures to ensure a smooth pilgrimage.Detailing the preparedness, DCP North East Delhi Joy Tirkey said, "We have issued Do's and Don'ts for the Kanwar Shivirs, arranged firefighting equipment, and set up first aid facilities and Ganga Jal. Around 1,100 personnel have been deployed," he stated.All the preparations have been made for the Kanwar Yatra...Safety and security measures have been taken...CCTV cameras will be installed and several other measures have been taken," he said while speaking to ANI.

Earlier, Delhi Police issued a traffic advisory regarding the arrangements for the Kanwar Yatra.The advisory informed that this year the expected number of Kanwariyas is about 15-20 lakhs.

"The holy expedition called Kanwar Yatra commences on the first day of Sawan (Shravan), i.e., July 22, 2024. It culminates on the Chaturdashi Tithi, i.e., August 2, 2024, as holy Ganga water will be offered to Lord Shiva. A large number of Kanwariyas reach Delhi, and some of them go to Haryana and Rajasthan via Delhi borders. This year, the expected number is about 15-20 lakhs," it said.The general public and motorists are advised to keep patience, observe traffic rules and road discipline and follow directions of traffic personnel deployed at all intersections, it stated.Devotees across the nation began their Kanwar Yatra on July 22, on the occasion of the first Monday of 'Sawan'.Many devotees thronged emples dedicated to Lord Shiva to offer their prayers and also took a holy dip in the Ganga to mark the first Monday of'Sawan'.

Devotees flock to temples, including the Mahakaleshwar temple in Ujjain, the Kashi Vishwanath temple in Varanasi, the Kali Paltan temple in Meerut, and the Jharkhandi Mahadev Temple in Gorakhpur, to offer their prayers.Haridwar saw an influx of pilgrims, prompting enhanced security arrangements. The area has been divided into 14 superzones, 35 zones, and 132 sectors for better management.

This sacred month, typicallyfalling between July and August, marks a period of worship, fasting, and pilgrimage dedicated to the deity of destruction and transformation.Sawan holds a special place in Hindu mythology as the month when Lord Shiva is believed to have consumed the poison that emerged from the churning of the ocean (Samudra Manthan), saving the universe from its toxic effects.Devotees undertake fasting and offer prayers to seek the blessings of Lord Shiva during this period.

Shraddha Walkar Case: Aftab Poonawal's Plea For Trial Only Twice A Month Rejected

Special Fast Track Court Judge Manish Khurana Kakkar dismissed the plea of the accused, Poonawala.

New Delhi: Saket District Court has recently rejected Shraddha Walkar's murder case and accused Aftab Amin Poonawala's plea seeking trial to be held only twice every month to give suitable time to his counsel to prepare his defence. The court said that the accused was trying to deliberately delay the trial.Special Fast Track Court Judge Manish Khurana Kakkar dismissed the plea of the accused, Poonawala."It appears that since substantial witnesses have been examined and material witnesses are yet to be examined after filing the supplementary challan along with the witnesses cited in the main charge sheet, the accused is trying to deliberately delay the trial," the Special Court said in an order of July 6.In fact, learned defence counsel had failed to appear on dates that were fixed as per his convenience for cross-examination of the witnesses, and several witnesses are yet to be cross examined by the accused, it added.It also said that only 134 out of 212 prosecution witnesses have been examined since June 2023. Therefore, consecutive dates are required to conclude the trial expeditiously.There is an application which was moved by Vikas Walkar, father of Shraddha Walkar, seeking release of her bones so that her last rites may be performed."Moreover, the right of the accused to a fair trial cannot be allowed to completely trump the right of the victim to a dignified

cremation as well as the right of the surviving heir of the deceased to cremate the body of the deceased with dignity and respect," the court observed.The court noted that, admittedly, the bones of the deceased have not been released to the father of the deceased/victim, who has been appearing diligently physically or through virtual mode. He has specifically prayed that the bones of his only daughter be released to him expeditiously as soon as possible since he has to cremate her body parts."Infact, the said right cannot be allowed to be completely thwarted by slackening the pace of trial at the whims and fancy of the accused, who has been adequately accommodated on each date of hearing so as to give him ample opportunity to prepare his defence as well as to cross-examine the witnesses," the court emphasised.The court said that the father of the deceased has also filed an application for release of the bones and for expeditiously exhibiting them.In reply to the application filed, the accused stated that he has no objection to release of the bones to the father of deceased, as the alleged bones and body parts have already been exhibited.

NEWS BOX

Trump shooting: Secret Service chief refuses to resign amid calls to step down

Washington. US Secret Service Director Kimberly Cheatle rebuffed bipartisan calls to resign for security failures that allowed a would-be assassin to wound Republican presidential candidate Donald Trump, and rankled lawmakers by refusing to provide details about the incident.The US House of Representatives Oversight Committee's Republican chair, James Comer, and top Democrat, Jamie Raskin -- normally bitterly divided on most issues -- each called on Cheatle to step down.

"This committee is not known for its model of bipartisanship, and I think today we came together unanimously in our disappointment," Comer told Cheatle. "We don't have that confidence that you can lead."Raskin said Cheatle had "lost the confidence of Congress at a very urgent and tender moment in the history of the country, and we very quickly need to move beyond this".During more than 4-1/2 hours of often contentious proceedings, Cheatle called the July 13 shooting "the most significant operational failure at the Secret Service in decades", comparing the breakdown to the 1981 attempted assassination of former President Ronald Reagan.But she repeatedly rebuffed calls to step down, saying at one point: "I think that I am the best person to lead the Secret Service at this time".

Monday's hearing marked the first round of congressional oversight of the attempted assassination at an outdoor campaign rally in Butler, Pennsylvania.Trump was wounded in the ear, one rally attendee was killed and another injured. The suspected shooter, 20-year-old nursing home aide Thomas Crooks, was killed by law enforcement. It is not clear what his motive was for the shooting.On Wednesday, FBI Director Christopher Wray will appear before the House Judiciary Committee. House Speaker Mike Johnson is also due to unveil a bipartisan task force to serve as a nexus point for House investigations.In the face of Republican claims that the Secret Service denied resources to protect Trump, Cheatle said security for the former president had grown ahead of the shooting."The level of security provided for the former president increased well before the campaign and has been steadily increasing as threats evolve", Cheatle said.She added that the Secret Service provided the security sought by the Trump campaign for the rally.

50 dead in Ethiopia due to landslides triggered by heavy rain

Addis Ababa. At least 50 bodies were pulled from the mud on Monday following two landslides in southern Ethiopia, a local official said."There was a heavy rain yesterday night and some people died from a landslide," said Kassahun Abayneh, the government spokesperson for Gofa district in the South Ethiopia regional state.

"In the (Monday) morning, locals, including police, gathered at the site to save those who were affected by the first landslide. That is when the second landslide happened around 10:00 a.m. (0700 GMT) today and

those who gathered there died."Meskir Mitku, the district general administrator of Gofa district in the Southern Ethiopia region, said women, children and local police were among the dead, the Ethiopian Broadcasting Corporation (EBC) reported.

Photographs on Facebook shared by EBC showed scores of people on a blank hillside searching for victims.

Bosses resign at Japan firm probing deaths linked to tablets meant to lower cholesterol

TOKYO. The chairman and president of a major Japanese dietary supplement maker announced their resignation on Tuesday, as the company probes 80 deaths potentially linked to tablets meant to lower cholesterol.Kobayashi Pharmaceutical is at the centre of a health scare linked to its over-the-counter tablets containing red yeast rice, which is fermented with a mould culture.Medical studies say red yeast rice or "beni koji" can improve cholesterol levels but also warn of a risk of organ damage depending on the ingredient's chemical make-up.A company statement said president Akihiro Kobayashi and chairman Kazumasa Kobayashi were leaving their posts. Both men belong to the firm's founding family.The decision was made "to clarify executive responsibility over a series of actions by our company related to the 'beni koji' issue", Kobayashi Pharmaceutical said.Red yeast rice has been used in food, alcoholic drinks and folk medicine for centuries around East Asia.The scandal erupted in March when the company, a household name in Japan, recalled three brands of dietary supplements after customers complained of kidney problems.It later said it had detected a potentially toxic acid produced by the mould at one of its factories, and the government inspected the firm's facilities.Last month, the company said it was probing a total of 80 deaths possibly connected to its pills, and investigating whether organs other than kidneys were harmed.But at the time the government called Kobayashi Pharmaceutical's delay in reporting the number of cases under investigation "extremely regrettable".On Tuesday, the company's board of directors said in a separate statement that they "pray for the souls of those who died... and offer condolences to the bereaved families".The company's new president is Satoshi Yamane, previously head of sustainability policy, the company said.Outgoing president Akihiro Kobayashi, who has expressed his intention to take responsibility for any harm caused, will remain in an executive role to manage compensation-related matters, it added.Kobayashi's red yeast rice supplements are regulated under a system created in 2015 under former premier Shinzo Abe.Some watchdogs have reportedly expressed concerns that the regulation of these products is not sufficiently stringent and that they do not always have the advertised effects.

Bangladesh PM Sheikh Hasina blames opposition for job quota violence

Dhaka. Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina blamed her political opponents for deadly violence that swept the country during recent student-led protests against quotas in government jobs, stating on Monday that a curfew would be lifted when the situation improved.Her comments came a day after the South Asian country's top court agreed to scrap most quotas in a ruling on Sunday, following days of clashes between protesters and security forces that prompted the government to shut down internet services, impose a curfew and deploy the army.Hospital data showed at least 147 people were killed in one of the worst outbreaks of violence in recent years.Hasina, 76, won a fourth-straight term in power in January in a national election boycotted by the main opposition party."When arson terrorism started, the protesting students said they were not involved in it", Hasina said in an address to business leaders in the capital Dhaka, her first comments since her government ordered a curfew late on Friday."We were forced to impose a curfew to protect the lives and property of the citizens. I never wanted it", she said. "We will lift the curfew whenever the situation gets better".Hasina blamed the main pposition Bangladesh Nationalist Party and the Jamaat-e-Islami party and its student wing for the violence that started last week.The parties did not immediately respond to requests for comment but critics, including the BNP, have previously accused Hasina of authoritarianism, human rights violations and crackdowns on free speech and dissent - charges her government denies.The streets appeared calm in Dhaka on Monday, a day after the Supreme Court ruled in favour of an appeal from the government against a lower court order and directed that 93% of government jobs should be open to candidates on merit.The ruling scaled down quotas in state jobs previously reserved for groups including families of freedom fighters, women and so-called disadvantaged groups, cutting it to 7 per cent from 56 per cent.Experts have blamed the unrest on stagnant job growth

in the private sector and high rates of youth unemployment that have made government jobs, with their regular wage hikes and other privileges, more attractive.

'48-HOUR ULTIMATUM'

Late on Sunday, protesters gave the government 48 hours to meet a string of new demands, but most appeared to be obeying the curfew on Monday in cities that had seen regular demonstrations after a high court in June reinstated the old quotas.Thousands were injured in protests that turned violent last week, as security forces fired tear gas, rubber bullets and sound grenades to scatter the demonstrators.Tanks were seen stationed at several places in Dhaka on Monday, while armed security patrols directed the few motorists who ventured out. There were no reports of violence in the country, officials said.The new demands from protesters included a public apology from Hasina for the violence, restoration of internet connections and reopening of campuses.

The Anti-Discrimination Student Movement also called for the resignation of some ministers and university officials and the dismissal of police officers deployed in the areas where students were killed.We are giving an ultimatum to the government to fulfil our eight-point demand within 48 hours", one of the Movement's leaders, Hasnat Abdullah, told reporters.He did not say what would happen if the government did not meet the demands. The government did not immediately comment.Dhaka police said they had arrested 516 people for involvement in "destructive attacks.

Kamala Harris wins enough delegates to become Democratic presidential nominee

World. US Vice President Kamala Harris has won the support of enough Democratic delegates to win the party's nomination for president, a report with CNN suggested.Harris has so far been backed by more than the 1,976 pledged delegates she requires to win the nomination on the first ballot.Harris became the party's presumed nominee after President Joe Biden withdrew from his reeelction campaign on Sunday, following weeks of party acrimony and internal polls showed his support collapsing in a battle against Republican rival Donald Trump.She secured the nomination on Monday night (US local time), less than 36 hours after Biden endorsed her.

In an X post, Harris said, "Tonight, I am proud to have earned the support needed to become our party's nominee.

Over the next few months, I'll be traveling across the country talking to Americans about everything on the line.""I fully intend to unite our party and our nation, and defeat Donald Trump," Harris said.A statement from her, upon becoming the presumptive democratic nominee for President, was also posted on her X account.These endorsements are not binding, and with President Joe Biden out of the race, delegates are free to vote for the candidate of their choice, CNN reported.On Tuesday, Harris will campaign in the critical battleground state of Wisconsin for the first time as a presidential candidate.

The Wisconsin trip offers another opportunity for the 59-year-old former California prosecutor to reset the Democrats' campaign and make the case that she is best positioned to beat Trump.Harris is scheduled to deliver remarks at a political event in Milwaukee at 1.05 pm CDT (1805 GMT).She offered a sense of how she plans to attack Trump on Monday, referring to her past of pursuing "predators" and "fraudsters" as San Francisco district attorney and California attorney general.

Elon Musk says his son is 'dead', 'killed by woke mind virus'

World Elon Musk, during an interview, has revealed one of his sons was "figuratively dead" after the Tesla and SpaceX CEO was tricked into giving consent for his child to go on puberty blockers.

During the conversation, Musk also said he vowed to destroy the virus."It happened to one of my older boys, where I was essentially tricked into signing documents for one of my older boys, Xavier," Musk told Jordan Peterson."This is before I had any understanding of what was going on. Covid-19 was going on, so there was a lot of confusion and I was told Xavier might commit suicide if he doesn't," the billionaire said."That was a lie right from the outset," Peterson responded."Incredibly evil, and I agree with you that the people that have been promoting this should go to prison," Musk said.

The Tesla CEO added it wasn't explained to him that puberty blockers are "actually just sterilisation drugs" when he gave his consent for his son to undergo the treatment."I lost my son, essentially. They call it deadnaming for a reason," Musk said.

"The reason it's called deadnaming is because your

son is dead. My son Xavier is dead, killed by the woke mind virus."After an extended pause, Musk added, "I vowed to destroy the woke mind virus after that."Musk's revelation came after he asked about his thoughts on doctors performing sex change procedures on children, a practice both Musk and Peterson described as "evil."According to a report with the Daily Mail, Xavier got his name changed to Vivian Musk, after he came out as transgender in June 2022."I no longer want to be related to my biological father in any way, shape or form," Vivian said at the time, according to the report.

Phillipines orders ban on Chinese-run online gambling outfits

Manila. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. on Monday ordered an immediate ban on widespread and mostly Chinese-run online gaming operations, accusing them of venturing into crimes, including financial scams, human trafficking, torture, kidnappings and murder.His move to ban the Chinese-run online gambling outfits — estimated to number more than 400 across the Philippines and employing tens of thousands of Chinese and Southeast Asian nationals— came amid a crackdown backed by Beijing.That has led to the shutdown of several sprawling complexes where authorities suspect thousands of Chinese, Vietnamese and other nationals mostly from Southeast Asia have been illegally recruited and forced to work in dismal conditions.Marcos announced the decision during his state-of-the-nation address, when he also said that the Philippines would press efforts to strengthen its defensive capability by forging security alliances with friendly countries to counter threats to its territorial interests in the South China Sea, adding that his country would only settle disputes through diplomacy.The Philippines has a

complicated relationship with China, including significant trade engagements and cooperation against crime. But they have also had longstanding disputes in the South China Sea.Relatedly, Philippine senators ordered the arrest of a town mayor in Tarlac province north of Manila who has failed to appear at public hearings where allegations against her were being investigated, including her alleged links to a large online gambling complex near her townhall and suspicions that she fraudulently hid her Chinese nationality to be able to run for a public office reserved only for Filipinos.The mayor, Alice Guo, has denied any wrongdoing but has been suspended from her post with her financial assets ordered frozen. Philippine senators say the massive online gambling industry has flourished largely due to corruption in regulatory agencies and payoffs to local officials."Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder," Marcos said in his address. "The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop."Marcos ordered the gaming agency to wind down the operations of the gambling outfits by year's end, drawing loud applause in the House of Representatives. He asked labor officials to look for alternative jobs for Filipino workers who would be displaced because of the shutdown.

Setting out his vision for the year ahead, Marcos outlined moves to address a range of issues, including soaring costs of food and electricity, poverty and low wages.His administration's "bloodless war" on dangerous drugs never aimed at "extermination," Marcos said in an obvious criticism of his predecessor's brutal anti-drugs crackdown that left thousands of mostly innocent suspects killed.

Israel sends tanks back into Gaza's Khan Younis after evacuation order, 70 dead

Gaza medics said that the Palestinians were killed by tank salvoes in the town of Bani Suhaila and other towns fringing the eastern side of Khan Younis, with the area also bombarded from the air.

UPDATED.: Israel sent tanks back into the greater Khan Younis area after ordering evacuations of some districts it said had been used for renewed attacks by militants and at least 70 Palestinians were killed by Israeli fire, Gaza medics said on Monday.The Palestinians were killed by tank salvoes in the town of Bani Suhaila and other towns fringing the eastern side of Khan Younis, with the area also bombarded from the air, they said.Residents of the densely built-up area of southern Gaza said the tanks advanced for more than two kilometres (1.2 miles) into Bani Suhaila, forcing residents to flee under fire."It is like doomsday", one resident, who only identified himself as Abu Khaled, told Reuters via chat app. "People are fleeing under fire, many are dead and wounded on the roads".The Gaza health ministry said the dead included several women and children and that at least 200 other people had been wounded. The Gaza ministry does not distinguish between militants and civilians in its death tallies.The Israeli military said in a statement evacuation orders to the population in eastern Khan Younis resulted from intelligence information indicating militants were firing rockets from those areas and Hamas was attempting to regroup."Since this morning, the IAF and IDF artillery forces have struck more than 30 terror infrastructure sites in Khan Younis, including in the area from which a projectile was launched toward Nirim in southern Israel earlier today", the military said.Around 400,000 people were living in the targeted areas and dozens of families had begun to leave their houses, Palestinian officials said, adding they were not given time to get out of harm's way before the Israeli strikes began.

Some families fled on donkey carts, others on foot, carrying mattresses and other belongings.The Palestinian Red Crescent Society said two of its clinics located in

eastern Khan Younis had been knocked out of operation because of the new offensive.At Khan Younis' Nasser Hospital, some people stood outside the morgue to bid farewell to dead relatives.

"We are tired, we are tired in Gaza, every day our children are martyred, every day, every moment", said Ahmed Sammour, who lost several relatives in bombings of eastern Khan Younis."No one told us to evacuate. They brought four floors crashing down on civilians", Sammour added.In nearby Deir Al-Balah, where hundreds of thousands of Palestinians are sheltering, an Israeli airstrike hit a tent used by local journalists inside Al-Aqsa Hospital, killing one of them and wounding two other people, the Hamas-run Gaza government media office said.The new death raised the number of Palestinian journalists killed in the Israeli offensive to 163, it added.

EVACUATION ORDERS

Earlier on Monday, the Israeli military said it had issued new evacuation orders due to renewed Palestinian militant attacks, including rockets launched from the targeted areas in eastern Khan Younis. The orders did not include health institutions, Palestinians said.The military said it was adjusting the boundaries of a designated humanitarian zone in coastal Al-Mawasi - to the west of Khan Younis - to keep the civilian population away from areas of combat with Hamas-led Palestinian militants.The Gaza Civil Emergency Services said Israel's new orders showed it had downsized the humanitarian-designated areas in southern and central areas, where 1.7 million people were sheltering, to 48 sq km (18.5 sq miles) from 65 sq km (25 sq miles) in the past.The Palestinians, the United Nations and international relief agencies have said there is no safe place left in Gaza.Health officials at Nasser Hospital in Khan Younis urged residents on Monday to donate blood because of the large number of casualties being rushed to the medical centre.

NEWS BOX

SL vs IND: Charith Asalanka named new captain as Sri Lanka announce T20I squad

New Delhi. Sri Lanka announced a 16-member squad to take on Suryakumar Yadav-led India in a three-match T20I series from July 27 to 30 in Pallekele. As expected, Sri Lanka named middle-order batter Chairth Asalanka as their captain for the series. Asalanka takes over from Wanindu Hasaranga, who quit the role after Sri Lanka's early exit from the T20 World Cup in June in the USA and the West Indies.Much like Sri Lanka, India also appointed a new T20I captain Suryakumar Yadav after Rohit Sharma retired from T20I cricket following the World Cup triumph. While Gautam Gambhir has travelled with the senior national team as its new head coach, Sanath Jayasuriya has been appointed as Sri Lanka's interim head coach for the upcoming series.Sri Lanka have named a power-packed unit, which has a good mix of experience and youth.

SRi LANKA T20I SQUAD FOR INDIA SERIESCharith Asalanka – Captain, Pathum Nissanka, Kusal Janith Perera, Avishka Fernando, Kusal Mendis, Dinesh Chandimal, Kamindu Mendis, Dasun Shanaka, Wanindu Hasaranga, Dunith Wellalage, Maheesh Theekshana, Chamindu Wickramasinghe, Matheesha Pathirana, Nuwan Thushara, Dushmantha Chameera, Binura Fernando.Former captain Wanindu Hasaranga will still remain an integral part of the side, which will be coached by Jayasuriya. Hasaranga picked 15 wickets in the recently concluded Lanka Premier League season.

Saw him hug the cup and cry: Ashwin on Rahul Dravid's T20 World Cup celebration

New Delhi R Ashwin recounts the heartfelt moment when former Indian coach Rahul Dravid hugged the ICC T20 World Cup trophy and cried after clinching India's first major ICC title in 11 years. This touching scene marked the end of Dravid's coaching stint as he led the Men in Blue to their first major ICC trophy in 11 years with a narrow seven-run victory over South Africa on June 29. Dravid, a legendary cricketer who never clinched a significant ICC World Cup title as a player or captain, finally found redemption in his last assignment as head coach.Later in July, former Indian opener Gautam Gambhir was announced as Dravid's successor, ready to start his era on the white-ball tour to Sri Lanka from July 27 onwards. Ashwin paid tribute to Dravid's success despite the criticism and setbacks he faced in his career as a player and a coach, such as the 2007 50-over World Cup first-round exit. Ashwin acknowledged Dravid's impact on the team over the last few years, noting how he had changed its approach."My moment was when Virat Kohli called Rahul Dravid and gave him the cup. I saw him hug the cup and cry. Rahul Dravid screamed and cried. I saw him enjoy it. I felt that a lot. I want to talk about a person who is sacred. In 2007, during the 50-over World Cup, India got knocked out. Rahul Dravid was the captain at that time. He didn't captain the one-day side after that. He has been with the Indian team. If something doesn't go well, if the Indian team goes out or loses a match, immediately, they ask what Rahul Dravid is doing," Ashwin said on his YouTube channel.Ashwin emphasized Dravid's meticulous planning and unwavering commitment, noting, "I know what he has been doing with this team for the past 2-3 years. I know how balanced he has been.

Top overseas athletes to watch out for - Sun Yingsha

New Delhi Sun Yingsha, a prominent Chinese table tennis player, is known for her exceptional skills and achievements in the sport. Born on November 4, 2000, in Shijiazhuang, Hebei province, China, she has rapidly risen through the ranks to become one of the top table tennis players in the world. Starting the sport at a young age, Sun quickly showed great promise and joined the Chinese national team, competing in international tournaments. Her breakout moment came in 2017 when she won the Japan Open, defeating some of the world's top players, marking her as a rising star in the table tennis world.Sun Yingsha's career is decorated with numerous accolades. Her journey to the top has been nothing short of meteoric. With lightning-fast reflexes, powerful strokes, and an uncanny ability to read her opponents, Sun Yingsha has quickly established herself as a formidable force. Her aggressive playing style, coupled with her exceptional technique, has made her a nightmare for opponents. She has consistently performed well in major international competitions, including the Olympics, World Championships, ITTF World Tour events, and the Asian Games. Some of her notable achievements include:

YINGSHA's DECORATED CAREER

1. World Championships: Sun has won multiple medals at the World Table Tennis Championships, including gold in women's doubles and mixed doubles events.2. ITTF World Tour: She has secured numerous titles on the ITTF World Tour, demonstrating her dominance in both singles and doubles categories.3. Olympic Games: At the Tokyo 2020 Olympics, Sun Yingsha won a silver medal in the women's singles event and contributed to China's gold medal victory in the women's team event.

YINGSHA EYES GOLD IN PARIS

Sun Yingsha is known for her aggressive playing style and quick reflexes. Her forehand and backhand strokes are powerful and precise, allowing her to dominate rallies and put pressure on her opponents.

Debutant Athletes to watch out for in Paris Olympics 2024: HS Prannoy

HS Prannoy, a prominent Indian badminton player, is set to make his debut at the Paris Olympics despite facing significant health challenges. His journey highlights his resilience and determination, making him a key player to watch.

New Delhi. Star Indian badminton player, HS Prannoy, despite battling a chronic stomach disorder, a persistent back injury, and a recent viral illness, remains resolute ahead of his much-awaited Olympic debut. At 32, Prannoy is focused on building his stamina for the grind that awaits him in Paris later this month, with the support of his coach and former player RMV Gurusaidutt. The 32-year-old Kerala shuttler, a 2022 Thomas Cup title winner and a world and Asian Games bronze medallist has battled past a chronic stomach disorder, a nagging back injury, and most recently, a week-long bout of the mosquito-borne viral disease.2023 was a dream year for Prannoy in his long career, with the Kerala shuttler winning bronze medals at both the World Championships and the Asian Games. Prannoy also reached multiple finals on the BWF World Tour, winning the Malaysia Masters and achieving a career-high world ranking of No. 6.

However, Prannoy's performances have declined this year due to a health issue. The 31-year-old has suffered from constant nausea for the last four months, caused by a malfunctioning muscle lining the esophagus, leading to food regurgitation and vomiting. This condition is similar to the acid reflux he experienced in 2018-19, which he eventually managed to resolve. The health issues also led to a weight loss of five kilograms and had a psychological impact on him. Prannoy currently holds a win-loss record of 10-14, with eight early-round exits in 10 individual tournaments and no finals appearances this year.Speaking about his upcoming Olympic debut, Prannoy expressed his desire to approach the games with a simple and normal mindset, without succumbing to unnecessary pressure. With his best ranking of No. 6 in the BWF World Rankings, Prannoy is an athlete to watch out for in the badminton competition at the Paris Olympics. Preparing for Paris, Prannoy has received substantial support, including over Rs. 1.8 crore from the TOPS and ACTC schemes, covering various training and recovery expenses. This support extends to his coach Rohan Mathews' participation in key international events and the Olympics.

Awarded the Arjuna Award in 2022, and his persistence and skill have established him as a leading figure in Indian badminton. Prannoy has been drawn alongside Le Duo Phat of Vietnam and Fabian Roth of Germany in Group K. Prannoy, who has been in good form, is favourite to reach the Round of 16 from the group. Ranked No. 13 in the world, Prannoy's true potential far exceeds his ranking, with the ability to compete against the top athletes globally. Prannoy's exceptional stamina and ability to play long rallies sets him apart from the rest. If he can manage his injury, Prannoy could be a real force to deal with.

Kevin De Bruyne staying at Manchester City: Pep Guardiola dismisses Saudi rumours

New Delhi Manchester City manager Pep Guardiola has dismissed rumors linking Kevin De Bruyne with a move away from the club amidst speculation about a potential transfer to Saudi Arabia. De Bruyne, whose contract extends until 2025, mentioned last month that he is open to the idea of a move, but Guardiola believes there will be no major changes to the squad before the transfer window closes on August 30. "Kevin is not going," Guardiola stated during a press conference at North Carolina State University on Monday, ahead of their opening US tour match against Celtic. There had been considerable speculation that City might sell De Bruyne, cashing in on the Saudi offer due to the 33-year-old entering the final year of his contract. Replacing De Bruyne would be an almost impossible task, and while it may be inevitable in the future, Guardiola is confident it won't be an issue this summer."I am delighted with the squad for many years.

I don't know what will happen in the market; if someone leaves, we will talk about that. But 85-95% of the squad will remain the same. We've made an impact in the market over the years, and every situation is different. I feel comfortable because the quality we have in the squad is difficult to replace," Guardiola explained. City recently signed 20-year-old Brazilian winger Savinho, and Guardiola confirmed that Kalvin Phillips,

who was on loan to West Ham United, has been training with the first team."Savinho can play on the wing, and when he is one-on-one, he is devastating," Guardiola added. "He is young, and bringing in one or two players to keep things fresh is necessary, but we cannot change six or seven players. It is impossible and unsustainable. Many players want to come here, but we didn't get agreements from the clubs, and when they ask for a very high price, we don't do it."Manchester City will begin their Premier League title defense at Chelsea on August 18.

Paris Olympics: Satwiksairaj poses with 'beast' Rafael Nadal at Games Village

New Delhi India's top shuttler Satwiksairaj Rankireddy had his fanboy moment on his first day at the Olympic Games Village in Paris. The 23-year-old met and greeted tennis legend Rafael Nadal and shared the moment on social media. Satwik was chuffed to meet the great, who was in Spain's training kit, on Monday, July 22.Satwiksairaj Rankireddy wrote in his caption that he was 'with the beast' as the two athletes were all smiles while posing for the photograph. Satwiksairaj was donning the official Indian kit after arriving in Paris earlier in the day. The Indian shuttler also shared a photo of himself with his doubles partner Chirag Shetty and top-ranked men's singles shuttler HS Prannoy from the Games Village.While athletes are focused and under pressure to deliver at the biggest sporting spectacle, the Games Village offers budding stars an opportunity to brush shoulders with some of the legends of the game. Notably, Satwiksairaj, ahead of his maiden Olympics in Tokyo, had shared a photo of him alongside Novak Djokovic.Satwiksairaj Rankireddy and Chirag Shetty were relaxed on Day 1 of their stint at the Games Village. The doubles duo, ranked No. 3 in the world, is one of India's biggest medal hope at the Paris Olympics. Having won a historic Asian Games gold medal in men's doubles last year in Jakarta, Satwik and Chirag are well-placed to win a medal for India in badminton.No Indian man has won a medal in badminton at the Olympics. Saina Nehwal's London Olympics bronze and PV Sindhu's silver in Rio and bronze in Tokyo are the only three medals. Satwik and Chirag have an opportunity to script history.

Satwiksairaj Rankireddy and Chirag Shetty, who are seeded third, will face the World No. 6 pairing of Fajar Alfian and Muhammad Rian Ardianto of Indonesia. Having drawn in Group C, the star shuttles will also have matches against the world No. 31 German combination of Mark Lamsfuss and Marvin Seidel and world No. 43 Lucas Corvee and Ronan Labar of France in the group.Satwik and Chirag are one of the four seeded pairs along with top seeds Lian Wei Keng-Wang Chang (1) of China, Kang Ming Hyuk and Seo Seung Jae (4) of Korea and Astrup and Rasmussen of Denmark (2).

On the other hand, Rafael Nadal will be keen on making it count in what will be probably his last Olympics campaign. The Spaniard will team up with Carlos Alcaraz in men's doubles.

Paris Olympics: Lebron James inspires USA to win vs Germany in final warm-up game

New Delhi LeBron James once again showcased his legendary prowess, leading the US men's basketball team to a hard-fought 92-88 victory against World Cup champion Germany before the Paris Olympics. The game, held in London on Monday night, served as the final warm-up before the Olympic Games commence later this week. James, who was announced earlier in the day as the male flagbearer for the U.S. in Friday night's opening ceremony along the River Seine, delivered an electrifying performance. He scored the final 11 points for the Americans, securing their win in the tense closing moments. This feat mirrored his previous clutch play, where his decisive layup against South Sudan secured a 101-100 win.

"It was a good test for us. And I'm glad we were able to once again, you know, keep our composure, persevere like we did the other day versus South Sudan," James said. "It was a good win for us." James finished the game with 20 points, supported by Joel Embiid's 15 points, Stephen Curry's 13, and Anthony Edwards' 11. For Germany, Franz Wagner led with 18 points, while Andreas Obst, Dennis

Schroder, Daniel Theis, and Moritz Wagner contributed significantly. The victory marked the end of a challenging exhibition slate for the U.S., who finished 5-0 despite several close calls. Canada, Australia, South Sudan, and Germany all tested the Americans, but each time they managed to persevere, largely thanks to James' leadership.As the Paris Games approach, the U.S. team, buoyed by their recent performances, is prepared to take on the world. "We've had every experience," Curry said. "Now it's obviously a matter of showing up when the lights are bright next week. I think we're ready. I think we're prepared. Now we have to perform." Despite the win, the U.S. team faced challenges, particularly from beyond the arc. Germany outscored them 39-18 from 3-point range, a trend that also appeared in their game against South Sudan. Additionally, turnovers proved costly, with the U.S. committing 14 to Germany's seven.

Paris Olympics 2024: Athlete influencers compete for likes as well as medals

Paris. Athletes on the hunt for Olympic gold will also be chasing likes and follows on social media in Paris, as a battle for a coveted piece of viral fame kicks off at the Games. A social media side hustle unlike any other will play out across a frantic 16 days beginning on July 26 with Olympians looking to exploit a narrow window to connect with fans from the Games on platforms like YouTube, Tik Tok and Instagram.American rugby player Ilona Maher went viral at the Tokyo Olympics and now boasts more than a million followers on Tik Tok, despite her sport having less traction than others in the United States.Her teammate Ariana Ramsey wants to follow a similar path in Paris, hoping the four videos she will be producing each day will build her online persona and help with her ambition to one day start her own athletic apparel brand."It is so much pressure because there's only so much you can really plan for," she told Reuters.

Paris Olympics 2024: Full Coverage

"I can make a list of content ideas and try and execute them there, but it's going to be more of a matter of like what is going on in the time? What can I capture? What's relevant?"Like many other Olympians who work second or even third jobs, Ramsey has used social media to supplement her income, earning one-off deals with brands and charging about $100 for an Instagram Reel or $50 for an Instagram story post.

In years past, athletes like Ramsey might have needed a manager to negotiate deals with brands. Now, a company will reach out directly to strike a deal."This is a whole second job," said Ramsey, who also competed in Tokyo.Athletes do not have to be among the top echelons of fame to gain traction online, Kate Johnson, Google's global marketing director, sports, entertainment, and content partnerships, told Reuters."You don't have to have a big name.

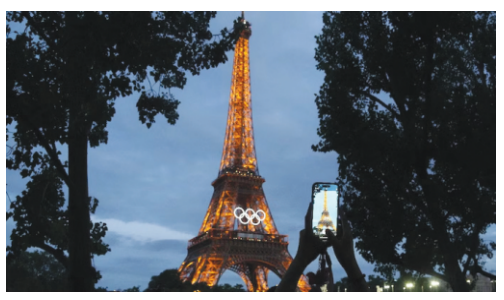

You have something unique to tell and to share that brands want access to," she said.The Women's Sports Foundation trustee won silver as a rower in 2004 and sees extraordinary new opportunities for athletes rapidly unfolding since she stepped onto the Olympic podium in Athens.YouTube, which is owned by Google's Alphabet Inc., counted 1 billion unique monthly visitors in 2013. That number roughly doubled by 2022."I feel like I have to do a public service announcement for Olympic athletes who have been in the zone, competing, focusing, training and haven't necessarily been paying attention to how to monetize this moment in time for themselves," she said.

SEEKING BRAND PUSH

For some, a deep-pocketed sponsor can offer a boost. Visa offered their more than 100 "Team Visa" athletes a masterclass in digital storytelling and engagement ahead of the Paris Games, led by social media creators.The course, offered for the first time, included practical instruction on how to use platforms like Tik Tok as well as guidance on digital storytelling."Helping in how they are going to engage with their fans and be better and more comfortable kind of in this creative space was something that was of value," said Andrea Fairchild, the senior vice president of global sponsorship strategy at Visa.Samsung Electronics 005930.

Sara Tendulkar's

Blue Lehenga Is Perfect Wedding Wear

A beautiful video of Sara Tendulkar in a powder blue and ivory floral lehenga set has delighted her fans on social media. Sara posted the clip with a purple heart emoji as the caption.Sara Tendulkar wore the lehenga set to Anant Ambani and Radhika Merchant's grand wedding festivities. The traditional ensemble comes from the shelves of designer Seema Gujral's eponymous label. It is available on the brand's official website and is called Powder Blue Floral Lehenga Set. The lehenga set will cost you Rs 2,48,000.

Sara's lehenga set by Seema Gujral comprises a bralette, lehenga skirt and dupatta. Embellished with powder blue three-dimensional floral embroidery, crystals, pearls and sequins on an ivory base, the ensemble is an excellent choice for bridesmaids during the wedding season.Sara's sleeveless blouse features a plunging neckline, a pearl tassel embellished drop hem, a backless design and a fitted bust, while the lehenga features a cinch ed waist and an A-line flared skirt. She completed the look by draping the matching embroidered net dupatta over her arms.Sara accessorised the ensemble with a pearl-embellished clutch, a dainty diamond necklace, earrings and a bracelet. She wore her hair in a centre parting and braided style adorned with delicate baby's breath flowers. Darkened eyebrows, pink lips, black eyeliner, blush-tinted cheeks, mascaraed lashes and shimmery pink eyeshadow rounded out the makeup.

Sara Tendulkar is the daughter of cricket legend Sachin Tendulkar and his wife Anjali Tendulkar. She is rumoured to be dating cricketer Shubman Gill. However, both of them have never commented on the matter.Although she has yet to face the camera, Sara is already popular on Instagram. Sachin's daughter, who holds a Masters degree, has a massive following of 6.8 million on Instagram. She often shares videos from shoots and has also been endorsing several brands on social media.

Keerthy Suresh's

Stunning Look In Blush Pink Saree Will Drive Your Monday Blues Away

Ethnic outfits are always in fashion. From weddings to festive gatherings, ethnic fits are always in style, especially sarees. If you're still not convinced, check out actress Keerthy Suresh's latest photoshoot in a blush pink saree, which has taken the internet by storm. Keerthy is currently busy with the promotions for her upcoming film, Raghu Thatha. She has once again displayed her impeccable sense of style by donning a gorgeous saree, which enhanced her elegance and grace. Let's take a closer look at it.

Keerthy Suresh chose a blush pink saree from the wardrobe of designer Archana Rao. Her saree was no regular one; it was a two-way saree, which is a modern take on the traditional garment, and this innovative feature allows the saree to be draped in different styles. Her saree gives a playful and fresh touch, thanks to its beautiful print of small wildflowers all over it. The saree's opposite side is vivid crimson that is trimmed with dainty lace, which creates a stunning contrast that elevates the ensemble. She teamed her saree with a matching strappy blou se. As per reports, her saree comes with a price tag of Rs 42,000.Her selection of accessories enhanced her entire look. Keerthy chose elegant jewellery, such as silver earrings and a big ring. Her jewellery accessorised the stunning saree, while adding a hint of glitz. She kept her make-up subtle and natural, including proper contouring, a trace of kohl, winged eyeliner, and a pink lip colour matching her entire ensemble. She left her hair open in soft waves, which added to her overall elegant aspect and accentuated her beauty.

The pictures went viral in no time. Fans showered compliments in the comment section. One of the users wrote, "Damn, you look so cute and sweet." Another one added, "Looking Gorgeous, Keerthi." Many showered red hearts and fire emojis in the comment box.Keerthy Suresh's upcoming project, Raghu Thatha, is written and directed by Suman Kumar. It also stars MS Bhaskar, Ravindra Vijay, and Rajeev Ravindranathan in the pivotal roles.

Auron Mein Kahan Dum Tha 'Tuu' Song: Ajay Devgn and Tabu Give A Glimpse Of Their Heartwarming Chemistry

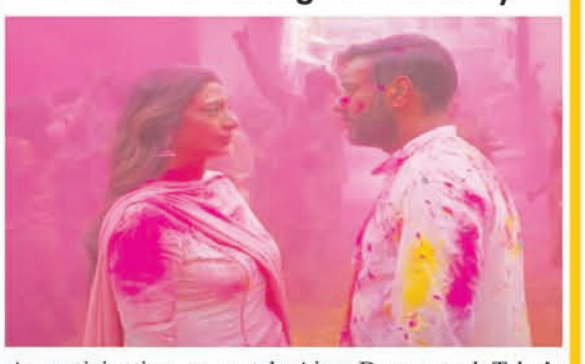

As anticipation to watch Ajay Devgn and Tabu's chemistry in Neeraj Pandey's Auron Mein Kahan Dum Tha increases each day, the makers have released a short love story through their latest music video, Tuu. Showcasing young and growing love with the vibrancy of festivities, the song captures various festivals, from Janmastmi to Holi, and illustrates the seven stages of love.

The song features a grand sequence of Matki Fod, a colourful Holi, and scenes exploring the rarely shot interiors of the Gateway of India, among other beautiful and visionary moments that display the innocent feeling of love. Tuu has been composed by the Oscar-winning maestro M. M. Kareem, sung by Sukhwinder Singh and Javed Ali. Auron Mein Kahan Dum Tha marks Ajay and Tabu's tenth film together and fans are eager to watch them together as lovers. Director Neeraj Panday reveals that he wasn't aware of their off-screen camaraderie but he always knew that they were the perfect fit for the film. "Two years back, when we were figuring out our next theatrical release, the germ of this film came to me. It was there in some form in my head before that but I didn't actually sit down and write about it till two years ago. And Ajay and Tabu were my first choices. Having said that, I don't know if it's their friendship that translated onscreen because I know nothing about its background," the filmmaker said.

"The much-awaited love saga, 'Auron Mein Kahan Dum Tha', will have its theatrical release on 2nd August 2024. The anticipation for the film has been increasing each day as fans eagerly await the chance to witness the chemistry between Ajay Devgn and Tabu in this heartfelt story by Neeraj Pandey," the makers said in a press release issued a week back.Presented by NH Studioz, Auron Mein Kahan Dum Tha is a Friday Filmworks Production, produced by Narendra Hirawat, Kumar Mangat Pathak (Panorama Studios), Sangeeta Ahir, and Shital Bhatia. The film is set for a theatrical release on 2nd August 2024.

Vicky Kaushal Opens Up On Working With Rashmika Mandanna in Chaava: 'The Only Person Who Can…'

Vicky Kaushal and Rashmika Mandanna will soon be seen sharing the screen space together for a one-of-a kind historical drama 'Chhava'. The movie will star Vicky as Chhatrapati Sambhaji Maharaj, while Rashmika Mandanna will step into the role of Yesubai Bhonsale. As the fans wait eagerly to see their favourite stars in an intense historical drama, the former recently opened up o working with Rashmika in the film.In a recent interview, Vicky praised Rashmika in the film and added, "Rashmika is the only person who can make hearts in 56 ways. But another sweetheart of a person. Humne saath mein hamari agli film Chaava hain where Rashmika and I got to act for the first time together. And she brings in so much positivity on the sets. She is a person like that. So she is beautiful at heart."

With a smile that can light up any room, Rashmika Mandanna has become synonymous with warmth and positivity in the entertainment industry. Her fans adore her not only for her talent but also for her unwavering connection with them. Always eager to keep her fans in the loop, she ensures they are updated on every aspect of her life and career journey.

Chaava is a historical drama that revolves around the life of Chhatrapati Sambhaji Maharaj, the son of Chhatrapati Shivaji Maharaj. In the film, Vicky Kaushal is set to portray the character of Chhatrapati Sambhaji Maharaj, the eldest son of the Maratha empire's founder. On the other hand, Rashmika Mandanna takes on the role of Yesubai Bhonsale in the film. The film also stars Akshaye Khanna, Ashutosh Rana, and Divya Dutta in key roles. According to a report by Pinkvilla, actor Neil Bhoopalam has also been roped in to portray the character of a Mughal prince in the film.Chaava marks the second collaboration between Vicky Kaushal and Laxman Utekar after Zara Hatke Zara Bachke. The film is scheduled to hit theatres on December 6, 2024. Apart from Chaava, Vicky Kaushal has a stunning lineup of projects in his kitty. He was last seen in Bad Newz with Triptii Dimri and Ammy Virk.